वार्षिक रिपोर्ट

२०२२-२३

RIS@40

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

ग्लोबल साउथ के विकास को सुनिश्चित करना

विषय सूची

महानिदेशक की रिपोर्ट..... v

अध्याय I : जी20 अध्यक्षता 1

अध्याय II : वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था और सहयोग..... 21

अध्याय III : क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा 33

अध्याय IV : व्यापार, निवेष और क्षेत्रीय सहयोग..... 41

अध्याय V : विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार..... 53

अध्याय VI : पारंपरिक चिकित्सा..... 61

अध्याय VII : महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और मानव पूंजी के लिए बच्चों में निवेश.....67

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद.....71

सुखमय चक्रवर्ती पुस्तकालय आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र 83

अभिस्वीकृति 87

मानव संसाधन..... 89

वित्तीय विवरण..... 96

संचालन परिषद

अध्यक्ष

राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार
(18 जून 2022 तक)

पदेन सदस्य

श्री विनय क्वात्रा
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(1 मई, 2022 से)

श्री अजय सेठ
सचिव, आर्थिक कार्य
विभाग, वित्त मंत्रालय
(15 अप्रैल, 2021 से)

श्री सुनील बरतवाल
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय

डॉ राजेश एस. गोखले
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(3 अक्टूबर 2023 तक)

प्रोफेसर अभय करंदीकर
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(4 अक्टूबर 2023 से)

श्री दामु रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

अपदेन सदस्य

श्री शेषाद्री चारी
अध्यक्ष, चाईना स्टडी सेन्टर,
माहे, मनीपाल

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के
पूर्व राजदूत

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
पुर्व उप गवर्नर, आरबीआई

सदस्य सचिव (पदेन)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

श्री एस. टी. देवरे

सदस्य

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ, नीति आयोग

डा. सुमित सेठ
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय
(26 जुलाई 2023 तक)

डॉ. रघुराम एस.
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी,
औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान
(आईएसआईडी), नई दिल्ली

प्रोफेसर एस.के. मोहंती
आरआईएस

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जब 1 दिसंबर 2022 को जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण की, तो उस समय संकट और अराजकता से घिरा विश्व, महामारी के बाद के प्रभावों, संघर्षों व आर्थिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। भारत की अध्यक्षता का केन्द्र बिंदु मानव केंद्रित दृष्टिकोण सहित "*वसुधैव कुटुंबकम्*" के शाश्वत भारतीय दर्शन पर आधारित "आशा, उपचार और सद्भाव" पर यथावत रहा। भारत ने संकल्प लिया कि अपनी अध्यक्षता को निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख बनाया जाएगा। इसका आशय है कि प्रतिकूल भू–राजनीतिक परिस्थिति को इस प्रक्रिया पर हावी नहीं होने दिया जाएगा, इसके बदले ठोस नतीजों पर पहुंचने के लिए भारत, उत्तर–दक्षिण के साथ ही साथ पूर्व–पश्चिम मतभेदों पर काम करने का हर संभव प्रयास करेगा। इस पृष्ठभूमि के साथ भारत ने दो बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, इस बात पर गौर करते हुए कि जी–20 मुख्य रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक मंच है, इसलिए आर्थिक विकास और स्थिरता के मुद्दों पर भू–राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए; और दूसरा, जी–20 को उसी स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए जैसा कि अधिकांश बहुपक्षीय संगठनों में पाया जाता है और इसमें 'ग्लोबल साउथ की आवाज' शामिल की जानी चाहिए। आरआईएस ने 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के बाद से ही जी–20 में पहल के साथ अपनी सहभागिता पर्याप्त रूप से बढ़ा ली थी।

भारत की अध्यक्षता के दौरान, संस्थान को जी–20 की कार्य योजनाओं में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गए। यह थिंक–20 (टी–20) प्रॉसेस का अविभाज्य अंग बन गया और इसने नीतिगत सारांश में योगदान दिया तथा प्रख्यात विशेषज्ञों की भागीदारी से अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए। विदेश मंत्रालय ने संस्थान को 'यूनिवर्सिटी कनेक्ट' कार्यक्रम के अंतर्गत 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में जी–20 व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करके युवाओं को जी–20 प्रॉसेस में शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने यूथ–20 से संबंधित कार्यक्रम को देश भर में आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस को संपर्क किया। साथ ही साथ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आरआईएस से जी–20 कृषि समूह के लिए अपना नॉलेज पार्टनर बनने का आह्वान किया। इसी समय, आरआईएस को जी–20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए काम करने के लिए भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार, आरआईएस भारत की जी–20 की अध्यक्षता को सफल बनाने से जुड़े देशव्यापी प्रयासों में योगदान देने वाला एक सक्रिय भागीदार बन गया। इनमें जी–20 के प्रमुख समूहों अर्थात साइंस–20, सिविल–20, वूमन–20, आदि के साथ आरआईएस का सक्रिय रूप से संबद्ध होना शामिल रहा। प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित पर्यावरण

सम्मत जीवनशैली (लाइफ), जी–20 से संबंधित कार्य का प्रमुख सिद्धांत है। जी–20 के कार्य का एजेंडा केवल वर्ष 2022–2023 के लिए ही निर्धारित नहीं किया गया है, अपितु इसके कार्यक्षेत्र का दायरा उससे आगे भी बढ़ाया गया है, ताकि जी–20 मंच के लिए एक परिवर्तनकारी वैश्विक भविष्य की परिकल्पना की जा सके।

आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट के लिए पृथक दृष्टिकोण अपनाया गया है। आरआईएस की ओर से साल भर आयोजित की गई समस्त अनुसंधान गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा देने के स्थान पर संकाय सदस्यों ने आरआईएस की इन कार्य योजनाओं को अपने विद्वतापूर्ण विमर्श के ताने–बाने में सहज रूप से शामिल करने का प्रयास किया है। इसका प्रत्येक खंड आरआईएस द्वारा शुरू की गई नई अनुसंधान कार्यपद्धति, डेटाबेस प्रणाली और अनुसंधान परियोजनाओं पर गहनता से गौर करता है। प्रत्येक अध्याय का आरंभ वरिष्ठ संकाय सदस्यों की विद्वतापूर्ण व्याख्या और परिप्रेक्ष्य से किया गया है, जो हमारे अनुसंधान के लक्ष्यों के संदर्भ की बारीकियां बताते हैं।

जी–20 से संबंधित उत्तरदायित्वों में महत्वपूर्ण सहभागिता के अतिरिक्त, यह वार्षिक रिपोर्ट कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान को मजबूत बनाने की आरआईएस की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसका विस्तृत विवरण विभिन्न अध्यायों में स्पष्ट रूप से किया गया है। यह अध्याय वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था और सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुगमता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ–साथ पारंपरिक चिकित्सा और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में हमारे योगदान पर प्रकाश डालते हैं। इन अध्यायों के प्रमुख विषयों के अंतर्गत–सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और आसियान–भारत साझेदारी से लेकर समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी तक, आईबीएसए, आईओआरए, नीली अर्थव्यवस्था, बिम्सटेक, आरसीईपी, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), सूक्ष्म, लघु और मझौले आकार के उद्यम(एमएसएमई), कृत्रिम आसूचना (एआई), महत्वपूर्ण खनिज, विज्ञान कूटनीति, एसडीजी के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आयुष क्षेत्र सहित अन्य विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रकाशन भी लाए गए, जिनमें विद्यार्थी समुदाय के लिए अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया और तमिल जैसी विविध भारतीय भाषाओं में तैयार की गई *जी–20 प्रवेशिका* शामिल है। इसके अलावा, हमारे संकाय सदस्य विभिन्न बाहरी प्रकाशनों और नीतिगत संवादों में सक्रिय रूप से संलग्न रहें, जिसके कारण समकालीन शैक्षणिक और नीतिगत चर्चाओं में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में हमारे संस्थान की स्थिति और मजबूत हुई।

हम अपने संकाय सहयोगियों के आभारी हैं कि उन्होंने आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट की विषय सामग्री को नवोन्मेषी तरीके से समृद्ध करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिसे संस्थान की कार्य योजनाओं को जीवंत कथानक के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर, आर्थिक

मामलों के राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय और बहुपक्षीय ढांचे के साथ संदर्भित करते हुए नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सका है। आशा है कि यह रिपोर्ट शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, व्यवसायियों, नीति निर्माताओं, व्यापार और उद्योग मंडलों के साथ–साथ मास मीडिया बिरादरी द्वारा हमारे अनुसंधान कार्यक्रमों की क्षमता को समझने की दिशा में प्रेरक और व्यवहारिक समझी जाएगी।

हम अनुसंधान कार्यक्रम और प्रशासनिक गतिविधियों में संस्थान का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए आरआईएस की आमसभा/शासी परिषद और अनुसंधान सलाहकार परिषद के सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं। संस्थान के संचालन की दृष्टि से यह साल अद्वितीय रहा है। वित्तीय जिम्मेदारियों की निगरानी के लिए दो सदस्यीय समिति की नियुक्ति के जरिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को आमसभा/शासी परिषद के स्तर तक बढ़ाया गया है, जो पहले आंतरिक समितियों के स्तर पर किया जाता था। संस्थान के अनुसंधान कार्यों में निरंतर सहयोग देने के लिए हम विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय; आर्थिक कार्य विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; और नीति आयोग को धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर, हम आरआईएस के संकाय सदस्यों और प्रशासनिक सहयोगियों का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने विविध स्तरों पर संस्थान को सौंपे गए कार्य को प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों के साथ पूरा किया।

मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आरआईएस सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। इसके लिए हम अपने सम्मानित साझेदार थिंक टैंकों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता की अपेक्षा करते हैं।

सचिन चतुर्वेदी

अध्याय 1

जी–20 अध्यक्षता

प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला जी–20 वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के नेतृत्व के अंतर्गत टिकाऊ और समावेशी विकास पर केन्द्र बिंदु बढ़ गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रमुख रणनीतियों का उपयोग किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करके, टिकाऊ शहरीकरण को प्रोत्साहन देकर तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, भारत हरित और अधिक टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। डिजिटल समावेशन को मजबूत बनाते हुए, वित्त तक आसान पहुंच, सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, खुले बाजारों, निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों की वकालत करके और व्यापार बाधाओं में कमी लाने जैसी एसएमई के विकास को सुगम बनाने वाली नीतियों को बढ़ावा देते हुए, भारत टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देश लाभांवित होंगे।

विकासशील देशों के अनुसंधान के प्रति समर्पित प्रमुख थिंक–टैंक के रूप में, आरआईएस ने जी–20 के पुनरुत्थान और परिवर्तन में गहन योगदान देने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। विभिन्न पहलों, अनुसंधान कार्यक्रमों और जी–20–के अन्य विशिष्ट कार्य समूहों और सहभागिता समूहों के साथ संबद्धता के जरिए आरआईएस ने टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठन ने विभिन्न हितधारकों से विशेषज्ञता और जानकारी एकत्र करने के लिए टी–20 (थिंक टैंक–20), एस–20 (साइंस–20), वाई–20 (यूथ–20), और सी–20 (सिविल–20) समूहों के साथ सक्रियता से परस्पर बातचीत की है।

आरआईएस ने जी–20 के कृषि संबंधी कार्य समूह के लिए ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य किया है और कृषि पद्धतियों, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आरआईएस ने जलवायु स्मार्ट कृषि के संबंध में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनके अंतर्गत विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाते हुए कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जी–20 की रूपरेखा के भीतर कृषि क्षेत्र में अनुकूलन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर विचार–विमर्श किया गया।

टी–20 सहभागिता समूह के अंतर्गत, आरआईएस लाइफ (आजीविका, आय, खाद्य सुरक्षा और समानता) और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य बल –3 में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आरआईएस समग्र कल्याण और समुचित आर्थिक विकास में योगदान देने वाले मूल्यों पर जोर देने की दिशा में प्रयासरत रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती मौजूदगी के अनुरूप, आरआईएस ने जी–20 की अध्यक्षता के दौरान स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग (एसईएलएम) में भाग लिया है।

इसके अतिरिक्त, आरआईएस ने जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसके तहत वैश्विक महत्व के मामलों पर सार्थक चर्चा में एक सौ एक विश्वविद्यालयों को शामिल करना तय किया गया। आरआईएस अनुसंधान को प्राथमिकता देने, नए नेटवर्क बनाने और युवाओं के साथ जुड़ने के जरिए समृद्ध और न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था के जी–20 के लक्ष्य की दिशा में प्रेरक शक्ति बना हुआ है।

भारत की जी–20 अध्यक्षता

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों की विलक्षण सदस्यता वाले समूह जी–20 को हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में देखा गया है। ऐसा विशेषकर डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक आदि के नेतृत्व में होने वाली बहुपक्षीय वार्ताओं में कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने के कारण हुआ है। हालांकि जी–20 को नेताओं के शिखर सम्मेलन वाले स्तर तक पहुंचने के तत्काल बाद के वर्षों में, 2007–2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद मुख्यतः वित्तीय स्थिरता और व्यापक आर्थिक तालमेल की चुनौतियों से निपटना पड़ा है, लेकिन समय के साथ जी–20 के एजेंडे में आशातीत विविधता आई है। अतीत की तुलना में हाल के बरसों की अध्यक्षता के दौरान विकास के मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, एसडीजी, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण और कृषि, एमएसएमई, ढांचागत वित्तपोषण आदि जैसी समस्त समकालीन विकास से संबद्ध चुनौतियां 2010 में दक्षिण कोरिया की जी–20 की अध्यक्षता के बाद से विभिन्न मंत्रिस्तरीय, कार्य समूह और सहभागिता समूह की बैठकों में जी–20 विचार–विमर्श का हिस्सा रही हैं।

बीते कुछ वर्षों में, ऐसा माना जाने लगा है कि जी–20 अपनी प्रतिबद्धताओं और अपनी पहलों की प्रकृति, रूपरेखा और विषय सामग्री में कई उल्लेखनीय बदलावों का साक्षी बना है। मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों में सरकारों के बीच विचार–विमर्श के अलावा, बहुधा कार्य समूहों और सहभागिता समूहों की साझा संगोष्ठियां और विचार–मंथन होने लगे हैं और संभवतः अधिक प्रभावी हो गए हैं। प्रायः विभिन्न देशों की अध्यक्षताओं के दौरान नए कार्य समूहों और सहभागिता समूहों का आरंभ करके दुनिया की अल्पकालिक और मध्यम अवधि की चुनौतियों का जवाब दिया जाता रहा है। वर्तमान में 10 से अधिक सहभागिता समूह शैक्षणिक समुदाय, उद्योग संघों, सिविल सोसाइटी, श्रम संगठनों, युवा और महिला संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत की जी–20 की अध्यक्षता वर्ष 2023 में ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई है, जब दुनिया कोविड के बाद आर्थिक सुधार के लाभों को संचित कर रही है और अनिश्चित भू–राजनीतिक वातावरण के कारण उसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ रहा है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में 'वसुधैव कुटुम्बम्' (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) का मार्ग चुना है। लगातार विकासशील देशों की अध्यक्षताओं के दृष्टिकोण से भारतीय अध्यक्षता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के बाद 2024 और 2025 में क्रमशः ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसकी अध्यक्षता संभालेंगे। भारत विकास के कुछ ऐसे विचारों पर बल देने की कोशिश कर रहा है, जो उसके बाद लगातार दो देशों की अध्यक्षता के दौरान समर्थन जुटा सकेंगे। भारत ने एक समावेशी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए एसडीजी में तेजी लाने, न्यायसंगत संक्रमण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन, कई अन्य क्षेत्रों सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार जैसे विकास के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा शुरू की है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के तहत जी–20 द्वारा केंद्रित चर्चा और संभवतः कुछ समर्पित प्रतिबद्धताओं को प्रेरित करने के लिए एक नया कार्य समूह (आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन) और एक नया सहभागिता समूह (स्टार्ट–अप) प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, व्यापक पहुंच तथा राज्यों और स्थानीय सरकारों को शामिल करने के भारत के प्रयासों को जी–20 प्रॉसेस में जन भागीदारी के अभिनव प्रारूपों के रूप में देखा जाता है। जी–20 में जनभागीदारी,

विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को साथ जोड़ना, भारत की अध्यक्षता के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों और कार्यक्रमों ने भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय व्यंजन, स्थानीय उत्पादों तथा वनस्पतियों और जीवों को प्रस्तुत किया है।

लाइफ तथा मूल्यों और नैतिकता के महत्व के बारे में वैश्विक विचार–मंथन के लिए आरआईएस ने जनवरी 2023 में भोपाल में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ यह आयोजन विशेष रूप से लाइफ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूलन की दिशा में एक मुहिम के तौर पर लाइफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर वैश्विक चिंतन को सुगम बनाने के संबंध में टी–20 में भारत के योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ।

भारत की अध्यक्षता से पहले की समयावधि में आरआईएस ने भारत और सामान्य तौर पर विकासशील देशों के हित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए कई विचार–मंथन सत्र आयोजित किए। इस संबंध में, आरआईएस ने 27–28 अगस्त, 2022 को अपने प्रमुख आयोजन दिल्ली प्रोसेस को ''भारत की जी–20 की अध्यक्षता की ओर : संक्रमण और प्रतिस्पर्धा के दौर में नए विकास परिप्रेक्ष्यों और वृद्धि पर केंद्रित रणनीतिक भागीदारियों की तलाश'' विषय के साथ जी–20 को समर्पित किया। भारत के जी–20 शेरपा और विभिन्न देशों के जाने–माने विचारकों ने वैश्विक शासन व्यवस्था, एसडीजी, नए विकास परिप्रेक्ष्यों और इन मुद्दों को भारत की अध्यक्षता के दौरान उठाने के तरीकों के बारे में भी विचार–विमर्श किया। यद्यपि जी–20 की सफलता के लिए इसकी उत्तरोत्तर अध्यक्षताओं के दौरान कार्यों और प्रतिबद्धताओं का निरंतर बने रहना महत्वपूर्ण है, जी–20 तथा जी–7 और ब्रिक्स जैसे अन्य समूहों के बीच तालमेल भी महत्वपूर्ण होगा। उस भावना में, आरआईएस ने नई दिल्ली में जर्मनी के दूतावास के सहयोग से 7 जून 2022 को ''अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए क्षितिजः जी–7 और जी–20 के बीच तालमेल की तलाश' विषय पर एक हाइब्रिड कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें दोनों पक्षों के सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के अलावा, एक पैनल ने जी–7 और जी–20 देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। इसमें यह बात काफी मुखरता से सामने आई कि जी–7 और जी–20 जलवायु परिवर्तन, एसडीजी, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत के प्रभावशाली परिणामों के लिए मिलकर काम करें। ■

भारत की जी–20 अध्यक्षता के लिए कृषि एवं किसान कल्याण

भारत ने 1 दिसंबर 2022 को ''अमृतकाल'' में इंडोनेशिया से जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण की। अमृतकाल, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 से शुरू होकर स्वतंत्रता की शताब्दी तक की 25 साल की अवधि है। शेरपा ट्रैक के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की स्थापना 2011 में फ्रांस की अध्यक्षता के दौरान की गई थी, तब से यह संयुक्त राष्ट्र के 2030 के एजेंडे, विशेष रूप से भूखमरी को पूरी तरह समाप्त करने (एसडीजी 2) के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य अपशिष्ट और हानि, स्थिरता, और लचीली एवं समावेशी खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं जैसे अनेक वैश्विक मुद्दों पर सूचना के आदान–प्रदान और सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जी–20 के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

भारत की जी–20 की अध्यक्षता 2023 के दौरान आरआईएस को जी–20 कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) के ज्ञान साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार यह 1 अगस्त 2022 से दो साल की अवधि के लिए विभाग के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

इससे पहले भी आरआईएस ने अग्रसक्रिय रूप से कार्य करते हुए जी–20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 16 जुलाई, 2022 को एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, आईसीएआर, आईआईएम, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आरआईएस ने कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों पर व्यापक शोध किया और भारत की अध्यक्षता के लिए इश्यू नोट, संकल्पना नोट्स जैसे विभिन्न दस्तावेजों को आकार देने में योगदान दिया; और इंडोनेशिया की अध्यक्षता 2022 के एडब्ल्यूजी के लिए इनपुट प्रदान करने में भी शामिल था। जी–20 एडब्ल्यूजी के लिए जिस इश्यू नोट को अंतिम रूप दिया गया है, उसमें चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिनका विवरण बॉक्स में दिया गया है।

आरआईएस ने विभाग की कोर समिति की बैठकों में जी–20 एडब्ल्यूजी मुद्दों पर नियमित रूप से विचार–विमर्श को समृद्ध बनाने में योगदान दिया।

आरआईएस ने कृषि मंत्रियों के वक्तव्य के लिए ड्राफ्ट और जी–20 सहयोग के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण, मोटे अनाजों पर और कृषि बाजार सूचना प्रणाली जैसे अन्य पहलुओं पर भी इनपुट प्रदान किये।

आरआईएस ने वरिष्ठ परामर्शदाता, परामर्शदाताओं और युवा पेशेवरों की भर्ती के माध्यम से विभाग को अपनी टीम का विस्तार करने में भी सहायता प्रदान की।

विभाग ने भारत की अध्यक्षता, 2023 के दौरान जी–20 एडब्ल्यूजी के अंतर्गत कृषि मंत्रियों की बैठक से पहले चार कृषि प्रतिनिधि बैठकों (एडीएम) की योजना बनाई। आरआईएस ने विभाग को आवश्यकता के मुताबिक इनपुट प्रदान करने के लिए इन बैठकों में अपनी कृषि टीम भेजी। जून 2023 में संभावित कृषि मंत्रियों की बैठक (एएमएम) के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पहली एडीएम 13 से 15 फरवरी, 2023 को इंदौर में और दूसरी 29 से 31 मार्च, 2023 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई।

इंदौर में तीन दिवसीय प्रथम एडीएम के दौरान आरआईएस की पहल पर एडीएम के पहले ही दिन अर्थात 13 फरवरी, 2023 को 'खाद्य सुरक्षा हेतु जलवायु–स्मार्ट कृषि पर वैश्विक मंच' नामक एक समानांतर आयोजन किया गया। इस समानांतर आयोजन में जलवायु परिवर्तन की चुनौती की गंभीरता को रेखांकित किया गया और जलवायु–स्मार्ट कृषि (सीएसए) की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों पर विचार–विमर्श किया गया। आरआईएस के महानिदेशक ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए प्रोत्साहनों

भारत की अध्यक्षता 2023 के दौरान जी–20 कृषि कार्य समूह के प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

1. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण
2. जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत् कृषि
3. समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाएं और खाद्य प्रणालियां
4. कृषि संबंधी परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण

भारत की जी–20 प्रेसीडेंसी: कृषि और खाद्य स्थिरता में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि पर ग्लोबल फोरम में जी20 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए।

को नए सिरे से समायोजित करने, सीएसए के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था की आवश्यकता हेतु, डेटा यूज और डैशबोर्ड के लिए एक वृहद परिप्रेक्ष्य विकसित करने, प्रौद्योगिकी–आधारित पूर्वानुमान, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को जोड़ने, प्रौद्योगिकियों को अपनाने और एमएसएमई के नेतृत्व वाले नवाचार इकोसिस्टम की सहायता करते हुए नीतिगत नुस्खों निश्चित रूप देने वाली अपनी कार्यवाहियों को व्यवस्थित किया।

आरआईएस ने समानांतर आयोजन की रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए इनपुट देने सहित बैठक के सुचारू संचालन के लिए विभाग को सहायता प्रदान की और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर साझेदारी में योगदान देना जारी रखा। ■

पर्यावरण सम्मत जीवनशैली: लाइफ

भारत की जी–20 की अध्यक्षता ने व्यक्तिगत और समाज के स्तर पर व्यवहार में बदलाव लाने की उच्च महत्वाकांक्षा और प्रेरणा सहित टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के संबंध में जी–20 देशों को उद्देश्य और नीतिगत निर्देश प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करने के लिए लाइफ को प्रमुख एजेंडे के रूप में प्राथमिकता दी है। 'लाइफ' के माध्यम से भारत जलवायु कार्रवाई के संबंध में उच्च महत्वाकांक्षा को लक्षित करता है और निष्कर्षण से अधिक संरक्षण को प्रोत्साहन देने संबंधी एक नए विकास परिप्रेक्ष्य पर बल देता है, जो मौजूदा आर्थिक मॉडलों के अंतर्गत व्यापक रूप से प्रचलित है। यह आर्थिक प्रगति के आय–आधारित उपायों अर्थात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से परे जाने को भी अनिवार्य बना देता है।

पिछले कई वर्षों में, आरआईएस विकासशील देश के परिप्रेक्ष्य से एसडीजी के सार्थक कार्यान्वयन की दिशा में अनुसंधान और नीतिगत संवादों में गहन रूप से संलग्न है। एक ओर, कई त्रासद घटनाओं के कारण उपजे संकट और बहुपक्षवाद में संकट का सामना करते हुए तथा दूसरी ओर, विकास संबंधी परिवर्तनों में भारत की अपनी सफलता और टिकाऊ बदलावों की दिशा में साहसिक कदमों को स्वीकार करते हुए, आरआईएस नए विकास परिप्रेक्ष्य की संकल्पना के जरिए सतत विकास की अत्याधुनिक धारणा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरआईएस ने विकास के नए परिप्रेक्ष्य के रूप में 'लाइफ' के बारे में साक्ष्य–आधारित अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इस प्रकार उसे जी–20 की प्राथमिकता के रूप में पर्याप्त रूप से रेखांकित किया है। यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि आरआईएस ने अपने प्रमुख वार्षिक सम्मेलन दिल्ली डायलॉग VI 27–28 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में 'भारत की जी–20 की अध्यक्षता की ओर : विकास के नए आयामों और प्रगति की रणनीतियों की तलाश–संक्रमण और विवादों के दौर में साझेदारियां' विषय पर आयोजित किया।

आरआईएस ने *पर्यावरण सम्मत जीवन शैली (लाइफ), लचीलेपन और कल्याण के लिए नैतिक मूल्यों पर एक विलक्षण* कार्य बल – कार्य बल –3 की शुरुआत की, जिसमें अर्थशास्त्र, दर्शन, शहरी नियोजन, स्थिरता और विकास अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर की विशेषज्ञता वाले दुनिया भर के तेईस प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विद्वानों और व्यवसायियों को कार्य बल के सह–अध्यक्षों के रूप में शामिल किया गया।

आरआईएस ने टी–20, अर्बन –20 (यू–20), मध्य प्रदेश सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए), मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल कोष (यूनिसेफ), आरआईएस में वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी), जीआईजेड इंडिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के सहयोग से भोपाल में 16–17 जनवरी, 2023 को ''पर्यावरण सम्मत जीवनशैली (लाइफ), नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमयुक्त वैश्विक सुशासन : संरचना, वित्त और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग का संचार'' विषय पर सहभागिता समूह थिंक–20 के विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया। 'भोपाल घोषणापत्र' लाइफ और मूल्य–आधारित विकास परिप्रेक्ष्यों; एसडीजी में तेजी लाने; व्यापार, निवेश और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं; वन हैल्थ; बच्चे–हमारा भविष्य; लचीले बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण; महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास; कल्याण का

माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता करते हुए।

आकलन; समावेशी जी–20; और ग्लोबल साउथ सहित क्षेत्रों में प्रमुख सिफारिशें प्रदान करता है।

कार्य बल के सदस्यों ने भारत की थिंक–20 प्रक्रिया में सामूहिक योगदान देने के लिए कई विचार–मंथन सत्रों में भाग लिया और स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ''लाइफ, वैल्यूज़ एंड वेलबीइंगः टुवार्ड्स ए न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम'' नामक नए खंड में मूल लेखों का योगदान देने पर सहमति व्यक्त की। इस दिशा में आरआईएस की भागीदारी चरम पर रही, क्योंकि उसने 16–17 जनवरी 2023 को भोपाल में ''पर्यावरण सम्मत जीवनशैली (लाइफ), नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमयुक्त वैश्विक सुशासन : संरचना, वित्त और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग का संचार'' विषय पर एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी परिणति 'भोपाल घोषणापत्र' में हुई, जो बहुत सराहा गया। इसमें विकास के नए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता, कल्याण का आकलन जीडीपी से परे किए जाने की आवश्यकता और अफ्रीकी संघ को जी–20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल करने की वकालत पर जोर देते हुए ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य से टिकाऊ और समावेशी विकास की प्राथमिकताओं को सबसे आगे रखा गया है।

थिंक–20 ट्रैक के अलावा, आरआईएस जी–20 इंडिया के तहत सिविल–20 सहभागिता समूह के ज्ञान साझेदार के रूप में भी जुड़ा हुआ है। आरआईएस का प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर 2022 में, सी–20 इंडोनेशिया शिखर सम्मेलन में उपस्थित था और उसने भारत में जी–20 सचिवालय को सी–20 प्रक्रिया के बारे में संसाधनों और जानकारी के माध्यम से सहायता दी; और उसके बाद शुरुआती दिनों में भारतीय सी–20 सचिवालय को सहायता प्रदान की। आरआईएस टीम को सी–20 इंडिया के अनेक परामर्शों और रणनीति बैठकों में भी आमंत्रित किया गया है। आरआईएस सी–20 इंडिया के 3 अलग–अलग कार्य समूहों अर्थात –लाइफ कार्य समूह, और एकीकृत समग्र स्वास्थ्य के सी–20 कार्य समूह और सेवा से संबंधित सी–20 कार्य समूह– में सक्रिय योगदान दे रहा है।

भोपाल घोषणापत्र

- भोपाल घोषणापत्र में निम्नलिखित विशयों पर महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गईं:
- लाइफ और मूल्य–आधारित विकास परिप्रेक्ष्य एसडीजी में तेजी लाना
- व्यापार, निवेश और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं
- वन हेल्थ
- बच्चे–हमारा भविश्य
- लचीली अवसंरचना के लिए वित्तपोषण
- महिलाओं के नेतृत्व में विकास
- सुख–समृद्धि का आकलन
- समावेशी जी–20
- ग्लोबल साउथ
- अफ्रीकी संघ की सदस्यता
- जैवनैतिकता

इस सहभागिता के अंतर्गत, आरआईएस ने भारत की जी–20 की अध्यक्षता की तैयारियों के लिए सिविल–20 (सी–20) के समक्ष मौजूद मुद्दों पर चर्चा करने हेतु महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, पुणे; योजक, सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुणे; रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, मुंबई; विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी; और सेवा इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप से 14 नवंबर, 2022 को ''भारत की जी–20 की अध्यक्षता : विकास संबंधी भारतीय दृष्टिकोण और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका'' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। ■

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन भाषण देते हुए।

अंतरिक्ष 2.0: अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नया अंतरिक्ष युग

जी–20 संरचना के नवीनतम सहभागिता समूहों में से एक–स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग (एसईएलएम) की स्थापना 2020 में सऊदी अरब की जी–20 अध्यक्षता के दौरान की गई थी। जी–20 ने अपनी प्रथम दो एसईएलएम बैठकों का आयोजन सऊदी अरब की जी–20 अध्यक्षता (2020) और इटली की जी–20 अध्यक्षता (2021) के तहत कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए आर्थिक और यात्रा लॉकडाउन के कारण आभासी रूप से किया था। इंडोनेशिया की जी–20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित 2022 एसईएलएम वास्तविक दुनिया में आयोजित होने वाली प्रथम एसईएलएम रही। दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष–सक्षम देशों में से एक भारत ने अपनी जी–20 की अध्यक्षता के तहत एसईएलएम 2023 का आयोजन कर अपनी तरह के इस पहले अवसर का भरपूर लाभ उठाया और एक अत्यंत उपयुक्त एजेंडा निर्धारित किया। आरआईएस और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के बीच विलक्षण सहयोग के माध्यम से आरआईएस ने एसईएलएम एजेंडा–निर्धारण में सक्रिय रूप से भाग लिया।

आरआईएस अपने विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन–स्पेस) के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में सहयोग करता है। 2020 में स्थापित इन–स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली वाणिज्यिक गैर–सरकारी इकाइयों के लिए भारत के विनियामक और प्रमोटर के रूप में कार्य करता है। भारत के 2020 के अंतरिक्ष सुधारों के तहत स्थापित इस एजेंसी को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने का दायित्व सौंपा गया है। आरआईएस ''भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के पदचिह्नों को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने की रणनीति'' शीर्षक से एक नवीन रणनीतिक अनुसंधान अध्ययन कर रहा है, जिसे इन–स्पेस ने प्रायोजित किया है। यह अध्ययन इन–स्पेस के लिए प्रवेशिका है, ताकि वह भारतीय कंपनियों को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार तक पहुंच हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद कर सके।

आरआईएस ने एसईएलएम 2023 की भारत की अध्यक्षता का लाभ उठाने के लिए इन–स्पेस के साथ यथासमय सहयोग और एजेंडा–निर्धारित करने में सहायता प्रदान की है।

इस परियोजना के अंतर्गत, आरआईएस ने दो एसईएलएम बैठकों – शिलांग में आयोजित प्रीकर्सर इवेंट (17–18 अप्रैल, 2023) और बेंगलुरु में आयोजित एसईएलएम इवेंट (6–7 जुलाई, 2023) में सक्रिय रूप से भाग लिया। जहां एक ओर प्रीकर्सर इवेंट में जी–20 के सदस्य देशों के राजदूतों और जी–20, 2023 के अतिथि देशों की भागीदारी देखी गई, वहीं मुख्य कार्यक्रम में अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की भागीदारी देखी गई। शिलांग कार्यक्रम का औचित्य गैर–अंतरिक्ष क्षेत्र के हितधारकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ रही स्पेस 2.0 या न्यू स्पेस के रूप में ज्ञात घटनाओं में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना था। मुख्य कार्यक्रम में जी–20 के सदस्य देशों और जी–20, 2023 के अतिथि देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और लगभग 50 अंतरिक्ष उद्योगों की भागीदारी देखी गई। एसईएलएम 2023 पहली बार स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष यान बनाने और प्रक्षेपित करने में समर्थ किसी देश में आयोजित की गई, जिसने भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने और अपनी कुछ अंतरिक्ष कंपनियों को तेजी से बदलते वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था परिदृश्य में प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

भारत की जी–20 की अध्यक्षता ने एसईएलएम 2023 के एजेंडे को डीओएस द्वारा मुख्य रूप से इसके घटक संस्थानों, इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), और इन–स्पेस द्वारा चिन्हित किए गए 'एक नए अंतरिक्ष युग की ओरः अर्थव्यवस्था, उत्तरदायित्व, गठबंधन' विषय के दायरे में निर्धारित किया। यह विषय दुनिया भर में असंख्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को एक नई वैश्विक घटना के साथ प्रतिध्वनित करता है। इस घटना को अब स्पेस 2.0 या न्यू स्पेस के नाम से जाना जाता है।

2023 एसईएलएम थीम के प्रथम पहलू में इस बात को रेखांकित किया गया है कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम बनती जा रही है। इस उद्देश्य से एसईएलएम 2023 बैठक ने जी–20 सदस्य देशों के एनजीपीई के बीच सहयोग को मजबूत करने और अनुकूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियों को तैयार करने पर विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान की।

बाहरी अंतरिक्ष, विशेष रूप से कक्षा और सिस्लूनर अंतरिक्ष में बढ़ती गतिविधियों के साथ, अंतरिक्ष एजेंसियों और वाणिज्यिक अंतरिक्ष संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों को जिम्मेदारी से संचालित करना चाहिए। 2023 एसईएलएम थीम का दूसरा पहलू 'जिम्मेदारियों' पर केंद्रित है, जिसमें अंतरिक्ष प्रणालियों का निरंतर निर्माण, स्वच्छ प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष यान प्रणोदन प्रणालियों का उपयोग, कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष मलबे में कमी लाने के शमनकारी उपायों के साथ कक्षा को सुरक्षित और उसमें भीड़–भाड़ में कमी सुनिश्चित करना शामिल है। भारतीय 2023 एसईएलएम अध्यक्षता ने अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते खतरे से निपटने और विश्व कल्याण के लिए अंतरिक्ष में कुछ कक्षाओं में मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियां सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले 2021 एसईएलएम के एजेंडे की याद दिलाई।

थीम का तीसरा और अंतिम पहलू, गठबंधन, बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष उद्योग और शिक्षा जगत के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता पर रेखांकित करता है। इस उद्देश्य से, थीम में गठबंधन पर केन्द्र बिंदु अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षा रखने वाले देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की सहायता के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2022 से, आरआईएस में विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम ने भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाए जाने से संबंधित विचार–विमर्श में योगदान दिया है। आरआईएस ने वेबिनार आयोजित किए हैं और उद्योग–प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए ज्ञान साझेदारी प्रदान की है। आरआईएस ने 'पोटेंशियल रोल फॉर एकेडेमिया–इंडस्ट्री इंटरफेस फॉर स्पेस इकॉनोमीः इमर्जिंग पॉलिसी ऑप्शन्स फॉर इंडिया'' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण चर्चा पत्र प्रकाशित किया है, तथा आगामी महीनों में ऐसे कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति पत्र प्रकाशित होने वाले हैं। आरआईएस के पास एसईएलएम 2023 के निष्कर्षों से सीख ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ है। आरआईएस इन अनुभवों को 2024 की ब्राजील की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान उपयोग में लाएगा। ■

यूथ–20: वैश्विक भविष्य को सुगम बनाना

वाई–20, जी–20 के महत्वपूर्ण सहभागिता समूहों में से एक है। 2012 में अपनी स्थापना के बाद से, यह युवाओं के लिए जी–20 के साथ जुड़ने और मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में वैश्विक सहमति बनाने में योगदान देने का एक प्रभावी मंच रहा है। आमतौर पर, वाई–20 प्रक्रिया में कुछ युवा परामर्श, कुछ पूर्व–शिखर सम्मेलन बैठकें और एक अंतिम शिखर सम्मेलन शामिल होता है, जहां वाई–20 लीडर्स जी–20 नेताओं के लिए एक वक्तव्य तैयार करते हैं। हालांकि, भारत ने वाई–20 प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़ा है। भारतीय युवाओं द्वारा अनेक समस्याओं के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रदान किए जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) ने एक नई पहल वाई–20 विचार–मंथन कार्यशालाओं की शुरूआत की हैं, ताकि सफलतम युवाओं की ऊर्जा और अभिनव विचारों को वैश्विक चिंताओं का निवारण करने के लिए वैश्विक स्तर पर उपयोग में लाया जा सके। इन विचार–मंथन कार्यशालाओं की संकल्पना वाई–20 वक्तव्य के लिए नीतिगत अनुशंसाओं को एकत्रित करने तथा सफल युवाओं और शहर के स्तर पर स्थानीय नीति योजनाकारों के बीच संवाद को सुगम बनाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई है।

आरआईएस ने पच्चीस भारतीय शहरों में वाई–20 विचार–मंथन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए एमओवाईएएस के साथ साझेदारी की। यह प्रक्रिया जनवरी में भोपाल में पहली विचार–मंथन कार्यशाला के साथ शुरू हुई और तब से विभिन्न भारतीय शहरों में सत्रह सफल कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन विचार–मंथन कार्यशालाओं में युवा उद्यमियों, पेशेवरों, विद्वानों, सफल व्यवसायियों, डॉक्टरों, शांति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वाई–20 इंडिया के पांच विषयगत क्षेत्रों पर अपने विचार साझा किए। ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर कार्यशालाओं में नवाचारों को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण पर गहन चर्चा हुई। उद्योग 4.0 की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए, युवा उद्यमियों ने स्टार्ट–अप के लिए अनुपालन बोझ को कम करने, ओपन इनोवेशन सेंटर स्थापित करने, कृत्रिम आसूचना (एआई) के लिए नियम तैयार करने, इनक्यूबेशन केंद्रों के लिए क्लस्टर–आधारित दृष्टिकोण अपनाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों का फायदा उठाने के लिए एसटीईएम शिक्षा, सीखने की क्षमता और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने जैसे नीतिगत उपाय सुझाए।

'जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण' से संबंधित कार्यशालाओं में टिकाऊ जीवन के प्रति परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को कम करने और हरित ऊर्जा के उदय में तेजी लाने पर विचार–विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने इस ओर इंगित किया कि प्रतिबद्ध उत्सर्जन को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता और उन्होंने जी–20 नेताओं से बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों में कमी लाने के लिए जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

'स्वास्थ्य, कल्याण और खेल' से संबंधित सत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार, मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए रणनीति और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए युवा डॉक्टरों और नवोन्मेषकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। अन्य नीतिगत सुझावों के अलावा, प्रतिभागियों ने लोगों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करने के महत्व पर जोर दिया। 'साझा भविष्यः लोकतंत्र और शासन व्यवस्था में युवा' विषय पर चर्चा राजनीति और शासन व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और नेतृत्व प्रशिक्षण शुरू करने के इर्द–गिर्द घूमती रही। सुदृढ़ चुनावी सुधार, चुनाव लड़ने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण, सामुदायिक नेतृत्व में नई जान फूंकने के साथ–साथ नेतृत्व विकास पाठ्यक्रमों की शुरूआत, लोकतंत्र और शासन व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रमुख नीतिगत सुझावों के रूप में उभरे। ■

साइंस 20

साइंस–20 (एस–20) सहभागिता समूह की स्थापना 2017 में जर्मनी की अध्यक्षता के दौरान जी–20 देशों की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों को शामिल करते हुए की गई थी। भारत की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया और ब्राजील के साथ मिलकर भारत ट्रोइका का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया है। जी–20 के एजेंडे को आगे बढ़ाने में एस–20 की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास में विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके लिए सदस्य देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुभवों और आविष्कारों को प्रत्येक के साथ साझा किया जा सके। एस–20 इस लक्ष्य को हासिल करने का मंच है। एस–20 सहभागिता समूह का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों से मिलने वाले विज्ञान–आधारित परामर्शों और सिफारिशों को नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि निर्णयों को वैज्ञानिक सहमति के आधार पर लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। यह अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ चर्चा के माध्यम से सर्वसम्मति के आधार पर निरुपित की गईं विज्ञान–आधारित सिफारिशें नीति निर्माताओं के सामने प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2023 के लिए एस–20 के लिए भारत की ओर से प्रस्तावित मुख्य विषय "नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान" था। आरआईएस ने जनवरी 2023 में पुडुचेरी में आरंभिक बैठक में भाग लिया था, जिसमें भारतीय प्रस्तावों पर चर्चा और उनका समर्थन किया गया। इस व्यापक विषय के अंतर्गत, तीन मुद्दों– सबके लिए सम्पूर्ण स्वास्थ्य, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा तथा विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना–पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों (अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल) में विचार–विमर्श की योजना बनाई गई थी। विचार–विमर्श की श्रृंखला में कोयंबटूर की शिखर बैठक को भी शामिल किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को एस–20 के लिए सचिवालय नामित किया गया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) को एस–20 का नॉलेज पार्टनर नामित किया गया।

हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा: हरित ऊर्जा स्रोतों की दिशा में सहज परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकियों का रुख करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इस तरह के परिवर्तन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों को परस्पर लाभकारी रूप से साझा करने की आवश्यकता होती है। जी–20 राष्ट्र, जो ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों के संचयी उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदार हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से इस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। जी–20 देशों के ऊर्जा पोर्टफोलियो के भीतर परमाणु ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के आविष्कारों को उत्प्रेरित करने के लिए किया गया नए सिरे से किया गया प्रयास वैश्विक नेट–ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होगा।

सबके लिए सम्पूर्ण स्वास्थ्य: कोविड–19 महामारी के संकट के बाद, स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय अनिवार्यता है। निवारक स्वास्थ्य सेवा वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रही है। भारत ने इन सरोकारों को खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, समग्र चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में चिकित्सा की ऐतिहासिक पद्धतियां और पारंपरिक प्रणालियां वैज्ञानिक सहायता से महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। एकल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के रूप में विश्व और वन हेल्थ की

अवधारणा स्वास्थ्य देखभाल में उपयोगी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच काफी बड़ा फासला और असमानताएं हैं। कृत्रिम आसूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा संवर्धित डेटा–आधारित प्रक्रियाएं, अनुकूलनशील, टिकाऊ और समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित करने में सहायक हो सकती हैं। इससे वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े खतरों संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच वैश्विक तैयारियों, भागीदारी और सहयोग में सुधार होगा।

विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना: विज्ञान को सांस्कृतिक संवाद के दायरे के भीतर लाने की आवश्यकता है। नागरिकों को आवश्यक रूप से विज्ञान के साथ जोड़ा और संलग्न किया जाना चाहिए। विज्ञान और समाज को एक साथ लाने से गलत सूचना और भ्रामक सूचना के जोखिम टाले जा सकते हैं। ऐसा विज्ञान संचार, नागरिक विज्ञान तथा संस्कृति एवं विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों पर विज्ञान समुदाय और अन्य हितधारकों के बीच संवाद के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, जी–20 में एक रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (आरआईआईजी) भी है जिसमें जी–20 के अनुसंधान मंत्रालय और विज्ञान से संबंधित विषयों जैसे स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, आदि पर विचार मंथन करने वाले कई अन्य समूह शामिल हैं। शेरपा ट्रैक के माध्यम से ये सभी इनपुट नेताओं की बैठक में दिए जाते हैं। ■

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा (एकदम दायें) दीप प्रज्ज्वलन के समय अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट

भारत की जी–20 की अध्यक्षता एकजुटता कायम करने की आकांक्षा रखती है, जो बिखरी हुई दुनिया के घाव भर सकती है और 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' की चरमस्थिति पाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। 'जनभागीदारी' के मंत्र का उपयोग करते हुए, जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम भारत की जी–20 की अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख पहल है। यह जी–20 जैसी बहुपक्षीय प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए राष्ट्र के भीतर भविष्य की क्षमताओं का सृजन करता है। यह देश की तीव्र और समावेशी विकास प्रक्रिया को भी दर्शाता है, जिसमें विद्यार्थी हमारे देश के राजदूत हैं। पहले इस पहल के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विश्वविद्यालयों में पूर्व नौकरशाहों, प्रतिष्ठित प्रोफेसरों और विशेषज्ञों द्वारा 75 व्याख्यानों का आयोजन करने का प्रस्ताव था।

भारत के माननीय विदेश मंत्री विद्यार्थियों के साथ।

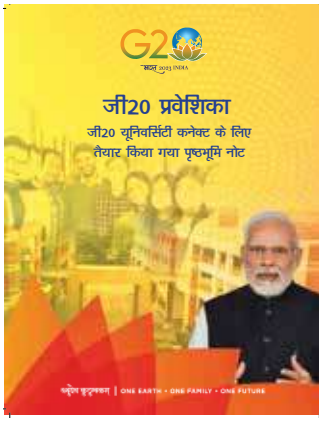

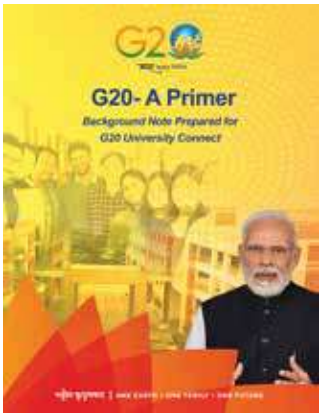

आरआईएस अपने विलक्षण बौद्धिक संसाधनों और पूर्व राजनयिकों, शिक्षाविदों और विषय विशेष के विद्वानों सहित विशेषज्ञों के नेटवर्क के साथ 101 व्याख्यान पूरा करने की प्रक्रिया में है। इस कार्यक्रम ने विचार–विमर्श की अकादमिक प्रकृति को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है और इस व्याख्यान श्रृंखला को अक्टूबर 2023 में संपन्न किए जाने की योजना है।

जी20 प्रवेशिका: क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित

समापन सत्र में गणमान्य प्रतिभागी।

विशिष्ट प्रयोग

इसका उद्देश्य एक ऐसी समावेशी प्रक्रिया का निर्माण करना है, जो हमारे देश के युवाओं को जी–20 प्रक्रिया में सक्रिय हितधारक बनने की अनुमति प्रदान करे। विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यानों के आयोजन से पहले अक्सर वाद–विवाद, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, मॉक जी–20 बैठकें, मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आदि जैसी समन्वित गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित होती हैं। ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों के बीच केवल रुचि ही नहीं जगातीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की कार्यवाही की प्रकृति और समसामयिक वैश्विक मामलों के बारे में संवेदनशील बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्याख्यान देने के लिए चुने गए विशेषज्ञ अक्सर प्रशासनिक अधिकारी और प्रोफेसर होते हैं जो अपने वैविध्यपूर्ण अनुभवों के समृद्ध विवरण विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं। ये विवरण उनके व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने का ठोस आधार बनते हैं। कुछ व्याख्यान विभिन्न समसामयिक विषयों पर उनके वर्तमान महत्व को ध्यान में रखते हुए और कभी–कभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शैक्षणिक केन्द्र बिंदु और भौगोलिक स्थिति पर आधारित होते हैं।

सामयिक भू–राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता

आज का नौजवान लगातार परस्पर अन्तः संबद्ध हो रही दुनिया में बड़ा हो रहा है, जहां विश्व के ऐसे भू–राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति सजग रहना जरूरी है, जो समूचे विश्व पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। संघर्ष, महामारी और पर्यावरणीय आपदाओं सहित प्रमुख वैश्विक घटनाक्रमों को अक्सर मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिलती है। इस मंच ने विद्यार्थियों को ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और नौकरशाहों के साथ सक्रिय रूप से

जुड़ने का अवसर प्रदान किया, जो उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और समकालीन वैश्विक व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। ये प्रबल बातचीत महत्वपूर्ण चिंतन के माहौल को बढ़ावा देने के साथ–साथ वैश्विक प्राथमिकता वाले मुद्दों पर विद्यार्थियों के विचारों को आकार देने में बेहद मददगार रही हैं। इसकी बदौलत ऐसा वातावरण तैयार हुआ है, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सीखने के समग्र अनुभव के लिए बेहद हितकारी रहा है।

भावी नेता तैयार करना

देश के भावी नेताओं का ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीतिक संघर्ष आदि जैसी समसामयिक वैश्विक चुनौतियों से अवगत होना और ऐसे मामलों के बारे में अपनी विशिष्ट समझ विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहल उच्च शिक्षा क्षेत्र में आने वाले बदलावों को भी पूर्णता प्रदान करती है, जो दूरदर्शी भविष्य को बढ़ावा देने में सहायता करेंगे और भविष्य के लिए ऊर्जावान नेता तैयार करेंगे। इससे भारतीय नेतृत्व के निर्णायक, महत्वाकांक्षी, कार्योन्मुख और सुधार से प्रेरित एजेंडे को बरकरार रखने में अपार सहायता मिलेगी। इस श्रृंखला का उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों के नौजवानों को नेतृत्व की संभावनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। इन व्याख्यानों ने मेंटरशिप कार्यक्रमों में भी योगदान दिया और प्रभावशाली रोल मॉडल से सीखने के अनुभवों का युवाओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। मार्गदर्शन देने, प्रेरित करने और महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा करने में मार्गदर्शक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो नेतृत्व की महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं के विकास में योगदान देते हैं। विश्वविद्यालय या संस्थान के स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न पहलों के जरिये युवाओं को वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने, सक्रिय रूप से सहभागिता करने और वैश्विक मामलों की समझ बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से

प्रोत्साहित किया जाता है। विविध संस्कृतियों के प्रति समानुभूति उत्पन्न करने से उत्कृष्ट मानसिकता वाले और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तनों के लिए समर्पित नेताओं के विकास में योगदान मिल सकता है। यह पहल युवाओं को सार्वजनिक भाषण और चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने, महत्वपूर्ण चिंतन के कौशल विकसित करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। विभिन्न संस्थानों में व्याख्यानों के आयोजन से पहले, मॉडल जी–20 वाद–विवाद, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सहित प्री–इवेंट गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उपरोक्त आयोजनों ने विद्यार्थियों का काफी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बेहद उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रदर्शित किया। ऐसी गतिविधियों में सहभागिता से विद्यार्थियों को न केवल पारंपरिक शैक्षणिक विमर्श से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि ये भविष्य के लिए सशक्त नेताओं को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ■

अध्याय II

वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था और सहयोग

कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीतिक संघर्षों और तनावों तथा जैव विविधता की हानि से उपजी तिहरी और समानांतर चुनौतियों ने वैश्विक आर्थिक प्रबंधन और सहयोग के ढांचे पर गंभीर दबाव बनाया है। इन परिस्थितियों ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक इकोसिस्टम में विकासशील देशों के समक्ष मौजूद असमानता और समावेशिता की चुनौतियों को और भी विकराल बना दिया है, एसडीजी के लिए वित्त और प्रतिबद्धता में कमी आई है तथा विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी और क्षमता संबंधी फासले बढ़ गये हैं। आरआईएस ने शोध पत्रों और प्रकाशनों सहित अपनी विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों और संभावित प्रतिक्रियाओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। विदेश मंत्रालय के ITEC कार्यक्रम ने आरआईएस को एसडीजी, विकास साझेदारियों और दक्षिणीय सहयोग जैसे विषयों पर क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों का संचालन करने में सक्षम बनाया।

आरआईएस के वैश्विक विकास केंद्र जीडीसी ने दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और शासन प्रणाली की सहायता, टिकाऊ कृषि, डिजिटल स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, वित्त आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के अनुभवों को साझा करने के लिए साझेदारियों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए। आरआईएस का जीडीसी विभिन्न वैश्विक चर्चाओं और बहुपक्षीय मंचों तथा विविध भारतीय हितधारक संस्थानों के समक्ष विकास संबंधी सहयोग, द्विपक्षीय संबद्धताओं पर ग्लोबल साउथ के सरोकारों को रेखांकित करना जारी रखे हुए है।

मौजूदा दौर विकसित और विकासशील देशों के बीच महत्वपूर्ण असंतुलनों का साक्षी है। धन और संसाधनों में भिन्नताओं के परिणामों ने देश के कल्याण और संभावनाओं पर असर डाला है। इन हितधारकों के बीच मौजूद आर्थिक असमानताओं ने वैश्विक बाजारों और उन्नत औद्योगिक क्षमताओं तक विकसित देशों की पहुंच भी सुनिश्चित की है।

महामारी ने इन दोनों ही तरह के देशों के मतभेदों को और ज्यादा उजागर कर दिया है। गरीबी के उच्च स्तर और आबादी की बड़ी तादाद के अनौपचारिक रोजगारों में संलग्न होने के कारण, लॉकडाउन के उपायों और प्रतिबंधों ने कमजोर आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ऋण सेवा के बढ़ते बोझ सहित सिकुड़ती राजकोषीय स्थिति ने देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) में एसडीजी वित्तपोषण संबंधी फासले को बढ़ा दिया है।

उनके बीच तकनीकी स्तर पर भी बड़ा फासला मौजूद है, जो विकसित देशों की क्षमता से मेल खाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की विकासशील देशों की कोशिशों में बाधक है। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और उन्हें अंगीकार करने के संबंध में भी असमानताएं मौजूद हैं और विकासशील देशों को इंटरनेट तक सीमित पहुंच, कनेक्शन की धीमी गति आदि जैसी डिजिटल अवसंरचना से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक तकनीकी कौशल भी प्रौद्योगिकीय प्रगति के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। इंटरनेट साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की खामियां दर्शाने वाले डिजिटल भेद के संबंध में भी इन दोनों हितधारकों के बीच काफी हद तक भिन्नता मौजूद है। तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में उदार वित्त पोषण, स्थापित अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय विशेष रूप से सहायक हैं, जबकि विकासशील देशों में तकनीकी सफलताओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी बरकरार है।

निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों और पद्धतियों के संबंध में विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच भेद हैं। विकसित देश अपने सुदृढ़ व्यापार नेटवर्क, वितरण चैनलों, अल्प व्यापार बाधाओं और सुनियोजित लॉजिस्टिक्स के साथ मजबूत बाजार पहुंच, वैश्विक व्यापार पर अधिक प्रभाव और व्यापार विविधीकरण की सुविधा का उपयोग करते हैं। विकसित बाजारों तक विकासशील देशों की पहुंच प्रायः अवरुद्ध होती है और सौदेबाजी करने की शक्ति सीमित होती है, उन्हें टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं और कड़े नियमों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन जैसी समसामयिक चुनौतियां भी विकासशील देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। विकासशील देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में विकसित देशों की तुलना में कम योगदान देते हैं, इसके बावजूद उन्हें इसके प्रभावों का भारी बोझ उठाना पड़ता है।

ऐसे में जलवायु संबंधी अन्याय के परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन और उनमें कमी लाने के लिए विकासशील देशों के पास बहुत कम संसाधन और क्षमताएं मौजूद हैं। जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक सीमित पहुंच के साथ, उनके पास जलवायु–के अनुकूल बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और पद्धतियों में निवेश करने के संसाधनों का अभाव है। इन कठिन वर्षों ने उन दोनों के बीच मौजूद संसाधनों और विकास क्षमताओं संबंधी विषमताओं को और अधिक उजागर कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर असमानताएं बढ़ी हैं।

जलवायु परिवर्तन जैसे जोखिमों के साथ ही साथ दुनिया भर के संघर्ष और अशांति भी मौजूदा भू–राजनीतिक परिदृश्य को चुनौती दे रहे हैं। पारंपरिक वैश्विक शक्तियों के आधिपत्य को चुनौती देते हुए उभरती और उदीयमान शक्तियां धीरे–धीरे अपना प्रभाव जमा रही हैं। क्षेत्रीय संघर्षों और सत्ता की खातिर टकरावों ने भी भू–राजनीतिक परिदृश्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। यूक्रेन में जारी संघर्ष, पश्चिम एशिया में जारी टकराव, दक्षिण चीन सागर में तनाव और क्षेत्रीय विवादों के व्यापक भू–राजनीतिक अशांतियों में तब्दील हो जाने की आशंका है।

ऐसे रुझान मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देते हैं और वैश्विक सहयोग के आदर्शों की राह में रुकावटे उत्पन्न करते हैं। आरआईएस वैश्विक क्षेत्र के ऐसे समकालीन घटनाक्रमों से अवगत रहता है और इनके समाधान के लिए प्रभावी विचार–विमर्श की गुंजायश उत्पन्न करने में सक्रिय रहता है। आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक और शांति स्थापना मामलों के विभाग (डीपीपीए),की सहायक महासचिव महामहिम सुश्री एलिजाबेथ मैरी स्पेहर की यात्रा के दौरान प्रमुख भारतीय थिंक टैंक और विख्यात विश्वविद्यालयों के साथ 'शांति और विकास' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। विचार–विमर्श के दौरान समाज के सामान्य दृष्टिकोण के ब्ल्यूप्रिंट के रूप में एसडीजी के महत्व पर जोर दिया गया तथा शांति एवं विकास के साथ इसके पारस्परिक संबंधों पर बल दिया गया। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में शांति और विकास तथा इस गठजोड़ के महत्व के बीच संपर्क को रेखांकित किया गया। चर्चा के दौरान शांति और विकास के समर्थन में दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग की संभावना पर भी जोर दिया गया।

महामहिम सुश्री एलिजाबेथ मैरी स्पेहर, सहायक महासचिव शांति निर्माण सहायता, डीपीपीए, पैनल चर्चा के विशिष्ट प्रतिभागियों को संबोधित कर रही हैं।

ग्लोबल साउथ के अनेक अंतरराष्ट्रीय संकटों से गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कोविड–19 महामारी के कारण हुई अभूतपूर्व तबाही, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे, भू–राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, महंगाई, विशेष रूप से भोजन और ईंधन की बढ़ती कीमतें आदि समूचे वैश्विक समुदाय के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इन चुनौतियों का ज्यादा असर पड़ा है। इसलिए, सभी दक्षिणी विकासशील देश इन अभूतपूर्व चुनौतियों से निपटने के किफायती और टिकाऊ समाधान तलाशने जुटे हैं, क्योंकि एसएससी का दर्शन सामूहिक कार्रवाई और सहयोगियों के बीच एकजुटता पर आधारित है।

विकासशील देशों की बिरादरी का सदस्य होने के नाते भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी फिर से बढ़ाने के लिए तत्पर है, ताकि वह बिखरी हुई विश्व व्यवस्था को नेविगेट करने, दक्षिण की आवाज को बल प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की कायापलट करने का सामर्थ्य रखने वाले सरल, स्केलेबल और टिकाऊ समाधान साझा करके साथी विकासशील देशों में क्षमताएं विकसित करने में सहयोग कर सकें। एसडीजी पर बल दिया जाना, ऐसे किसी भी कार्यान्वयन का स्पष्ट सूचक होगा।

इसी संदर्भ में, आरआईएस ने विकास साझेदारियां : दक्षिणीय सहयोग के बारे में जानना' विषय पर एक ITEC पाठ्यक्रम का अयोजन किया। विकास के लिए सहयोग पर पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एसएससी की व्यापक अवधारणा, विशेषकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और विकासशील देशों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और विकास संबंधी सहयोग में हाल के रुझानों के संदर्भ में इसके डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) की एकीकृत और बहुआयामी समझ से अवगत कराते हुए इसकी विविधता और बहुलता के बारे में जानकारी दी। यह कार्यक्रम सैद्धांतिक ढांचे, वैश्विक संरचना पर केंद्रित था और इसमें समावेशी विकास की राह में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में प्रयासों और चुनौतियों और एसएससी के मूल्यांकन की रूपरेखा को भी शामिल किया गया। इन मुद्दों पर व्यापक जानकारी देने के लिए आरआईएस ने प्रतिभागियों के लाभ के लिए इन–हाउस संकाय के अलावा विख्यात विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा *''ग्लोबल साउथ और विकास साझेदारियों के परिप्रेक्ष्य''* शीर्षक से तैयार की गई रिपोर्ट भी जारी की गई।

सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के बीच सुदृढ़ प्रतिबद्ध ता, सहयोग और साझेदारी की आवश्यकता है। इस दिशा में, आरआईएस–जीडीसी ने वैश्विक विकास संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए दक्षिणीय सहयोग (एसएससी), त्रिकोणीय सहयोग के उपकरणों (टीआरसी) के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के प्रयासों का नेतृत्व किया है।

इसी तरह, सुधार की दिशा में भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल –प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जो डिलीवरी की मौजूदा प्रक्रियाओं को नए सिरे से डिजाइन करने, बायोमेट्रिक सिस्टम (आधार) की सीडिंग के जरिए सही ढंग से लक्षित लाभार्थियों तक लाभों की बेहतर और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ ही साथ सरकार द्वारा

निजी लाभार्थियों को इन–काइंड ट्रांसफर करने से संबंधित है। मलावी के वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ मलावी के इच्छुक प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के महत्व, संबंधित वर्ग के लिए नियोजित धन के 100 प्रतिशत अंतरण की गारंटी के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान की गई।

आरआईएस शैक्षणिक समुदाय, नीति निर्माताओं, व्यवसायियों, सिविल सोसाइटी और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के लिए दिल्ली प्रॉसेस के अंतर्गत सम्मेलनों का आयोजन करता है। दिल्ली प्रॉसेस –6 में, एसएससी, एनएससी और टीआरसी, विकास बैंकों और संसाधनों को जुटाने से आगे बढ़कर, विकास के नए आयामों, वैश्विक विकास पहल तथा साझेदारी और सहयोग के दायरे जैसे प्रमुख विषयों के साथ–साथ विकास के नए आयामों और सहयोग के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया। ग्लोबल गवर्नेंस और एजेंडा 2030 में एसडीजी 2.0 के बारे में नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता पर विचार–विमर्श किया गया। इसके अलावा, विमर्श के दौरान विख्यात प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत बनाने, जनगणना के आंकड़ों को नया रूप देने और व्यापक सामाजिक आयामों के मापदंडों को शामिल करने पर जोर दिया गया।

कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इन नई रूपरेखाओं को आगे बढ़ाने के लिए साझा समस्याओं के समाधान की दिशा में अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों पर चर्चा करने और उन्हें साझा करने के मंच शुरू किए हैं। इस संबंध में, जीडीसी ने दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग के संबंध में कंपाला में दूसरे अफ्रीका उच्च स्तरीय फोरम में भाग लिया, ताकि सतत विकास के लिए तथा विकासशील देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 की प्राप्ति को उत्प्रेरित करने के लिए उपयुक्त अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान–प्रदान और मितव्ययी तकनीकी

भारत के जी–20 शेरपा श्री अमिताभ कांत दिल्ली प्रॉसेस-VI के दौरान उद्घाटन भाषण देते हुए।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद कार्यशाला में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

नवाचारों के हस्तांतरण को सुगम बनाया जा सके।

भारत और अफ्रीका में विकास की बारीकियों में समानता के मद्देनजर जीडीसी ने डरबन में एजेंडा 2030 और 2063 (अफ्रीका) के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा पर अफ्रीकन पीअर रिव्यू मैकनिज्म (एपीआरएम)–यूएन डीईएसए कार्यशाला में भी भाग लिया तथा समावेशी सतत विकास को बढ़ावा देने की क्षमता सहित परखे गए, स्केलेबल विकास समाधानों को रेखांकित किया। एपीआरएम–यूएन और डीईएसए के साथ मिलकर अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं की प्रदायगी के लिए नवोन्मेषी तंत्र की आवश्यकता का विश्लेषण किया गया। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की प्रगति को संभव बनाने के लिए मुख्य रूप से वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं के गहन हस्तांतरण, विकास से जुड़े अनुभवों और ज्ञान को साझा करने की आवश्यकता होगी।

इस अवधि में जीडीसी ने आरआईएस की अंतर–सरकारी गतिविधियों, बहुपक्षीय वार्ता में विकासशील देशों के साथ सहयोग किया है। वैश्विक साझेदारियों की दिशा में किए गए प्रयासों ने देशों को बेहतर तालमेल कायम करने और प्रबल विकास सहयोग की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी क्षमता मजबूत बनाने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। स्थिरता पर विचार करते समय, कार्यक्रमों की शुरुआत परिवर्तन और सुधार के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन देने में सक्षम रही है, जिसका प्रतिभागी देशों द्वारा स्वतंत्र रूप से अनुसरण किया जा सकता है और इस प्रकार मांग से प्रेरित एसएससी के पहलू पर जोर दिया जा सकता है।

विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त ज्ञान समाधान उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय क्षमताएं बढ़ाने में ज्ञान साझा करना अहम योगदान दे सकता है। हाल की महामारी ने वर्टिकल से हॉरिजेंटल विकास से संबंधित सहयोग में आमूल–चूल बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी देशों के सामने असंख्य चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। इस दिशा में अब अतिरिक्त प्रमाण की नहीं, अपितु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसी के अनुरूप, भारत के कोविड–19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को–विन) प्लेटफॉर्म के अनुभव के माध्यम से जीडीसी दक्षिणीय सहयोग की आवश्यकता की प्रबलता से

हिमायत कर रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के सृजन, ज्ञान हस्तांतरण, सहयोगपूर्ण और समन्वित हस्तक्षेपों में सहायता करना और संसाधनों को एकत्रित करना, प्लेटफार्मों का लाभ उठाना तथा स्वास्थ्य के परिणामों में सुधार के लिए स्थायी समाधानों के अवसरों का पता लगाने के लिए साझेदारियों को प्रेरित करना था। इस संबंध में, पेरिस पीस फोरम, दुबई एक्सपो 2020 आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनेक देशों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कार्यशालाएं, वेबिनार, द्विपक्षीय सत्र आयोजित किए गए। इसी तरह के संपर्कों के दौरान जाम्बिया और युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई दिलचस्पी को देखते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सहयोग से गहन द्विपक्षीय सत्र आयोजित किए गए। एनएचए के अधिकारियों ने डेमो के बाद विस्तृत प्रस्तुतियों के जरिए इन देशों को भारत द्वारा को–विन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अरबों भारतीयों का सफल टीकाकरण करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इन देशों में उनके विशिष्ट हितों के बारे जानने के लिए उपयुक्त मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल टीकाकरण संरचना स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने और अगले कदम निर्धारित करने के लिए तकनीकी सहायता की पेशकश की।

इसी के अनुरूप, डेटा सृजित करने की प्रक्रियाओं को समझने के संबंध में भारत के साथ सहयोग करने की इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की मंशा के आधार पर एनएचए की सहायता से इथियोपिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि प्रमाण पर आधारित नीति विकसित करने, महामारी से निपटने की कार्रवाई को प्रोत्साहन देने और उसे लागू करने में सहायता मिल सके। को–विन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वास्थ्य आश्वासन योजना–आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), विशेष रूप से योजना को ट्रैक और संचालित करने में मदद करने के लिए पीएमजेएवाई द्वारा स्थापित रिएल टाइम डैशबोर्ड पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। वर्तमान में, इथियोपिया सरकार द्वारा समुदाय–आधारित स्वास्थ्य बीमा (सीबीएचआई) योजना और इलेक्ट्रॉनिक–सामुदायिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (ई–सीएचआईएस) का संचालन किया जा रहा है। एनएचए अधिकारियों ने इस बात पर बल दिया है कि दावों के मैन्युअल तरीके से प्रॉसेस करने की बजाय, एमओएच, इथियोपिया इतनी बड़ी बीमा योजना के कुशल संचालन के लिए

भारत–मलावी इंटरैक्टिव सत्र में प्रतिभागी।

दावों पर कार्रवाई करने संबंधी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकता है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि भारत सरकार ने सम्पूर्ण टीकाकरण, अंग दान, रक्तदान के लिए को–विन को छोटे दवाखानों और डॉक्टरों के लिए लाइट–एचएमआईएस (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली) के रूप में सेवाएं देने के लिए फिर से एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करने की पहल की है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत एक मजबूत आधार बना रहा है और एबीडीएम के निर्बाध कार्यान्वयन की संभावनाएं तैयार कर रहा है।

एसटीआई नीतियों के अंतर्गत डिजिटल क्षमता निर्माण को मजबूती प्रदान करना और अपने लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल फासले मिटाना जीडीसी के हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। कोविड–19 महामारी ने निश्चित रूप से कई उद्योगों की गति को प्रभावित किया है। इसके बावजूद, भारत लगातार शीर्ष पर रहते हुए डिजिटल भुगतान के परिदृश्य में अग्रणी बनकर उभरा है। इसका फिनटेक उद्योग समृद्ध हुआ है और कैशलेस अर्थव्यवस्था का रुख करने से भुगतान के बुनियादी ढांचे और सक्षम नवाचारों को बढ़ावा मिला है। इस दिशा में, जीडीसी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के सहयोग से अनेक कार्यशालाओं, एक्सपोजर विजिट और अफ्रीका के अनेक देशों (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, मोजाम्बिक, सेशेल्स, मलावी,युगांडा, रवांडा, ज़िम्बाब्वे, गाम्बिया, गैबॉन, आदि) के साथ द्विपक्षीय सत्र, बी2बी और तकनीकी चर्चाओं आदि का आयोजन किया। डिजिटल क्षमता निर्माण को मजबूती प्रदान करने और डिजिटल फासले मिटाने, डिजिटल साधनों से आर्थिक सुधार और वृद्धि पर जोर दिया गया। इन देशों के त्वरित आर्थिक विकास के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), रूपे डेबिट कार्ड, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली आदि जैसे उत्प्रेरक समाधानों को उनके साथ साझा किया गया। सभी प्रतिभागी देशों ने, विशेष तौर पर डिजिटल रूपांतरण में भारत को मिली अपार सफलता के मद्देनजर, विचारों के व्यापक आदान–प्रदान की संभावना और उससे सीख ग्रहण करने की उत्सुकता प्रकट की। ■

डीबीटी प्रणाली पर कार्यशाला में उपस्थित गणमान्य प्रतिभागी।

प्रमुख कार्यक्रम

- आरआईएस ने जर्मनी के दूतावास के सहयोग से 7 जून, 2022 को 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए क्षितिजः जी–7 और जी–20 के बीच तालमेल की संभावनाओं की तलाश' विषय पर हाइब्रिड कार्यक्रम का आयोजन किया।
- जीडीसी भारत–युगांडा द्विपक्षीय सत्र, 28 जून, 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), भारत सरकार और एमओएच युगांडा के बीच को–विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया।
- विदेश मंत्रालय इंटर्नशिप आरआईएस ने 6 जुलाई 2022 को 37 एमईए इंटर्न की मेजबानी की।
- दिल्ली प्रॉसेस ''भारत की जी–20 की अध्यक्षता की ओर : विकास के नए आयामों और प्रगति की रणनीतियों की तलाश–संक्रमण और विवादों के दौर में साझेदारियां' 27–28 अगस्त, 2022।
- आरआईएस में वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) द्वारा डिजिटल भुगतान समाधान पर भारत–मलावी इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया; 28 सितंबर 2022।
- आरआईएस ने सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (सीआरआरआईडी), और अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के सहयोग से चंडीगढ़, भारत में कृषि व्यापार और नीतिगत विश्लेषण के क्षेत्रों में दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया; 29–30 सितंबर, 2022।
- प्रमुख भारतीय थिंक–टैंक और विख्यात विश्वविद्यालयों के साथ 'शांति और विकास' पर पैनल चर्चा। नयी दिल्ली; 6 अक्टूबर 2022.
- आरआईएस और महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, पुणे; योजक, सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुणे; रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, मुंबई; विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी, और सेवा इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप से 14 नवंबर 2022 को ''भारत की जी–20 की अध्यक्षताः विकास संबंधी भारतीय दृष्टिकोण और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका'' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- आरआईएस में वैश्विक विकास केंद्र द्वारा 29 नवंबर 2022 को भारत की जी–20 प्राथमिकताओं पर एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई।
- सुषमा स्वराज भवन, विदेश मंत्रालय में 1 दिसंबर, 2022 को विदेश मंत्रालय के सहयोग से जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कर्टेन रेज़र कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया।
- आरआईएस ने टी–20 और इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सहयोग से 27 दिसंबर 2022 को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 105वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर सीएमएस बिजनेस स्कूल, जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में ''भारत की जी–20 की अध्यक्षता और विश्व आर्थिक व्यवस्था'' विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया।
- 'लर्निंग साउथ–साउथ कोऑपरेशन' पर आईटीईसी कार्यक्रम, 12–23 जनवरी, 2023।

- ' कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (केटीआईसीसी), भोपाल, मध्य प्रदेश में 16–17 जनवरी, 2023 को ''पर्यावरण सम्मत जीवनशैली(लाइफ), नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमयुक्त वैश्विक सुशासन : संरचना, वित्त और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग का संचार'' विषय पर टी–20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- कृषि प्रतिनिधियों की बैठक (एडीएम) के एक अतिरिक्त कार्यक्रम के रूप में आरआईएस ने 13 फरवरी, 2023 को इंदौर में 'खाद्य सुरक्षा हेतु जलवायु–स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक मंच' का आयोजन किया।
- पुद्दुचेरी विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के सहयोग से, आरआईएस ने युवा शोधकर्ताओं और नीति विश्लेषकों को कृषि व्यापार के क्षेत्रों से परिचित कराने के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। पुद्दुचेरी; फरवरी 17–18 2023।
- भारत की जी–20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बारे में 23 फरवरी 2023 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर जेफरी डी. सॉक्स के साथ चर्चा।
- आरआईएस द्वारा 13–24 मार्च, 2023 को एसडीजी पर ई–आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- आरआईएस, नई दिल्ली में 27 मार्च 2023 को आरआईएस और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की आवश्यकता के संबंध में विद्यार्थियों और संकायों के बीच इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन।

प्रकाशन

जी–20 प्रवेशिका : जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के लिए पृष्ठभूमि नोट जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किया गया

रिपोर्ट्स

- ''भारत की जी–20 की अध्यक्षता की ओर : दिल्ली प्रॉसेस VI – विकास के नए आयामों और प्रगति की रणनीतियों की तलाश–संक्रमण और विवादों के दौर में साझेदारियां' आरआईएस, 2023, नई दिल्ली
- ट्रिनिटी ऑफ द साउथ : डेमोक्रेसीज फॉर डेवलेपमेंट आरआईएस, नई दिल्ली, 2022
- भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोगः संभावनाएं और चुनौतियां, आरआईएस, नई दिल्ली, 2022
- महामारी के बाद की दुनिया में भारत–अफ्रीका संबंधों पर गोलमेज, आरआईएस, नई दिल्ली, 2022

चर्चा पत्र

- एसडीजी टार्गेट 10.1 इनेक्विटी एंड इनिक्वालटीज़ : मेशर्मेंट च्वाइसिज एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर्टी सेंसटाइजिंग इन्डिसिज़ प्रमोद कुमार आनंद और कृष्ण कुमार द्वारा
- जी–20 इनिशिएटिव्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस : प्रोग्रेस एंड शॉर्टफाल्स & जी.ए. तडस द्वारा

पत्रिकाएं

- जी–20 डाइजेस्ट, वॉल्यूम 1, नंबर 4
- जी–20 डाइजेस्ट, वॉल्यूम 2, नंबर 1
- डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू वॉल्यूम 6, नंबर 1, जनवरी–मार्च 2023

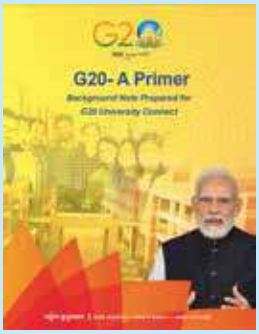

अध्याय III

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा

विकास को प्रोत्साहन देने और गरीबी में कमी लाने में व्यापार की भूमिका सुस्थापित हो चुकी है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि जिन देशों में व्यापार एकीकरण में वृद्धि हुई है, वहां गरीबी में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, 1980 के दशक के मध्य से बहुसंख्य देशों ने अधिक उदार व्यापार व्यवस्था के पक्ष में आयात प्रतिस्थापन नीति को छोड़ दिया है। हालांकि, व्यावहारिक साक्ष्य से पता चलता है कि केवल टैरिफ में कमी किया जाना आवश्यक भले ही हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त करने के लिए इतना भर किया जाना ही काफी नहीं है। अपितु व्यापार में अच्छा प्रदर्शन किसी देश की उदार व्यापार व्यवस्था को कुशल कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा के साथ पूर्णता प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अपर्याप्त परिवहन प्रणाली, खराब लॉजिस्टिक्स और जटिल व्यापार प्रक्रियाएं किसी देश की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं और इस प्रकार व्यापार उदारीकरण से होने वाले लाभ कम कर सकती हैं। यद्यपि पिछले कई वर्षों से बहुपक्षीय मंचों/संगठनों द्वारा व्यापार सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय सहयोग, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तरों पर बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण चैनल के रूप में उभरा है।

आरआईएस क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण रूप से बल देता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, आरआईएस ने अपनी ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 गतिविधियों के साथ–साथ नीतिगत समर्थन के माध्यम से कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंपरा बरकरार रखते हुए, आरआईएस ने पिछले साल भी हिंद–प्रशांत पर अधिक बल देते हुए सीमा–पार व्यापार की सुविधा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देने के लिए कई शोध और नेटवर्किंग गतिविधियों की शुरूआत की। आरआईएस की अनुसंधान गतिविधियों ने नीली अर्थव्यवस्था के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, समुद्री कनेक्टिविटी, ऊर्जा कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करते हुए इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। क्षेत्रीय अवधारणा के रूप में हिंद–प्रशांत के उद्भव और भारत के लिए इसके निहितार्थों का पता लगाने के लिए भी अध्ययन किए गए हैं। आरआईएस बाधाओं की पहचान करने और इन क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए नेपाल, भूटान, आसियान, यूरोपीय संघ, जापान आदि जैसे कई देशों/संगठनों के प्रमुख हितधारकों के साथ भी संपर्क बनाए हुए है।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने विशेषकर मुक्त और असीम विश्व की अवधारणाओं सहित विश्व व्यवस्था के अनेक आयामों को बदल डाला है। सरकारों, सीमा एजेंसियों, लॉजिस्टिक कंपनियों, व्यापारियों, स्वास्थ्य से जुड़े व्यवसायियों, दैनिक वेतन भोगियों और कई अन्य लोगों ने केवल स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं; अपितु सीमा–पार व्यापार और कनेक्टिविटी सहित जीवन के कई अन्य क्षेत्रों पर भी महामारी का प्रभाव महसूस किया। सरकारों ने लोगों की आवाजाही पर रोक और आवश्यक उत्पादों के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए; आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गईं; और इसका दुनिया भर में सीमा–पार व्यापार के प्रदर्शन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर व्यापक असर पड़ा।

हालांकि, इन परिस्थितियों ने सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अधिक सतर्क होने के लिए प्रेरित किया है। हाल की रणनीतियां सीमा– पार व्यापार और कनेक्टिविटी में मौजूद बाधाओं को घटाने , कम से कम आंशिक रूप से घटाने के प्रति लक्षित हैं। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता में सुधार लाने, संस्थागत तालमेल बढ़ाने, डिजिटल व्यापार और ई–कॉमर्स को अपनाने और आकस्मिक संकटों के प्रबंधन के लिए नवोन्मेषी पद्धतियों को अपनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। अनेक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समितियों के लिए आपातकालीन स्थितियों में सीमा–पार व्यापार से निपटना प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रीय सरकारें और व्यापार समितियां जैसे संस्थान कनेक्टिविटी और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए नवोन्मेषी उपाय और रणनीतियां विकसित करने में सहायक हैं।

इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्याय आरआईएस द्वारा पिछले एक साल में विभिन्न शोधों, अध्ययनों, कार्यशालाओं, संवादों और सम्मेलनों के माध्यम से सीमा–पार व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक उत्साहजनक और सक्षम वातावरण बनाने हेतु प्रस्तावित और प्रस्तुत किए गए विचारों और नीतिगत सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अध्याय का भौगोलिक महत्व हिंद–प्रशांत पर केंद्रित है, जो वैश्विक जीडीपी में लगभग 65 प्रतिशत का योगदान देने वाले विशाल क्षेत्र को कवर करता है। व्यापार और कनेक्टिविटी की दुनिया में हिंद–प्रशांत क्षेत्र का भू–रणनीतिक महत्व भी सर्वविदित तथ्य है। व्यापार सुविधा और कनेक्टिविटी में अच्छे बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय मानक निकायों जैसे गुणवत्तापूर्ण अवसंरचनात्मक संस्थानों द्वारा निभाई जाती है। वे मानकों में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मानकों पर आम तौर पर सहमति बन जाती है, तो वे अंतर प्रचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और सीमाओं के पार उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा लगातार सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। दूसरा, परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन और मान्यता के लिए अनुरूपता मूल्यांकन निकाय महत्वपूर्ण हैं। इससे व्यापारियों के बीच विश्वास उत्पन्न करने में मदद मिलती है। अंततः, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण करने वाली संस्थाएं व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए प्रेरक शक्तियां हैं। व्यापार और कनेक्टिविटी के इन मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आरआईएस

आसियान–भारत: पुस्तक विमोचन

आसियान–भारत रणनीतिक साझेदारी को सवंर्धित करते हुए नवंबर 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया। इस अवसर पर, आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने महामारी के बाद के परिदृश्य में आसियान–भारत सहयोग मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार–मंथन करने के लिए 4 नवंबर, 2022 को नोम पेन्ह में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया। आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा *"आसियान–भारत संबंधों के तीस वर्ष: हिंद–प्रशांत की ओर"* नामक स्मारक खंड जारी किया गया। पूर्वावलोकन की साझेदारी कंबोडियन इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन एंड पीस (सीआईसीपी) के साथ की गई।

ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ कई कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और संवाद आयोजित किए। जापान दूतावास और यूरोपीय संघ सहित साझेदारों ने इन आयोजनों की सह–मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपर्युक्त बिंदुओं के अतिरिक्त, ये विचार–विमर्श व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नए नोड्स के रूप में हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा परिवर्तन पर भी केंद्रित था।

समुद्री परिवहन और कनेक्टिविटी वैश्विक व्यापार के आधार हैं। आरआईएस ने सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल शिपिंग मार्गों, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, पारगमन पर कम समय लगने और सुविकसित बंदरगाहों तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री कनेक्टिविटी और परिवहन के बारे में अपनी चर्चा का विस्तार किया। कुल मिलाकर, ये हिंद–प्रशांत में व्यापार और कनेक्टिविटी को प्रभावशाली ढंग से बढ़ा सकते हैं। नीली अर्थव्यवस्था के दायरे में मत्स्य पालन और जलीय कृषि, अपतटीय ऊर्जा, तटीय पर्यटन और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया गया है। इस क्षेत्र में काम जारी रखने के लिए, यह स्वाभाविक ही है कि आरआईएस ने समुद्री संसाधनों और अर्थव्यवस्था को महत्व देना बरकरार रखने के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) की शुरुआत की। सीएमईसी की स्थापना एक समझौता ज्ञापन के जरिए की गई, जिस पर माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में भारतीय बंदरगाह संघ और आरआईएस के बीच हस्ताक्षर किए गए। आरआईएस के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग नीति–उन्मुख अनुसंधान और क्षमता निर्माण के विस्तृत अनुसंधान और प्रसार पर जोर देते हैं, ताकि ग्लोबल कॉमन्स के लिए समुद्र तल पर खनन, महासागर प्रशासन, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान आदि जैसे नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में प्रगति और विकास के बारे में वैश्विक जागरूकता और चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके।

आरआईएस ने विभिन्न स्वरूपों में साझेदारी को मजबूत और सहयोग को व्यापक बनाने के लिए सदैव द्विपक्षीय सहयोग को महत्व दिया है। दुनिया भर में साझेदारों के साथ अपने विभिन्न संवादों के दौरान आरआईएस ने व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने और सुगम बनाने में द्विपक्षीय संबंधों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। आरआईएस द्वारा भूटान, कोरिया, किर्गिस्तान और श्रीलंका के साझेदार संस्थानों के साथ आयोजित द्विपक्षीय वार्ता में इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ वित्तीय समावेशन, परियोजना मूल्यांकन, आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों, आईपीईएफ आदि जैसी विशेषताओं के बारे में भी विचार–विमर्श किया।

मौजूदा रूपरेखाओं के भीतर व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण उपकरण और परिप्रेक्ष्य हैं। आरआईएस ने दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत की उप–क्षेत्रीय और क्षेत्रीय भागीदारी से जुड़ी पहलों में अपनी छाप छोड़ते हुए उपलब्धियां हासिल की हैं। आरआईएस भारत में बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक (बीएनपीटीटी) का संस्थापक सदस्य और नोडल प्वाइंट है। आरआईएस ने चार्टर को अंतिम रूप देने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने और बिम्सटेक सचिवालय को मजबूत बनाने सहित बिम्सटेक द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों को रेखांकित किया है। आरआईएस कनेक्टिविटी और समृद्धि के सेतु के रूप में बिम्सटेक की विलक्षण मजबूती में यकीन रखता है।

बिम्सटेक की ही भांति, आसियान भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल चुका है, क्योंकि वह भौगोलिक रूप से हिंद–प्रशांत के केंद्र बिंदु में स्थित है। आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र ने प्रमुख हितधारकों, आसियान साझेदारों और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वर्ष 2022 को आसियान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया। हिंद–प्रशांत में हितों के तालमेल, भू–राजनीतिक बदलावों और आसियान के महत्व के बारे में विचार प्रकट करने के लिए वेबिनार, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए गए।

आरआईएस द्वारा संचालित विभिन्न अध्ययनों की मुख्य सिफारिशें

इतिहास से सीखना महत्वपूर्ण होता है: जब हम विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रह होते हैं, सभ्यता की कड़ियां दिल में यथावत रहती हैं, क्योंकि आरआईएस का मानना है कि इतिहास से सीखना महत्वपूर्ण होता है। याद करने के लिए, समकालीन सांस्कृतिक विचार, स्वरूप और प्रथाएं, ...विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों में पुरातन संबंधों की प्राचीनता और समृद्धि को विरासत, संग्रहालयों, कला, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कूटनीति, और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में नई प्रतिबद्धता के माध्यम से आगे लाया गया है। अतीत वर्तमान में अस्तित्व में रहता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है।

उच्च आय ही विकास का एकमात्र संकेतक नहीं है: सतत विकास लक्ष्यों के मापदंडों ने समावेशी और समग्र विकास की बारीकियों को बदल दिया है। मौजूदा दौर में, ''देशों का मूल्यांकन विकास के मानदंडों की एक विस्तृत श्रृंखला के आधार पर किया जाता है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों में समानता, जलवायु कार्रवाई, न्याय और मजबूत संस्था और शासन प्रणाली और अन्य विकास संकेतक शामिल हैं।' 'एशिया में ऐसा देखा जा सकता है जहां ''सिंगापुर, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देश आसियान में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, वे एसडीजी के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50 का हिस्सा नहीं हैं। मेलिंडा मार्टिनस द्वारा लिखित एआईसी कार्य पत्र'', *''असेसिंग आसियान–इंडिया फ्यूचर कोऑपरेशन ऑपर्च्यूनिटीज थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क''* पर आधारित यह सिफारिश हमें इस बात का आभास दिलाती है कि देशों को विकास का रुख कैसे करना चाहिए और उस संदर्भ में एसडीजी के मद्दों को प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए।

लोकतंत्र में कानून का शासन : मौजूदा दुनिया और उभरती भू राजनीति के बहुस्तरीय और जटिल रंगमंच होने के बावजूद लोकतांत्रिक नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, यह सिफारिश की जा रही है कि हिंद–प्रशांत को ''मुक्त, नियम–आधारित, समावेशी, ''सभी प्रकार के दबाव से मुक्त'' क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए... लोकतांत्रिक मूल्य और मानदंड हिंद–प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक जगत को परिभाषित करने में पर्याप्त रूप से दिखाई देते हैं, जो व्यापार के मुक्त प्रवाह के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सम्मान को सुगम बना सकते हैं।''

बेहतर व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए बहुपक्षवाद का पालन महत्वपूर्ण : हिंद–प्रशांत में आसियान के नेतृत्व वाले बहुपक्षवाद की भूमिका के बारे में आरआईएस इस बात पर जोर देता है कि बहुपक्षवाद के व्यापक दायरे के भीतर, देश ''संस्कृति, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, पर्यावरण, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।'' (कुंडू 2022, एआईसी कमैन्ट्री सं. 31) हिंद–प्रशांत में, सबसे अच्छा उदाहरण ''भारत और आसियान के बीच मौजूदा संस्थावाद'' होगा जिसे

माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) श्री सर्बानंद सोनोवाल।

''मजबूत बनाने की जरूरत है, नियमित बैठकों की जरूरत है, परियोजनाओं को समय पर लागू करने और लगातार समीक्षा किए जाने की जरूरत है।'' इसके अलावा, जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर एक आलोचनात्मक दृष्टि आरआईएस के वैश्विक आउटरीच के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करती है।

निर्बाध और कागज रहित सीमा–पार व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी व्यापक और समग्र विकास की दिशा में एक कदम है। हिंद–प्रशांत के देशों को अभी तक डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा, अवसंरचना और विभिन्न अन्य पहलुओं के मानकों पर काम करने की जरूरत है। इस अध्याय में हमने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और मानकों को प्राप्त करने हेतु समाज और देशों के बीच सहयोग और साझेदारी में सुधार, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर जी2जी साझेदारी, ट्रैक 1.5 कूटनीति, बहुपक्षवाद, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, टिकाऊ ऊर्जा और समुद्री कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को आरआईएस द्वारा विशेष अहमियत दिए जाने के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ, चुनिंदा आरआईएस प्रकाशनों को ध्यान से पढ़ने से इतिहास, सभ्यतागत संबंधों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से सीखने के महत्व और एक समावेशी दुनिया के निर्माण में उनका योगदान रेखांकित होता है। संक्षेप में, व्यापार सुविधा और कनेक्टिविटी पर आरआईएस का वर्टिकल विशेष रूप से सहकार्य और सहयोग के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, समाजों और संबंधित हितधारकों पर दूरगामी और स्थायी प्रभाव पर नजर रखता है। ■

भूटान के पत्रकारों और संपादकों का प्रतिनिधिमंडल।

जर्नल ऑफ एशियन इकॉनोमिक इंटीग्रेशन

एआईसी, आरआईएस और चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी, थाईलैंड की साझा पहल

विवरण	सेज जर्नल्स द्वारा प्रकाशित पीअर रिव्यू जर्नल
	अप्रैल 2019 –अप्रैल 2023– सभी अंक उपलब्ध। इस समय सीमा में 5 खंड प्रकाशित।
	आवृत्ति– द्विवार्षिक
पाठक संख्या	40,541 (कुल 5 खंडों के पीडीएफ और एचटीएमएल डाउनलोड)
	ईएलएसएसएन 26316854 । आईएसएसएनः 26316846
सार एवं अनुक्रमण	डीप डाइव
	जे–गेट
	ओसीएलसी
	अर्थशास्त्र में शोध पत्र (आरई पीईसी)
	यूजीसी–केयर (समूह।)
	स्कोपस
	गूगल स्कॉलर
संपादक	सचिन चतुर्वेदी
	सुथीफंड चिराथिवत
	प्रबीर डे
सदस्यता ग्रहण करें	https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-asian-economic-integration/journal203596#subscribe

प्रमुख कार्यक्रम

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा नई दिल्ली में जापान दूतावास, आरआईएस और आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र के साथ साझेदारी में 8 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में हिंद–प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के कनेक्टिविटी स्तंभ पर ''मुक्त, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोगः सवंर्धित कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक लचीलेपन का निर्माण'' शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- इस श्रृंखला का दूसरा वेबिनार 22 अप्रैल, 2022 को आभासी रूप से आयोजित किया गया।
- आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, भारत, ईयू एक्सटर्नल एक्शन सर्विस और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) के साथ मिलकर 27 अप्रैल 2022 को 'भारत–ईयू कनेक्टिविटीः नया संदर्भ, नए क्षितिज' का आयोजन किया।
- आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (एआईएनटीटी) की दो दिवसीय आभासी गोलमेज चर्चा (सातवां दौर) 12–13 मई, 2022 को आयोजित की गई थी।
- आसियान और भारत के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक साझेदारी पर 30 जून, 2022 को एक वेबिनार आयोजित किया गया।

- भारत–आसियान संबंधों के तीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा आसियान भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस के सहयोग से ''भूराजनीतिक बदलाव और अवसरः भारत–दक्षिण–पूर्व एशियाई संबंधों में नए क्षितिज'' विषय पर 20–21 जुलाई 2022 को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- 6 अगस्त, 2022 को आरआईएस द्वारा 'श्रीलंका में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और आगे की राह' पर वर्चुअल पैनल चर्चा आयोजित की गई।
- नई दिल्ली, भारत में 8 अगस्त, 2022 को आसियान की 55वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) द्वारा पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।
- आरआईएस में वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 24 अगस्त, 2022 को नयी दिल्ली में बिम्सटेक के महासचिव महामहिम श्री तेनज़िन लेकफेल के साथ ''साझेदारी के माध्यम से विकास का कायाकल्पः बिम्सटेक की भूमिका'' विषय पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया।
- फोरम फॉर इंडियन साइंस डिप्लोमेसी (एफआईएसडी), आरआईएस की ओर से 14 और 20 सितंबर, 2022 को भारत और आर्कटिक पर दो ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किए गए।
- आरआईएस में समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) की स्थापना के लिए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में भारतीय बंदरगाह संघ और आरआईएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) और कम्बोडियन इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन एंड पीस (सीआईसीपी) ने नोम पेन्ह में 19वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर 4 नवंबर, 2022 को संयुक्त रूप से पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया।
- आरआईएस में एआईसी ने ''जी–20: आसियान और भारत के बीच हितों का तालमेल'' शीर्षक से चौथे वेबिनार का आयोजन किया।
- आरआईएस में 22 नवंबर 2022 को भूटान के मीडिया संगठनों के पत्रकारों/संपादकों के साथ इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया।
- आरआईएस ने 30 जनवरी 2023 को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) के महासचिव महामहिम श्री माइकल विलियम लॉज और उनके साथ आए आईएसए प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस प्रतिनिधिमंडल में मैरी बोरेल–मैककिनोन, चीफ ऑफ स्टाफ और प्रमुख, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट, डॉ. मधुमिता कोठारी, वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. होजे डैलो मोरोस, प्रमुख, पर्यावरण प्रबंधन एवं खनिज संसाधन कार्यालय, डॉ सोनकाशी मिश्रा, कार्यक्रम प्रबंधक के शामिल थे।
- आरआईएस ने आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में किर्गिज़ गणराज्य के एक एससीओ रेजिडेंट शोधकर्ता श्री बातिर–मुहम्मद अज़ामतोविच कारागुलोव का 16 फरवरी 2023 को स्वागत किया। उन्होंने आरआईएस संकाय सदस्यों के साथ बैठक में चर्चा में भाग लिया।
- आरआईएस ने 7 मार्च, 2023 को कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी (केआईईपी) के अध्यक्ष किम, हेउंग होंग और केआईईपी के सदस्यों की मेजबानी की; उन्होंने कोरिया–भारत सहयोग की स्थिति और दोनों संस्थानों के बीच सहयोग की भविष्य की दिशा पर चर्चा की।

प्रकाशन

पुस्तक/रिपोर्ट

- कनेक्टेड हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियाः आइकन्स नैरेटिव्स, मॉन्यूमेंट्स, पारुल पंड्या धर, (संपा.)सेज स्पेक्ट्रम, नई दिल्ली, नवंबर 2022

चर्चा पत्र

- इंडो–पेसेफिक स्ट्रेटेजीज : व्हॉट डू दे एन्टेल फॉर इंडिया?, पंकज वशिष्ठ द्वारा

कार्य–पत्र

- मेलिंडा मार्टिनस, ''असेसिंग आसियान–इंडिया फ्यूचर कोऑपरेशन ऑपर्च्यूनिटीज थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क'' एआईसी, कार्य पत्र, रु 11 नई दिल्ली
- थर्टी ईयर्स ऑफ आसियान–इंडिया रिलेशन्स : द स्टॉक–टेकिंग ऑफ आउटकम्स फॉर 1992–2022, सम्पा कुंडू द्वारा

नीतिगत सारांश

- मेकांग गंगा पॉलिसी ब्रीफ संख्या 11, मार्च 2022

एआईसी टिप्पणी

- 30वीं वर्षगांठ पर आसियान–भारत संबंधों को मजबूत करने के तरीके, गुरजीत सिंह, एआईसी टिप्पणी संख्या 29, मई 2022।
- वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए आसियान–भारत साझेदारी, के. श्रीनाथ रेड्डी, एआईसी टिप्पणी संख्या 30, जून 2022।
- अगले 30 में आसियान–भारत सहयोगः व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर, मुहम्मद वफ़ा खारिस्मा और संपा कुंडू, एआईसी टिप्पणी संख्या 31, जुलाई 2022
- समान वैश्विक सतत विकास के लिए जी20 और आसियान–भारत सहयोग, नित्या नंदा, एआईसी टिप्पणी संख्या 32, अगस्त 2022।
- आसियान–भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर, चिंतामणि महापात्र, एआईसी टिप्पणी संख्या 33, सितंबर 2022।
- भारत–सिंगापुर फिनटेक कॉरिडोरः गहरे भारत आसियान वित्तीय संबंधों के लिए एक प्रवेश द्वार, प्रियदर्शी दाश, सिद्धि शर्मा और सुखमनी कौर, एआईसी टिप्पणी संख्या 34, अक्टूबर 2022।
- आसियान–भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022: परिणाम और आगे का रास्ता। प्रबीर डे और तुहिनसुभ्रा गिरि, एआईसी कमेंटरी नंबर 35, नवंबर 2022।
- भारत–जापान संबंध और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसकी संभावनाएं, मकोतो कोजिमा, एआईसी टिप्पणी संख्या 36, दिसंबर 2022।
- आपूर्ति शृंखला विविधीकरण की वैश्विक खोजः क्या भारत को इससे लाभ मिल रहा है? पंकज वशिष्ठ और ऊर्जा तपन, एआईसी कमेंटरी नंबर 37, जनवरी 2023।
- इंडो–पैसिफिक में भारत और आसियान के लिए आगे के रास्ते, इयान हॉल। एआईसी कमेंटरी नंबर 38, फरवरी 2023।
- आसियान–भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022: परिणाम और आगे का रास्ता, एआईसी टिप्पणी
- भारत–सिंगापुर फिनटेक कॉरिडोरः गहरे भारत–आसियान वित्तीय संबंधों के लिए एक प्रवेश द्वार, एआईसी टिप्पणी
- भारत–जापान संबंध और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसकी संभावनाएं।

पत्रिका

- जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, खंड– 4, संख्या– 2, सितंबर

अध्याय IV

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग

वैश्विक मंदी की शुरुआत से बहुपक्षवाद की, विशेष रूप से डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता उपांतिक होती जा रही है, जिसमे बहुपक्षीय प्रक्रिया में अनेक चुनौतियों जैसे डब्ल्यूटीओ में सुधार, विशेष और विभेदक उपचार, विवाद निपटान तंत्र जैसे मुद्दों के समाधान ढूँढना शामिल है। दोहा दौर के समय से मत्स्य पालन सब्सिडी जैसे लंबित मुद्दों का अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है, जबकि पिछले एमसी12 में सदस्य देशों की संतुष्टि के अनुकूल सदस्यों द्वारा हर मुमकिन प्रयास किए गए थे। संगठन की क्षमता से परे अधिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए, डब्ल्यूटीओ के जनादेश का विस्तार करने के लिए मेगा क्षेत्रों का दबाव बढ़ रहा है। रुस–यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, और इस संदर्भ में भारत और विश्व अर्थव्यवस्था पर के लिए इस स्तिथि के निहितार्थ को समझने के लिए आरआईएस ने अनुकरण विश्लेषण द्वारा उपयुक्त नीतियाँ विकसित करने का प्रयास किया है। साथ ही, आरआईएस ने बांग्लादेश, विएतनाम, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मॉरीशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, कोरिया, आदि सहयोगी देशों के साथ, और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के ढाँचे में आईबीएसए, आईओआरए, बिमस्टेक, आरसीईपी, जीसीसी, आशियान, ब्रिक्स सहित क्षेत्रीय समूहों के भारत के साथ व्यापार संबंधों की जाँच के लिए कई अध्यन्न भी किए है। विभिन्न भागीदारों के साथ व्यापार वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए आरआईएस ने व्यापार मुद्दों के समाधान के लिए कई पद्धतियाँ विकसित करने के साथ नये विचारों पर भी प्रयोग कर रहा है, जिसमें निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की जाँच के लिए भारत का अपने व्यापार साझेदारों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के डेटा के स्थान पर राज्य स्तरीय व्यापार डेटा का उपयोग करना शामिल है। आरआईएस कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय मूल शृंखला के विभिन्न चरणों को विकसित करने, निर्यात केंद्र को विकसित करने के लिए *'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'* योजना के प्रभाव की जांच करने, एमएसएमई क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन और मूल्यांकन करने, और आयुष क्षेत्र की निर्यात क्षमता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर भी शोध कार्य कर रह है। इन प्रयोगों ने आरआईएस को भारत में व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है।

यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका में क्षेत्रवाद की लहर के पुनरुत्थान के साथ ही 1960 के दशक से समूची दुनिया में देशों की परस्पर आर्थिक निर्भरता का रुझान प्रकट हो रहा है। वर्ष 1990–2008 के दौरान बढ़ते वैश्वीकरण ने मूल्य श्रृंखला क्षेत्र के माध्यम से बढ़ते व्यापार के साथ अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक एकीकरण को मजबूत बनाया है। यद्यपि भू–राजनीतिक तनाव बढ़ने से विवैश्वीकरण या डिग्लोबलाइजेशन का जोखिम बढ़ा है, जिसका वैश्विक उत्पादन और व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने देशों द्वारा घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित किए जाने के कारण 2023 में वैश्विक व्यापार के 2.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान व्यक्त किया है, जो महामारी के बाद वर्ष 2022 में वैश्विक मांग में अचानक वृद्धि के कारण 5.1 प्रतिशत हो गया था (आईएमएफ, 2023)। पिछले वर्ष अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के कारण उपजे प्रतिकूल प्रभावों से स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। महामारी, पूर्वी यूरोप में भू–आर्थिक तनाव, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी, संरचनात्मक सुधारों की धीमी गति आदि जैसे बाहरी कारकों के कारण वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं, व्यापार और सभी अर्थव्यवस्थाओं में समग्र आर्थिक वृद्धि के प्रति देनदारी बढ़ जाने की संभावना है। विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त निराशावाद के बावजूद, देशों की क्षेत्रीय/द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए प्रतिबद्धताओं की रफ्तार बढ़ रही है। आरआईएस बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से संबंधित कई अध्ययन और परामर्श

चित्र 1: आरटीए की संख्या में तेजी

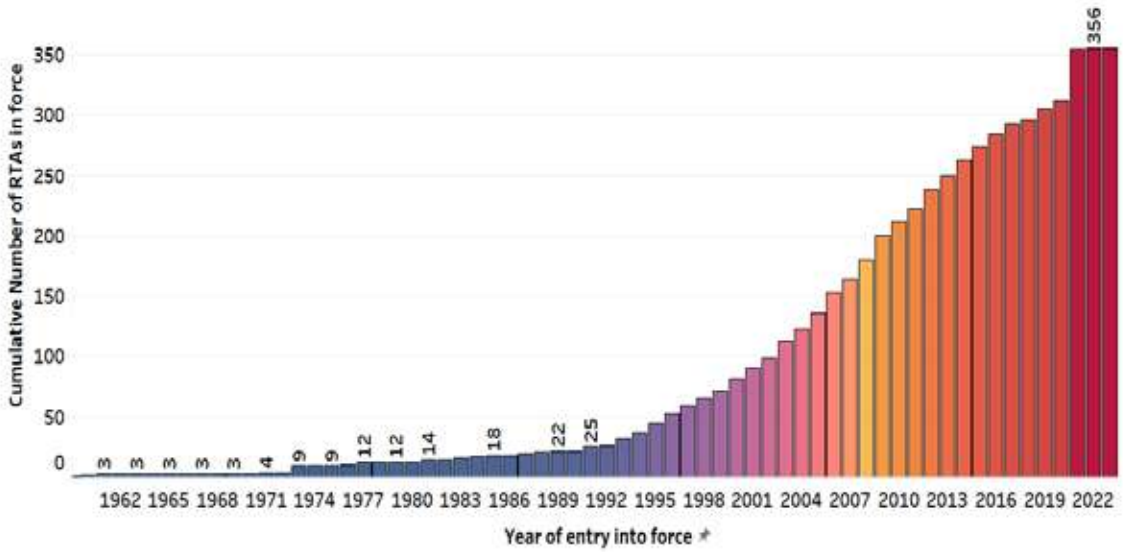

आयोजित करके वैश्विक व्यापार और निवेश के मुद्दों पर लगातार काम कर रहा है।

वैश्विक मंदी के जारी रहने के बीच क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) का प्रसार डब्ल्यूटीओ के हाल के आंकड़ों में बखूबी परिलक्षित हुआ है। जून 2023 तक, डब्ल्यूटीओ ने 356 प्रभावी आरटीए तथा आरटीए की लगभग 585 अधिसूचनाएं दर्ज की हैं, जो 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के आरंभ के बाद से प्रभावी हैं। चित्र–1 विश्व अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की संख्या के तेजी से बढ़ने को दर्शाता है। यहां इस बात पर गौर करना दिलचस्प होगा कि 2020 के बाद लगभग 43 नए आरटीए लागू हुए हैं, जबकि कोविड–19, रूस–यूक्रेन संघर्ष, महंगाई और आपूर्ति में व्यवधान तथा कमोडिटी और तेल की कीमतों में उछाल के कारण वैश्विक व्यापार को बड़ा आधात पहुंचा है। साथ ही, केवल आरटीए की संख्या ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि ऐसे नए क्षेत्रों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिन पर वे समझौते केंद्रित हैं। सिंगापुर के मुद्दों के अलावा, सरकारी खरीद, सीमा पार डेटा प्रवाह, डेटा सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा नीति, पर्यावरण और श्रम मानक आदि डब्ल्यूटीओ–प्लस और डब्ल्यूटीओ–एक्स्ट्रा के मुद्दों का दायित्व 21वीं सदी के अनेक नए आरटीए में लिया गया है। इनमें से अनेक मुद्दों पर अभी तक बहुपक्षीय मंच पर बातचीत जारी है, लेकिन 2000 के दशक में मेगा–क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (एमआरटीए) के उदय के साथ इन्हें प्रमुखता मिली है।

मेगा–क्षेत्रीय समझौतों का उद्भव वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभिन्न अनसुलझे मुद्दों के इकट्ठा होने का परिणाम है। दोहा में डब्ल्यूटीओ की वार्ता में ठहराव, विकसित देशों के विकास में परिपूर्णता की स्थिति आना और समानांतर रूप से विकासशील देशों में हो रही वृद्धि, टैरिफ वरीयता में कमी, तथा अर्द्ध निर्मित वस्तुओं एवं पुर्जों और संघटकों के व्यापार में बढ़ोत्तरी जैसे मुद्दे ट्रांस–पैसिफिक भागीदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौता (सीपीटीपीपी), ट्रांस अटलांटिक व्यापार एवं निवेश भागीदारी (टी–टीआईपी), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) आदि जैसे कुछ एमआरटीए के प्रस्तावों के लिए महत्वपूर्ण हैं। विश्व के जीडीपी और व्यापार में एक–चौथाई से अधिक के महत्वपूर्ण योगदान के साथ ये समझौते दुनिया

माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, भारत श्रीमती मीनाक्षी लेखी एसएईएस, 2022 में उद्घाटन भाषण देते हुए।

के अन्य आरटीए की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हैं। मात्रात्मक रूप से,एमआरटीए के तहत विचारित मुद्दे, पारंपरिक सिंगापुर मुद्दों के अतिरिक्त हैं और *'सीमा पर'* मुद्दों की तुलना में *'सीमा के पीछे'* व्यापार संबंधी मुद्दों पर केंद्रित हैं। इनमें से अनेक एमआरटीए कड़े नियमों और विनियमों के साथ व्यापार के लिए नए और उच्च मानक बनाने के प्रति लक्षित हैं, जो एफडीआई तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के गंतव्य बदलने की ओर प्रवृत्त हैं। व्यापार और निवेश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे नए और उच्च मानकों का दोहराव कई अन्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों में प्रमुखता से देखा गया है। उदाहरण के लिए, हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) वार्ता में, कई सदस्य देश सीपीटीपीपी मानकों के लिए जोर दे रहे हैं। दुनिया भर में विकसित हिंद–प्रशांत संकल्पना में निवेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बुनियादी ढांचा, डिजिटलीकरण, फिनटेक, चौथी औद्योगिक क्रांति, नीली अर्थव्यवस्था और त्रिकोणीय सहयोग प्रमुख क्षेत्र हैं। इतना ही नहीं, डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व के लिए इन एमआरटीए द्वारा प्रस्तुत खतरे पर इससे संबद्ध साहित्य में चर्चा होती रही है।

डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर के मुद्दों पर बहुपक्षीय स्तर पर विनियमन तंत्र के माध्यम से उपजे शून्य के 21वीं सदी के एमआरटीए द्वारा समाप्त हो जाने की संभावना है। 21वीं सदी के व्यापारिक समझौतों से निपटने में डब्ल्यूटीओ की अपरिवर्तित *'कार्य प्रणाली'* पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, ऐसे प्रमाण भी मौजूद हैं, जहां वैश्विक व्यापार की निगरानी के लिए बहुपक्षीय व्यापारिक मंच के रूप में डब्ल्यूटीओ की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण साबित हुई है। 2008 का वित्तीय संकट और कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी का उद्भव आदि कुछ ऐसी आपात स्थितियां हैं, जहां डब्ल्यूटीओ ने क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के बिना व्यापार के मुक्त प्रवाह में योगदान दिया और वैश्विक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में विवाद निपटान तंत्र (डीएसएम) के इस्तेमाल के विपरीत, डब्ल्यूटीओ के डीएसएम का

उपयोग सुस्थापित है और सभी सदस्य देशों द्व ारा विश्व व्यापार प्रणाली में उसे बखूबी इस्तेमाल किया गया है। बाली पैकेज, नैरोबी पैकेज जैसी डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में महत्वपूर्ण सफलताएं, डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय समझौतों का उपयोग और मत्स्य पालन सब्सिडी जैसे समझौतों का संपन्न होना, आपात स्थिति में डब्ल्यूटीओ द्वारा उठाए जाने वाले कदम, खाद्य सुरक्षा और कृषि, और 2022 में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी12) में जिनेवा पैकेज के तहत डब्ल्यूटीओ सुधारों ने डब्ल्यूटीओ के पुनरुत्थान की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। आरआईएस अपनी प्रमुख रिपोर्ट–*वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट* (डब्ल्यूटीडीआर) में, *अन्य बातों के अलावा,* प्रौद्योगिकी और व्यापार का भविष्य, बहुपक्षीय समझौतों और मेगा–एफटीए का प्रसार, विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) प्रावधान में कुछ विकासशील देशों को शामिल करने पर जारी चर्चा, डब्ल्यूटीओ सुधार, मूल्य श्रृंखलाओं का विखंडन, व्यापार और पर्यावरण, व्यापार में महिलाओं की भूमिका आदि डब्ल्यूटीओ से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा है, जो डब्ल्यूटीओ प्रक्रिया को मजबूत बनाने और वैश्विक क्षेत्र में नियम–आधारित व्यापार गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाती है। चतुर्वेदी, साहा और शॉ (2022) ने ब्रिक्स और विश्व में उच्च–प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत शामिल प्रावधान विकासशील देशों के लिए एसएंडडीटी तंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का विरोध करते हैं। हालांकि ग्लोबल साउथ का पिछले चार दशकों से लगातार विस्तार हो रहा है। वर्ष 2020–25 के लिए 6.8 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के साथ *साउथ माइनस चाइना* की विकास की संभावनाएं अनुकूल प्रतीत होती हैं, जो 7.6 प्रतिशत पर ग्लोबल साउथ के साथ तुलनीय हैं। हालांकि, दक्षिणी देशों के भीतर व्यापार का प्रसार असमान है और उस पर विशेषकर डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर वैश्विक स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक अन्य वैश्विक मुद्दा, जहां दुनिया को विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कुछ पृथक दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ रहा है, वह है व्यापार और जलवायु परिवर्तन का दुष्चक्र, जहां बहुपक्षीय व्यापार गवर्नेंस के माध्यम से अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के शमन पर समान रूप से बल देते हुए वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने पर वैश्विक सहमति की आवश्यकता है। डब्ल्यूटीओ का अनुमान है कि कुल कार्बन उत्सर्जनों का 25 प्रतिशत सीमा–पार उत्पादन और वितरण प्रक्रिया से जुड़ा है। हालांकि, विश्व ''प्रदूषण का स्वर्ग'' की व्यवस्था से पर्यावरण के अनुकूल व्यापार की दिशा में रुख किए जाने का साक्षी रह चुका है। प्रौद्योगिकी–प्रेरित हरित उत्पादों के माध्यम से व्यापार का रुख पर्यावरण के अनुकूल बनाना कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों द्वारा व्यापार और उत्पादन में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) और स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौती (वीईआर), जैसी कार्बन क्रेडिट योजनाएं, नवीकरण ीय ऊर्जा, कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र आदि के उपयोग के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि पृथक देशों में जलवायु–संबंधी अनेक नीतियों के कारण कार्बन रिसाव हुआ है, प्रदूषणकारी गतिविधियां कठोर कानूनों वाले देशों से उदार कानूनों वाले देशों की ओर स्थानांतरित हुई हैं। हाल ही में शुरु किए गए ईयू कार्बन कर को ''हरित संरक्षणवाद'' के उपाय के तौर पर देखा गया है, जहां यह व्यापार और वैश्विक उत्पादन की दक्षता को विकृत करने वाली आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ा रहा है। स्थिरता के बहाने, यूरोपीय

संघ गैर–टैरिफ बाधाओं के एक नए स्वरूप–कार्बन सीमा समायोजन कर के साथ विदेशी और घरेलू बाजारों के बीच कीमतों को ''समान'' करते हुए यूरोपीय संघ के उत्पादकों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसरों को बढ़ावा देने का दावा करता है। इस कार्बन कर का विरोध केवल अल्प विकसित देशों (एलडीसी) तथा ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिका जैसे देशों के लिए भी चिंता का विषय है। आरआईएस संकाय का टी–20 नीतिगत सारांश इंगित करता है कि इंडोनेशिया की जी–20 की अध्यक्षता के तहत, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं (ईएसजी) के हरित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रौद्योगिकियों (ईएसटी) को बढ़ावा देने से जलवायु परिवर्तन पर दबाव में कमी आएगी। हालांकि, विकासशील देशों की कमी ईएसटी तक पहुंच कायम करने में उनकी असमर्थता है। विकासशील देशों को उचित मूल्य पर ईएसटी का हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता है और इससे वैश्विक क्षेत्र में व्यापार की पर्यावरण के प्रति अनुकूलता बढ़ेगी।

भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने में योगदान देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत ने नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी), राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, आदि सहित जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी), जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के साथ 2070 के नेट–जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की है, जो अंततः 2022 में अंगीकृत दीर्घकालिक कार्बन विकास रणनीति की दिशा में योगदान दे सकता है। भारतीय रेल की तरह देश के कई प्रमुख क्षेत्र, भारत द्वारा अपना राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने से पहले ही नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सतत उत्पादन और उपभोग

समारोह में प्रतिष्ठित प्रतिनिधि।

बॉक्स 1: बिम्सटेक क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य व्यापार के आकलन की कार्यपद्धति

मौजूदा साहित्य में, कृषि उत्पादों को पोषण, खाद्य सुरक्षा, उत्पादन आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और व्यापार वर्गीकरण के साथ वर्गीकरण का एकीकरण साहित्य में विरला ही देखा गया है। व्यावहारिक अर्थ में, कृषि वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार वर्गीकरण में व्यापक भिन्नता है, जहां एफएओ उत्पादन वर्गीकरण खाद्य समूहों को मछली, मांस, खाद्य पदार्थ इत्यादि में विभाजित करता है, और व्यापार वर्गीकरण का हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कृषि उत्पादों को चार भागों या 24 एचएस चैप्टर्स में वर्गीकृत करता है। ''डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर ट्रेड इन द बिम्सटेक रीजन'' से संबंधित अध्ययन प्रसंस्कृत भोजन के लिए व्यापार वर्गीकरण को अपनाता है, जैसा कि मोहंती (2006 और 2014) तथा मोहंती और गौड़ (2022) में परिभाषित किया गया है। इस वर्गीकरण ने 6–अंकों वाले एचएस कृषि उत्पादों को 11 समूहों अर्थात मछली, मांस, अंडे, फल, सब्जी, कॉफी, चीनी, डेयरी, अनाज, खाद्य पदार्थों और तेल में बांटा है। *'स्माइल कर्व'* के ढांचे के अंतर्गत इस वर्गीकरण का परिचय और उपयोग व्यापार वार्ता और नीति निर्धारण के लिए डेटा का विश्लेषण करने का आधार प्रदान करेगा।

स्रोतः मोहंती और गौड़ (2022)

(एससीपी) की अवधारणा इस वर्ष की भारत की जी–20 की अध्यक्षता के तहत टी–20 कार्य समूह में लाइफ (पर्यावरण सम्मत जीवनशैली) पर एक अलग कार्य बल और सभी कार्य समूहों और मंत्रिस्तरीय बैठकों में क्रॉस–कटिंग क्षेत्र के रूप में प्रभावी ढंग से अंतर्निहित की गई है। टी–20 कार्य समूह में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण आरआईएस ने इस विषय पर कई कार्यशालाएं, पैनल चर्चाएं और संगोष्ठियां आयोजित की हैं। आईपीईएफ के सदस्य के रूप में, भारत ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ के तहत प्रतिबद्धताओं के बारे में बातचीत करता रहा है। यह 21वीं सदी के समझौतों में विभिन्न डब्ल्यूटीओ–प्लस और डब्ल्यूटीओ–एक्स्ट्रा क्षेत्रों में उद्यम करने की दिशा में उगाए गए अनेक कदमों में से एक है। भारत के क्षेत्रवाद की नई लहर के अंतर्गत ऐसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है।

भारत 2019 में आरसीईपी वार्ता से हट गया था। हालांकि, गौरतलब है कि यह वार्ता भारतीय परिप्रेक्ष्य से असंतुलित थी। केवल चीन के मामले को छोड़कर, सदस्य देशों के साथ भारत के मौजूदा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौते कुछ हद तक संतुलित हैं। अपनी नई एफटीए नीति के तहत भारत विभिन्न देशों के साथ सक्रियता से जुड़ रहा है। दूसरी लहर 2021 में शुरू हुई थी, उसी साल भारत ने मॉरीशस के साथ सीईसीपीए पर हस्ताक्षर किए और 2022 में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए। कनाडा, ब्रिटेन, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), यूरोपीय संघ, आईपीईएफ, इज़राइल, आदि कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत व्यापार समझौते कर रहा है। एफटीए के प्रति भारत के नए दृष्टिकोण को क्षेत्रवाद के इस नए चरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जहां उन चुनिंदा देशों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति है जिनके साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक हित हैं, लेकिन

उद्योगों की आवश्यक तैयारियों के साथ डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, स्वच्छ ऊर्जा, कराधान और पारदर्शिता आदि जैसे नए मुद्दों से निपटना होगा। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने हाल के अपने एक लेख *''व्हाय बायलेटरल ट्रेड डील्स आर बेनेफिशियल फॉर इंडिया''* में कहा कि देश ने ''एफटीए के प्रति अति महत्वाकांक्षी रुख'' अपनाया है, तथा बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार में यह खुलापन व्यापार की गति को बढ़ावा देगा और –भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि बरकरार रखने में मदद करेगा। भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित होने के लिए भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए नियम अपनाने के लिए राजी करना होगा। भारत–ईयू एफटीए के संबंध में भौगोलिक संकेतक (जीआई), श्रम मानक, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, विलय नियंत्रण, ऊर्जा और कच्चा माल, टिकाऊ खाद्य प्रणालियां, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), आदि जैसे नए क्षेत्रों पर चर्चा होती है और इनमें से अनेक समझौते भारत के लिए नए हैं। 21वीं सदी के आरटीए के साथ संबद्ध होने के लिए भारत ऐसे समझौतों को लंबे समय तक टालने का जोखिम नहीं उठा सकता और आंतरिक सुधारों के जरिए कठोर निर्णय लेने का समय आ चुका है। आरआईएस ने कई अध्ययन किए हैं तथा भारत–जीसीसी एफटीए, भारत–कनाडा एफटीए और भारत ऑस्ट्रेलिया सेवा वार्ता जैसे उन एफटीए के बारे में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को जानकारी प्रदान की है, जिनके साथ वर्तमान में बातचीत जारी है। साथ ही उन संभावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है जहां साझेदार के बाजार में भारत लाभ प्राप्त कर सकता है। भारत–जीसीसी एफटीए के संबंध में, आरआईएस का अनुसंधान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारत में जीसीसी की निर्यात संभावनाओं की तुलना में, जीसीसी क्षेत्र में भारत की निर्यात संभावनाएं अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के लिए अधिकांश निर्यात संभावनाए संयुक्त अरब अमीरात में है, जहां वह पहले ही द्विपक्षीय एफटीए संपन्न कर चुका है, उसके बाद जीसीसी क्षेत्र में सऊदी अरब के साथ ऐसा किया गया है। वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का

प्रोफेसर अभिजित दास

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

प्रोफेसर एस. के. मोहंती

राजदूत जयंत दासगुप्ता

आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारी आरआईएस में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेते हुए

लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत ने हाल ही में अपनी नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 प्रस्तुत की है, जो पिछली एफटीपी की तरह, पांच साल तक सीमित नहीं है। सरकार ने अपनी रणनीति का रुख प्रोत्साहन–आधारित व्यवस्था से इकोसिस्टम–सृजन करने वाले वातावरण की ओर मोड़ दिया है, जिसमें कारोबार की सुगमता पर समान रूप से बल देने के साथ ही साथ कृषि और एमएसएमई समूहों, उच्च–प्रौद्योगिकी निर्यात, ई–कॉमर्स निर्यात इत्यादि सहित निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों पर केन्द्र बिंदु किया गया है।

नए एफटीए साझेदार के साथ संबद्धता का आशय पारंपरिक व्यापारिक साझेदार से अलगाव हरगिज नहीं है। भारत अपने आस–पास और दुनिया के अन्य हिस्सों में पारंपरिक साझेदार के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को समान रूप से बढ़ावा दे रहा है। बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) की भारत के आस–पास और विश्व में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बढ़ती भूमिका पर 2003 से वैश्विक अर्थव्यवस्था में गौर किया जाता रहा है (चतुर्वेदी, 2022)। यह क्षेत्र सब–प्राइम संकट, महामारी और रूस–यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति में व्यवधान के दौरान आर्थिक उथल–पुथल के दबाव को सह सकता है और तमाम समस्याओं के बावजूद उच्च विकास दर बरकरार रखने के लिए खुद को लचीला बना सकता है। इस क्षेत्र ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कृषि व्यापार में व्यापार अधिशेष प्रस्तुत किया है। बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार में भी कृषि क्षेत्र में प्रगति देखी गई है, 2020 में इस क्षेत्र में क्षेत्रांतर्गत व्यापार लगभग 6 प्रतिशत रहा, जबकि उसकी तुलना में समग्र क्षेत्रांतर्गत व्यापार 9 प्रतिशत रहा। आरआईएस –आईएफपीआरआई–पीआरसीआई रिपोर्ट 2022 –डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर ट्रेड इन द बिम्सटेक रीजन' के अनेक परिणाम, व्यापार उदारीकरण वाले देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए फलों और सब्जियों तथा तैयार भोजन जैसे

विशिष्ट कृषि क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के तहत वर्गीकृत, जैसा कि बॉक्स 1 में वर्णित है, मछली, खाद्य पदार्थ और चीनी प्रमुख क्षेत्र हैं जहां इस क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्रांतर्गत व्यापार होता है (मोहंती और गौड़, 2022)। इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय देशों की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्र को दुनिया के कृषि व्यापार केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करने की भी क्षमता है। आरआईएस द्वारा अप्रैल 2022 में आयोजित तेरहवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) में 'व्यापार सहयोग और मूल्य श्रृंखला स्थानीयकरण', क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, जो क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं को सक्षम बनाने वाले वातावरण का निर्माण करने पर केंद्रित रही। स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, वित्त, एससीपी, डिजिटलीकरण, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु परिवर्तन आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी महामारी के बाद क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

आरआईएस अनुसंधान स्तंभों के तहत व्यापार, निवेश, वित्त और आर्थिक सहयोग में मुद्दों का विशाल कैनवास है। ऐसा एक कार्यक्रम आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं और दो भूटानी राजनयिकों के लिए एक प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) के लिए और दूसरा गाम्बिया के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकरियों के लिए था, जिसमें अनुसंधान के माध्यम से सृजित ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापार संबंधों के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों और अन्य आर्थिक सहयोग के मुद्दों को कवर किया गया था। व्यापार, निवेश और विकास निगम में आरआईएस अनुसंधान कार्यक्रम भारत में कई मंत्रालयों में नीति–निर्माण प्रक्रिया में और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों और नीति निर्माताओं सहित प्राप्तकर्ताओं की व्यापक रेंज के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करता है।

आरआईएस और इसके संकाय की देखरेख में प्रकाशित कार्यों को वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। पिछले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरआईएस को क्षेत्र में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा था। आरआईएस नीति निर्माताओं को उपयोगी और आवश्यक इनपुट प्रदान करने में अग्रणी रहा है, चाहे वह रिपोर्ट, नीतिगत सारांश, मोनोग्राफ आदि के प्रकाशन के रूप में हो या सरकार द्वारा सीधे मुक्त व्यापार वार्ता और संयुक्त अध्ययन समूह रिपोर्ट शामिल हो। ■

प्रमुख कार्यक्रम

- आरआईएस और साझेदार संस्थानों द्वारा 19 और 20 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में तेरहवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) का आयोजन किया गया।
- आरआईएस ने 20 मई, 2022 को गाम्बिया के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के एक शिष्टमंडल का स्वागत किया।
- आरआईएस द्वारा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (एसएसआईएफएस), नई दिल्ली के सहयोग से 05–07 जुलाई, 2022 के दौरान आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं और दो भूटानी राजनयिकों के लिए तीन दिवसीय प्रेरण या इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम) का आयोजन किया गया।
- आरआईएस द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) और सेवा भारत के सहयोग से 22 मार्च, 2023 को यूएन हाउस, नई दिल्ली में 'सक्रिय प्रतिभागियों और आर्थिक विकास के प्रेरकों के रूप में महिलाएं: आजीविका और देखभाल के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित' विषय पर टी–20 (कार्य दल 6) साइड इवेंट के लिए एक दिवसीय पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।
- आरआईएस ने एमईए और भारत.ईयू पर ईयू.यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा के सहयोग से 2 जून, 2022 को 'ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग: सतत ऊर्जा संक्रमण की ओर' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

प्रकाशन

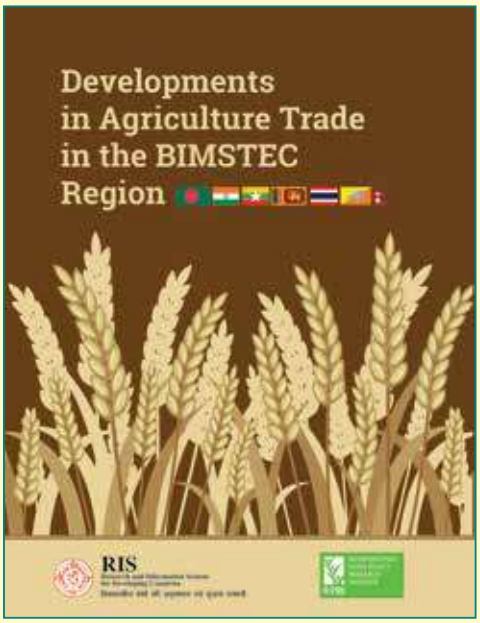

अध्याय V

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

आज की तेज़ रफ्तार और त्वरित रूप से विकसित हो रही दुनिया में, पारंपरिक ज्ञान (टी के), प्रौद्योगिकी और सामाजिक मुद्दों का संयोजन एक लुभावना परिदृश्य प्रस्तुत करता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। यह अध्याय अत्याधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) नीति, और पारंपरिक चिकित्सा (टी एम) के महत्व और वैश्विक विकास के एजेंडे में इसके सम्मिलन से लेकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की परिवर्तनकारी क्षमता और भविष्य की पूंजी के रूप में बच्चों में निवेश जैसे विविध विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन संयोजनों के बहुमुखी पहलुओं की पड़ताल करता है। भारत की जी–20 की अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए आरआईएस के अनुसंधानकर्ताओं ने विज्ञान कूटनीति, आयुष निर्यात के लिए गैर–टैरिफ बाधाओं, पारंपरिक ज्ञान–टी के, पारंपरिक चिकित्सा–टीएम और कल्याण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण और मूल निवासियों तथा भारत से संबंधित अंतरराष्ट्रीय चर्चा जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन किया है।

कृत्रिम आसूचना (एआई) और रोबोटिक्स से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा और ब्लॉकचेन तक जैसी नई प्रौद्योगिकियों के संभावित लाभों का उपयोग करने और समान पहुंच और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल भेद को पाटना और पारंपरिक ज्ञान की प्रणालियों को प्रौद्योगिकीय समाधानों में एकीकृत करना टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आरआईएस का अनुसंधान समावेशी विकास और महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी नीतियों को निरुपित करने हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों और सामाजिक मुद्दों सहित एसटीआई के बीच ऊर्जावान संबंधों को समझने पर केंद्रित है। विज्ञान कूटनीति वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। हम जी–20 की अध्यक्षता के दौरान राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने और साझा समस्याओं से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की भूमिका का अन्वेषण करते हैं। ऐसे प्रयास ज्ञान–साझा करने, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सामूहिक प्रयासों को सुगम बनाते हैं।

कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा–टीएम की उपयुक्तता समग्र जांच–पड़ताल का विषय है। अनुसंधानकर्ता पारंपरिक उपचारों की वैश्विक स्वीकृति और पहुंच को सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ आयुष उत्पादों के निर्यात में गैर–टैरिफ बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं। आरआईएस की एफआईटीएम टीम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, बीमारियों का बोझ कम करने और सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने हेतु पारंपरिक चिकित्सा–टीएम का लाभ उठाने के लिए रणनीतियों का विश्लेषण करती है। जी–20 देशों के संदर्भ में कल्याण को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा–टीएम की भूमिका रेखांकित की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभाव और सतत विकास के लिए व्यापक निहितार्थ की समझ इन प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोगपूर्ण प्रयासों को बढ़ावा देती है। अनुसंधानकर्ता राजनयिक और सॉफ्ट पावर उद्देश्यों के लिए इसके पारंपरिक ज्ञान–टीके का लाभ उठाने के लिए भारत द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली रणनीतियों की भी छानबीन करते हैं। भारत की वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक विरासत मूल निवासियों के समुदायों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विमर्शों का विषय है। इन सार्थक चर्चाओं की जांच से मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के वैश्विक महत्व को समझने में मदद मिलती है।

भारत की जी–20 की अध्यक्षता की प्रतिबद्धता के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों में निवेश करने पर जोर दिया गया है। आरआईएस अनुसंधान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सक्षम वातावरण बनाने और बाधाएं मिटाने से निर्णय लेने, नेतृत्वकारी भूमिका निभाने और उद्यमशीलता में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, से केवल महिला–पुरुष समानता में ही नहीं, अपितु व्यापक सामाजिक उन्नति में भी योगदान मिलता है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और सुरक्षित वातावरण प्रदान करके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, कुशल कार्यबल के निर्माण, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने और गरीबी के चक्र को तोड़ने में योगदान देता है तथा उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार राष्ट्रीय सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाओं से परे बीमारी के प्रकोप, पर्यावरणीय अपकर्ष, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि आदि जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। कृत्रिम आसूचना (एआई), रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), नैनो–क्वांटम और जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकियों जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियां तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं और समाज में बदलाव लाने के साथ ही साथ विकास से जुड़ी अनेक चुनौतियों से निपटने की अपार संभावनाएं प्रस्तुत कर रही हैं। साथ ही, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर पड़ने वाले परिणामों के संबंध में, निश्चितता के अभाव के कारण समाज और अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करने के संदर्भ में अनेक मुद्दे मौजूद हैं। इसलिए, इनका विनियमन और नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक से ही विज्ञान कूटनीति ने नए सिरे से ध्यान खींचा है। इसका यह अभिप्राय हरगिज नहीं है कि विज्ञान कूटनीति के उदाहरण इससे पहले मौजूद नहीं थे। बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव के साथ इस बात का बड़े पैमाने पर अहसास होने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने, अल्प या तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों वाले देशों के बीच सेतु बांधने, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता, बहुपक्षवाद में सुधार, प्रमाण–आधारित संधि और समझौते की बातचीत के साथ ही साथ सामान्य और वैश्विक चुनौतियों को हल करने में विज्ञान कूटनीति का दायरा अपरिमित है। व्यावहारिक, चुस्त, संतुलित और समावेशी विज्ञान कूटनीति की आवश्यकता है, जो स्थान और संदर्भ–विशेष और खासतौर पर ग्लोबल साउथ के भीतर मौजूद जरूरतों, आवश्यकताओं और विविधताओं को समायोजित करती हो।

इस संदर्भ में, आरआईएस की–विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी कार्य योजना में अनुसंधान गतिविधियों के दो पहलू अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति कार्यक्रम (एसटीआईपीपी) और विज्ञान कूटनीति (एसडी) कार्यक्रम शामिल हैं। निम्नलिखित खण्डों में उन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने की दिशा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग और किफायती तकनीकी समाधानों की तलाश और उनका प्रसार किया जाना महत्वपूर्ण है। एसटीआई नीतिगत क्षेत्र के तहत, आरआईएस विकास और उसके सामाजिक–आर्थिक पहलुओं, प्रभाव के आकलन और मूल्यांकन सहित व्यापक परिदृश्य को कवर करने वाले कई अनुसंधान अध्ययनों में संलग्न है। हाल ही में, आरआईएस ने एसडीजी के लिए एसटीआई पर एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना पूरी की (जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा समर्थित थी)। इसकी रिपोर्ट में 'भारत के लिए एसडीजी रोडमैप हेतु एसटीआई' और भारत के लिए 'एसडीजी प्रौद्योगिकी मैपिंग के लिए एसटीआई' के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका और प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र (टीएफएम) के प्रति भारत के योगदान से संबंधित पहलू को भी शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में एसडीजी खास तौर पर भूखमरी मिटाना (एसडीजी 2), स्वास्थ्य और कल्याण (एसडीजी 3), जल और स्वच्छता (एसडीजी 6) तथा किफायती और स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी 7) पर केंद्रित प्रमुख एसडीजी लक्ष्यों से संबंधित चुनौतियों के लिए एसटीआई को मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक रोडमैप और दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन्हें अपनाने की लागत को कम करने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाओं के माध्यम से साझा किया जा सकता है।

आरआईएस संकाय ने एसडीजी में शिक्षा के योगदान के साथ ही साथ आपदाओं से निपटने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी चर्चा में योगदान दिया है

इसके अलावा, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे को हासिल करने में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शक्तिशाली साधन स्वीकार करते हुए आरआईएस ने डिजिटलीकरण और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। यह एसटीआई नीति कार्य योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है, जो विकास के संबंध में डिजिटलीकरण से होने वाले लाभ को रेखांकित करता

है तथा क्षेत्रों और राष्ट्रों में मौजूद डिजिटल भेद से संबंधित सरोकारों और डिजिटलीकरण से लाभ प्राप्त करने में कौशलों, संस्थानों और अवसंरचना की भूमिका पर भी पर्याप्त रूप से प्रकाश डालता है। इस दिशा में, आरआईएस ने पांच महाद्वीपों के आठ देशों को जोड़ने वाले और डिजिटलीकरण के सामाजिक, आर्थिक, शासन और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने की दिशा में प्रयासरत होराइजन 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित "प्रोडिजीज़" परियोजना में संस्था के साथ भागीदारी की। पिछले साल, आरआईएस के इस परियोजना से संबंधित संकाय सदस्य बॉन में जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (आईडीओएस) में प्रतिनियुक्ति के लिए गए थे। इस साल के आरंभ में, आरआईएस ने भी जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग के एक वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता की मेजबानी की, जो इस परियोजना में प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के तहत, विशेष रूप से वर्तमान भू–राजनीतिक तनाव के संदर्भ में डिजिटल संप्रभुता और डेटा प्रशासन पर काम कर रहे थे। वर्ष के उत्तरार्ध में आरआईएस के एक अनुसंधानकर्ता को प्रतिनियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग (जर्मनी) भेजा जाएगा। "प्रोडिजीज़" परियोजना की परिणति निकट भविष्य में सहयोगपूर्ण अनुसंधान और प्रकाशनों में होगी।

समूची दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली वैश्विक महामारी पर गौर करते हुए वैश्विक संकटों के व्यापक मानवीय, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, आरआईएस ने यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित होराइजन 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में आरंभ की गई "प्रीपेयर्ड" नामक परियोजना में कई संस्थाओं के साथ भागीदारी की। यह परियोजना भविष्य में महामारियों से मुकाबला करने के लिए त्वरित, नैतिकता पर आधारित, प्रत्याशित उपायों पर ध्यान केंद्रित करती है और महामारी के दौरान उत्पन्न होने वाले नैतिकता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनसे निपटने की रूपरेखा और दिशानिर्देश विकसित करने के उद्देश्य से भविष्य में महामारियों का सामना करने के लिए तत्पर रहने के प्रति लक्षित है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) में वैश्विक नैतिकता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती बहस का विषय बन गया है। आरआईएस ने एसटीआई नीति में पहुंच, समता और समावेशन (एईआई) की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त किया है। एईआई का एक महत्वपूर्ण पहलू जेंडर और एसटीआई है। वैश्विक स्तर पर विज्ञान में महिलाओं के अल्प प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों द्वारा विशिष्ट नीतियों, पहलों और संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से इस उपेक्षा, असमानता और अल्प प्रतिनिधित्व को दूर करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आरआईएस टीम चर्चाओं में योगदान दे रही है और उसने यूनेस्को के साथ 'ए ब्रेडेड रिवर' नामक पुस्तक पर काम किया है जो भारत में महिलाओं और एसटीईएम के मुद्दों और चुनौतियों को हल करती है। आरआईएस के एक संकाय और आरआईएस के एक पूर्व अनुसंधानकर्ता ने पिछले साल दिसंबर में भारत में महिलाओं और एसटीईएम पर सेमिनार, मासिक संगोष्ठी के एक अंक का संपादन किया। आरआईएस विज्ञान, विशेषकर उभरती प्रौद्योगिकियों में एईआई पर काम करना जारी रखेगा।

उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावों पर अनुसंधान एसटीआई नीतिगत क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इनमें कृत्रिम आसूचना (एआई) और रोबोटिक्स प्रमुख प्रौद्योगिकियों के रूप में विकसित हो रहे हैं। रोजगार के साथ–साथ जिम्मेदार अनुसंधान और नवाचार के पहलुओं के संबंध में इन प्रौद्योगिकियों के नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रभाव (ईएलएसआई) का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने और किसी का भी पीछे नहीं छूटना सुनिश्चित करने के लिए समावेशी और जिम्मेदार एआई पर जोर देना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ

में, यूरोप और भारत के बीच तुलनात्मक अध्ययन के तहत डिजिटलीकरण के संबंध में डिजिटल रणनीतियों और सार्वजनिक नीतियों पर अनुसंधान किया गया। टीम ने एआई को विनियमित करने की मुश्किलों, भारत के पास वैश्विक डेटा शासन व्यवस्था को आकार देने के अवसर और ओपन सोर्स सीड मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए निजी स्वामित्व वाले बीज क्षेत्र के अधिक प्रभुत्व के विकल्पों की आवश्यकता के कारणों का अध्ययन किया है। आरआईएस इस मुद्दे पर नीति आयोग और यूनेस्को के साथ काम करने की योजना बना रहा है और निकट भविष्य के लिए कुछ कार्यक्रमों और प्रकाशनों की योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त आरआईएस आरंभ होने जा रहे सेंटर ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई के जरिए जिम्मेदार एआई के संबंध में आईआईटी–एम के साथ काम करेगा।

आरआईएस ने सिंथेटिक बायोलॉजी पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ काम करने की पेशकश की है। उभरती प्रौद्योगिकियों पर आरआईएस अनुसंधान में चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) और उसके प्रभाव शामिल हैं। निकट भविष्य में हम उभरती प्रौद्योगिकियों पर संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और कुछ प्रकाशन पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। हम हाल के घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं जैसे कि जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) जिसने 2020 की वैश्विक जैव विविधता योजना और बीबीएनजे (राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता) संधि प्रक्रिया को अपनाया है, जो एक संधि के साथ पूरी हो गई है जिसे जल्द ही अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एबीडीआर के आगामी अंक के लेखों में डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) सहित इन घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की गई है।

चीन पर तकनीकी निर्भरता घटाने और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की बढ़ती मांग भारत के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है, जिसके पास दुनिया का पांचवां विशालतम दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) भंडार है। भारत अपने आरईई भंडार का उपयोग एक उन्नतिशील उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र को स्थापित करने में कर सकता है। आरआईएस अनुसंधान भारत और हिंद–प्रशांत में इसके उभरते रणनीतिक साझेदारों के लिए आरईई के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन इस दिशा में वित्तीय, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। इसलिए विकास के प्रारंभिक चरण में स्पष्ट नीति और वित्तीय सहायता के संदर्भ में सरकारी सहायता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

आरआईएस अपने प्रसार और आउटरीच प्रयासों के तहत नियमित रूप से एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू (एबीडीआर) नामक अपनी ओपन एक्सेस अंतरराष्ट्रीय विद्वत समीक्षित ऑनलाइन पत्रिका प्रकाशित करता है और एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला का संयोजन करता है। वर्ष के दौरान इसके अंक भारत–ऑस्ट्रेलिया कृषि जैव प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने, सिंथेटिक जीव विज्ञान की कानूनी, नैतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों, भारत में पादप ऊतक संस्कृति के व्यावसायीकरण, डिजिटल अनुक्रम सूचना और जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) के लिए पक्षकारों के 15 वें सम्मेलन पर केंद्रित थे। जल्द ही केंट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल साइंस एंड एपिस्टेमिक जस्टिस (जीएसईजे) के साथ संयुक्त रूप से एबीडीआर का खंड 25 सं. 1, ''बायोइकॉनोमी फॉर द कॉमन गुड'' पर विशेषांक प्रकाशित किया जाने वाला है। 2023 एबीडीआर का रजत जयंती वर्ष है, इसलिए दो दिवसीय सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है और उस अवसर पर कुछ प्रकाशन भी जारी किए जाएंगे।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरआईएस द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, टेरी, सीईएफआईपीआरए और विज्ञान प्रसार के सहयोग से अगस्त 2017 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रसार के साथ–साथ सामाजिक आकांक्षाओं की बहस को व्यापक बनाना तथा जिम्मेदारीपूर्ण अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और समाज के बीच की खाई

को पाटना है। एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला में एसटीआई से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के विख्यात विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। इस अवधि के दौरान दिए गए व्याख्यानों में मस्तिष्क विज्ञान अनुसंधान, स्थिरता की नीतिगत चुनौतियां, समुद्री कचरा और माइक्रोप्लास्टिक्स प्रदूषण, हाई सीज़ और समुद्री जैव विविधता के लिए संधि, सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की दिशा में भारत में उठाए गए कदम आदि विषयों पर दिए गए व्याख्यान शामिल हैं।

आरआईएस, एसटीआई कार्य योजना की शुरुआत से ही विकास संबंधी नीतिगत दृष्टिकोण से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के मुद्दों पर अनुसंधान कर रहा है। बीते वर्षों में, इसने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और प्रकाशनों में योगदान देने के साथ ही साथ संबंधित क्षेत्रों पर नीतिगत परामर्श/इनपुट भी प्रदान किया है। आरआईएस ने एसटीआई से संबंधित विभिन्न विषयों के क्षेत्र में क्षमता का निर्माण किया है और अक्सर यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का पसंदीदा ज्ञान भागीदार रहा है। उस अवधि के दौरान विषय पर समसामयिक घटनाक्रमों और विषय पर विमर्श को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान विषयों और आउटपुट के दायरे और पहुंच में काफी वृद्धि हुई है।

विज्ञान कूटनीति

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, हमने अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ के साथ–साथ ग्लोबल साउथ के कुछ देशों को भी विज्ञान कूटनीति पर नए सिरे से गौर करते और विज्ञान कूटनीति से संबंधित अनेक कदम उठाते देखा है। विज्ञान कूटनीति की सैद्धांतिक रूपरेखा ग्लोबल–नॉर्थ पर केंद्रित होने के कारण, ग्लोबल साउथ की विज्ञान कूटनीति के शब्दकोश की परिकल्पना किया जाना महत्वपूर्ण है। आरआईएस की कार्य योजना विज्ञान कूटनीति के संबंध में इसी दिशा में ध्यान केंद्रित करती है। यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, सामान्य और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ–साथ एजेंडा 2030 की सार्वभौमिक प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए विज्ञान कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग का लाभ उठाने से संबद्ध है। आरआईएस संकाय ने दक्षिण और मध्य एशिया में भारत की ओर से की गई पहलों के साथ–साथ विज्ञान कूटनीति की सीख में योगदान दिया है। अपने विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम के अलावा, आरआईएस ने विज्ञान कूटनीति पर एक उन्नत कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव पर डीएसटी से चर्चा हो चुकी है। फिलहाल डीएसटी इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।

वर्ष 2018 से, आरआईएस विज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, नेटवर्क निर्माण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। संकाय ने भारत की विज्ञान कूटनीति के बारे में युवा प्रशिक्षु राजनयिकों, थाईलैंड और भूटान के राजनयिकों को व्याख्यान दिए हैं। आरआईएस को उसकी सक्रिय सहभागिताओं और प्रयासों के कारण, एसटीआई कूटनीति की थीम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा नीति अनुसंधान के लिए उपग्रह केंद्र (एसपीआर) के रूप में मान्यता दी गई है। एसपीआर के उद्देश्य और कार्य स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए थीम के तहत नीति अनुसंधान करना है।

शीत युद्ध के दौरान बाह्य अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग विज्ञान कूटनीति का मशहूर उदाहरण है। इस अवधि के दौरान आरआईएस कार्य योजना में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अनुसंधान प्रमुखता से उभर कर आया। भारत सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने के लिए निजी उद्यमों और स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन देने, सक्षम बनाने, अधिकृत करने और निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं। अंतरिक्ष और उसकी अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचानते हुए, आरआईएस ने दूरसंचार और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर अनुसंधान करने के लिए सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आरआईएस ने अक्टूबर 2022 में आयोजित भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस के पहले संस्करण में भाग

लिया। 24 जून, 2020 को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन–स्पेस) की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ाना और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। आरआईएस ने विशेष रूप से बिम्सटेक देशों के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए इन–स्पेस के साथ एक परियोजना शुरू की है।

प्रसार और आउटरीच के प्रयासों के तहत आरआईएस ओपन एक्सेस विद्वत समीक्षित ऑनलाइन पत्रिका *साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू (एसडीआर) का प्रकाशन* करता है। इस अवधि के दौरान पत्रिका के तीन अंक प्रकाशित हुए हैं। हाल ही में, केंट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल साइंस एंड एपिस्टेमिक जस्टिस(जीएसईजे) के साथ संयुक्त रूप से 'न्यू साइंसेज ऑफ साइंस डिप्लोमेसी' विशेषांक प्रकाशित किया गया। ग्लोबल साउथ से जी–20 ट्रोइका के बाद भारत की जी–20 की अध्यक्षता की भूमिका स्वीकार करते हुए जल्द ही साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू का विशेष जी–20 अंक प्रकाशित किया जाएगा। इस अंक में विज्ञान कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग और एसटीआई के संबंध में जी–20 से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के केंद्र में मौजूद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के साथ–साथ सामान्य चुनौतियों से निपटने और एसडीजी हासिल करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी समाधानों को साझा करने पर नजर रखने के लिए टीम *साइंस डिप्लोमेसी न्यूज अलर्ट* (पाक्षिक) प्रकाशित करती है। हाल ही में, भारत की जी–20 अध्यक्षता के महत्व और विचार–विमर्श में एसएंडटी की केंद्रीयता स्वीकार करते हुए जी–20 का एक नया खंड शुरु किया गया।

फोरम फॉर इंडियन साइंस डिप्लोमेसी (एफआईएसडी) के तत्वावधान में नियमित आधार पर अनेक सार्वजनिक व्याख्यान भी आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की आर्कटिक नीति के आरंभ और आर्कटिक में भारत की सहभागिता के बढ़ते महत्व और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की केंद्रीयता को देखते हुए आर्कटिक पर एफआईएसडी व्याख्यान आयोजित किए गए। भारत की आर्कटिक नीति और उसकी गतिविधियों से संबंधित नियमित इनपुट प्रदान करने और गतिविधियों का संचालन करने के लिए एनएससीएस द्वारा आरआईएस को अग्रणी थिंक–टैंकों के संघ का हिस्सा बनने के लिए भी चुना गया है।

भारत की मौजूदा जी–20 की अध्यक्षता के दौरान, आरआईएस जी–20 के विज्ञान–20 (एस–20) सचिवालय, आईआईएससी और आईएनएसए के साथ निकट संपर्क बनाए हुए है, ताकि वह एस–20 विचार–विमर्श में अपनी सहभागिता की रूपरेखा तैयार कर सके। आरआईएस के संकाय ने पुडुचेरी में आयोजित एस–20 आरंभिक बैठक में भाग लिया। आरआईएस ने आईएनएसए द्वारा आरंभ की जाने वाली एस–20 नीति वेबिनार श्रृंखला में शामिल होने में भी दिलचस्पी जाहिर की। आरआईएस को मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में रामनगर, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली पहली जी–20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज बैठक (जी–20–सीएसएआर) में भाग लेने 'समावेशी और कार्रवाई–उन्मुख वैश्विक एसएंडटी नीतिगत संवाद के लिए संस्थागत तंत्र' विषय पर बोलने के लिए पीएसए कार्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था।

आरआईएस एसटीआई टीम ने अपने नेटवर्किंग प्रयासों के तहत फरवरी 2023 में आरआईएस का दौरा करने वाले दक्षिण कोरियाई एसएंडटी काउंसलर के साथ ही साथ इंडिया–कोरिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन (आईकेसीआरआई) के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया और आगामी महीनों में एसटीआई

से संबंधित मुद्दों पर सिलसिलेवार वेबिनार आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाया।

अब जबकि आरआईएस अपनी स्थापना के चौथे दशक में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में अनुसंधान के विषयों, प्रकाशनों, सहयोग और नेटवर्क के संदर्भ में *अन्य बातों के साथ–साथ* एसटीआई कार्यक्रम के विस्तार और विविधता पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा।

इस अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम से जुड़े संकाय ने सहकर्मी–समीक्षित साहित्य और लोकप्रिय मीडिया में विभिन्न विषयों पर तथा कार्यक्रम के तहत किए गए अनुसंधान के आधार पर योगदान दिया। 2023 की जी–20 टी–20 प्रक्रिया में विषयों से संबंधित छह नीतिगत सारांशों का योगदान दिया गया। पिछले साल इंडोनेशिया की अध्यक्षता के दौरान, जी–20 टी–20 प्रक्रिया में चार नीतिगत सारांशों का योगदान दिया गया था। ■

वेबिनार में प्रमुख वक्ता।

प्रमुख कार्यक्रम

- फोरम फॉर इंडियन साइंस डिप्लोमेसी (एफआईएसडी) द्वारा 27 मई 2022 को आरआईएस में "बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और बाह्य अंतरिक्ष प्रशासन में उभरती चुनौतियां" विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया।
- आरआईएस ने 28 सितंबर 2022 को "अमृत काल के दौरान वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए भारत की अपरिहार्यताएं" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया।
- आरआईएस में 29 सितंबर, 2022 को जीडीसी द्वारा मलावी के लिए 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- आरआईएस और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में "सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार" विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- 43वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 28 अप्रैल 2022 को " मस्तिष्क विज्ञान पर अनुसंधान में निवेश क्यों करें?" विषय पर श्री सेनापति गोपालकृष्णन (क्रिस), सह–संस्थापक और पूर्व उपाध्यक्ष, इंफोसिस, अध्यक्ष, एक्सिलर वेंचर्स और अध्यक्ष, सीआईआई एआई फोरम और सीआईआई स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा दिया गया।

- 44वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 28 जून, 2022 को "स्थिरता की नीतिगत चुनौतियां'' विषय पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के पूर्व अवर महासचिव और टेरी की शासी परिषद के अध्यक्ष श्री नितिन देसाई द्वारा दिया गया।
- 45वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 30 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर, चेन्नई) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रवाकर मिश्रा द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय "भारतीय तट पर समुद्री कचरे और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति –राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति की आवश्यकता" था।
- 46वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान, 30 दिसंबर 2022 को डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, साइंस डिप्लोमेसी फेलो, आरआईएस द्वारा "महासागर और समुद्री जैव विविधता के लिए उभरती संधि" विषय पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया।
- 47वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 24 जनवरी 2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग (जर्मनी) के सूचना विज्ञान विभाग में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापक, प्रोफेसर डॉ. इंग्रिड श्नाइडर द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय "भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौर में डिजिटल संप्रभुता और डेटा गवर्नेंस" था।
- 48वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 31 मार्च 2023 को आईसीएमआर–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (एनआईसीपीआर) की निदेशक डॉ. शालिनी सिंह द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय था "सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलनः भारत में उठाए गए कदम" था।

प्रकाशन

परिचर्चा पत्र

- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए अकादमिक–उद्योग इंटरफेस की संभावित भूमिकाः भारत के समक्ष उभरते नीति विकल्प, द्वारा चैतन्य गिरी

पत्रिकाएं

- एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा, खंडः 24, संख्या 1, मार्च, 2022
- साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू, खंड 4, संख्या 2, अक्टूबर 2022
- एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा, खंड 24, संख्या 2, जुलाई 2022

अध्याय VI

पारंपरिक चिकित्सा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स की मांग में वृद्धि के बीच पारंपरिक हर्बल दवाओं के उपयोग में उनके मूल देशों के बाहर भी वृद्धि हो रही है। इस मांग के परिणामस्वरूप पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र की वृद्धि और विकास के सकारात्मक अनुमानों के कारण इनके विस्तार, नवाचार और संस्थागतकरण से संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए विचार–विमर्श किए जा रहे हैं। स्वयं भारत का आयुष क्षेत्र निर्यात में लगातार वृद्धि का साक्षी बन रहा है, हालांकि प्रत्येक बाजार में पारंपरिक चिकित्सा के संबंध में अलग–अलग विनियामक व्यवस्थाओं और व्यापार के लिए गैर–टैरिफ बाधाएं उसकी पहुंच को सीमित करती हैं। मानक रूप से शास्त्रीय ग्रंथों से प्राप्त सूत्रों पर आश्रित और नए रासायनिक सत्वों के उपयोग के विरुद्ध आयुष उद्योग के भीतर, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आईपीआर का उपयोग एक विवादास्पद बहस है।

एफआईटीएम की इस वर्ष की कार्य योजना में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में उपरोक्त उल्लिखित मुद्दों पर नीतिगत अनुसंधान शामिल है। पारंपरिक दवाओं पर राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्शों के रुझानों के आकलन में बैकएंड और फॉरवर्ड लिंकेज पर अनुसंधान, टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं से लेकर एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीतिगत और गवर्नेंस पहल और वन हैल्थ फ्रेमवर्क में एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में उपयोगिताओं तक का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। आयुष मंत्रालय द्वारा उपयुक्त नीतिगत आउटपुट को शामिल करने के लिए एफआईटीएम द्वारा आयुष उद्योग, विनिर्माण और सेवाओं दोनों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। पहले आयुष विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के बाद, इस वर्ष एफआईटीएम ने स्वास्थ्य प्रणाली में स्थिरता, एकीकरण, नवाचार, व्यापार और संस्थागतकरण के उभरते मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। एफआईटीएम भारत की जी–20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा पर आरआईएस और आयुष मंत्रालय की गतिविधियों में भी योगदान दे रहा है।

आयुष निर्यात के लिए गैर–टैरिफ बाधाएं

हर्बल औषधि के वैश्विक व्यापार में आयुष निर्यात में काफी वृद्धि देखी गई है, हालांकि इस क्षेत्र की व्यापार क्षमता का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा सका है। राष्ट्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर बढ़ते प्रयासों के बावजूद, पारंपरिक दवाओं की उनके मूल देशों के बाहर फार्मास्यूटिकल्स के रूप में स्वीकार्यता अब तक क्रमशः विकसित होने के क्रम में है। बाज़ार तक पहुंच काफी हद तक आयातक देशों के अधिकार, गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी विनियामक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, जिनमें व्यापक पैमाने पर भिन्नता होती है। एफआईटीएम की रिपोर्ट 'आयुष निर्यातः प्रमुख बाजारों में विनियामक अवसर और चुनौतियां' उन देशों/क्षेत्रों यानी अमरीका, यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापक रुझानों या प्रवृत्तियों पर केंद्रित है, जहां सभी आयुष उत्पाद श्रेणियों (50 प्रतिशत) में भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं। यह रिपोर्ट इन बाजारों में आयुष फार्मास्यूटिकल्स के लिए औषधि पंजीकरण कानूनों की उपयुक्तता का विश्लेषण करती है। यह प्रमुख व्यापार बाधाओं (टैरिफ और गैर–टैरिफ) और बाजार तक पहुंच हासिल करने के लिए भारतीय निर्यातकों द्वारा अपनाए गए विविध विनियामक मार्गों पर गौर करती है। इसमें सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) को हर्बल निर्यात में कुछ मुख्य बाधाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत द्वारा संभावित प्रतिकृति के लिए यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों में टीसीएम दवा पंजीकरण के लिए चीन द्वारा अपनाई गई नीतिगत रणनीतियों की पड़ताल करती है। यह इन बाजारों में पूरक चिकित्सा सेवा क्षेत्र के विकास के साथ रुझानों और संबंधों पर भी गौर करती है। अंत में यह वैश्विक अनुरूपता मूल्यांकन मानदंडों के अनुपालन में मानकों तथा पता लगाने की क्षमता को सुव्यवस्थित करके बाजार तक अधिक से अधिक पहुंच के लिए नीतिगत रणनीतियों का सुझाव देती है।

पारंपरिक चिकित्सा के लिए रक्षात्मक और सकारात्मक सुरक्षा उपकरण के रूप में आईपीआर

बढ़ता पारंपरिक चिकित्सा उद्योग नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आईपीआर के उपयोग की संभावनाओं पर भी गौर कर रहा है। 1992 में जैविक विविधता सम्मलेन के साथ रक्षात्मक सुरक्षा की दिशा में अंतरराष्ट्रीय पहल शुरू होने से पहले तक पारंपरिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान को कोई भी विशिष्ट कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। ये मुख्यतः आईपीआर के उपयोग के जरिए औषधियों के पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते थे। स्वयं भारत ने इन प्रणालियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आईपी कानूनों में तब तक कोई विशेष प्रावधान नहीं किया, जब तक पारंपरिक ज्ञान से आईपीआर प्राप्त करने को रोकने के लिए विधायी संशोधनों को अंजाम नहीं दिया गया। आरआईएस ने अतीत में आईपीआर, जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान प्रणालियों के परस्पर संबंधों पर आधारित समृद्ध साहित्य तैयार किया था। पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र की तुलना में वर्तमान आईपीआर व्यवस्था की पड़ताल के व्यापक अधि ादेश के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2022 में भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों (टीएसआईएम) के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआरएस) संरक्षण को सक्षम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में आरआईएस संकाय शामिल है। इस अधिदेश के तहत लाया गया चर्चा पत्र पारंपरिक चिकित्सा, विशेषकर आयुर्वेद जैसी भारतीय प्रणालियों के लिए आईपी सुरक्षा की वर्तमान स्थिति; इन प्रणालियों में नवाचार के मुद्दे, और टीएम को पेटेंट कराने में चुनौतियों और जोखिमों की पड़ताल करता है। यह एक ऐसे उद्योग में सकारात्मक सुरक्षा की दलील देता है, जहां अनुसंधान का उद्देश्य नए सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (एपीआई) की खोज या विकास करना नहीं है। यह पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतों पर केस अध्ययनों के साथ भारतीय आईपी कानूनों और नीतियों में प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। अंततः यह क्षेत्र में नवाचारों और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आईपीआर की प्रासंगिकता के संबंध में विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पारंपरिक चिकित्सा के द्वारा एसडीजी–3 के लक्ष्य हासिल करना

एसडीजी–3 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आठ साल से भी कम समय बचे होने के कारण स्वास्थ्य देखरेख संबंधी रणनीतियों में सरलता और नवाचार का वैश्विक आह्वान किया गया है। इसमें एक–आयामी दृष्टिकोण

से परे देखना शामिल है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के रामबाण के रूप में केवल आधुनिक दवाओं को ही प्राथमिकता देता है। दुनिया अब पारंपरिक चिकित्सा पर गौर करने लगी है और नैदानिक अनुसंधान का उन्नतिशील समूह इसकी वैधता में सहायता कर रहा है। संचारी रोगों से मृत्यु दर में कमी, मातृ, प्रसवपूर्व और पोषण स्थितियों और गैर संचारी रोगों के उभरते बोझ ने स्थायी कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा के निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार किया है। इस पृष्ठभूमि में एफआईटीएम ने 15 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात के भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) में ''एसडीजी–3 हासिल करना : एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य देखरेख में पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) को मुख्यधारा में लाने पर केन्द्र बिंदु सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की भूमिका' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस पैनल में डॉ. गीता कृष्णन; तकनीकी अधिकारी पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (टीसीआईएम) इकाई, डब्ल्यूएचओ, जिनेवा; डॉ. नितिन अग्रवाल, एमडी, ब्लिस आयुर्वेद, नई दिल्ली; प्रोफेसर अर्पण भट्ट, प्रोफेसर और एचओडी स्वास्थ्यवृत्त और योग, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर, गुजरात; डॉ. नम्रता पाठक, पीएचडी, सदस्य सचिव, एफआईटीएम और सलाहकार, आरआईएस, प्रोफेसर एस.एस. मोदी, ईडीआईआई, गांधीनगर, गुजरात; और वैद्य काशीनाथ समागंडी, सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर ने भाग लिया। यह चर्चा साक्ष्य आधारित नैदानिक प्रोटोकॉल, डेटा जेनरेशन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (यूएचसी) में पारंपरिक चिकित्सा को पुख्ता रूप से शामिल करने संबंधी रणनीतियों पर केंद्रित थी। अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियों में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए सैल्यूटोजेनिक दृष्टिकोण के पक्ष में दलील और गैर संचारी रोगों (एनसीडी) पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, क्योंकि इसका किसी परिवार के खर्च के वित्तीय पहलुओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

जी–20 में पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण

भारत की जी–20 की अध्यक्षता के अंतर्गत कल्याण की भूमिका की प्रबल रूप से वकालत की जा रही है। समकालीन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां, संकीर्ण महामारी विज्ञान पर केन्द्र बिंदु की तुलना में उत्तरोत्तर रूप से पारंपरिक पूरक और वैकल्पिक हर्बल दवाओं से प्राप्त टिकाऊ स्वास्थ्य रणनीति के रूप में कल्याण पर आधारित समग्र दृष्टिकोण की मांग कर रही हैं। आरआईएस की अध्यक्षता में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली (लाइफ), लचीलेपन और कल्याण के लिए नैतिक मूल्यों से संबंधित टी–20 का टास्क फोर्स 3 इस परिप्रेक्ष्य को केन्द्र बिंदु में लाने का प्रयास करता है। एफआईटीएम संबंधित कार्यक्रमों में अनुसंधान और संकाय भागीदारी के माध्यम से इस प्रस्ताव में योगदान दे रहा है। आरआईएस द्वारा भोपाल में 16–17 जनवरी 2023 को विशेष थिंक–20 कार्यक्रम के तहत आयोजित समानांतर सत्रों में से एक, *'वन हेल्थ, वेलनेस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन'* की अध्यक्षता प्रोफेसर टी.सी.जेम्स ने की। पैनल ने वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे अत्यावश्यक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें देश वाहकों, पशु, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ संपर्क की जटिलता के बावजूद, वन हैल्थ के सिद्धांतों के आधार पर बहु–क्षेत्रीय, सहयोगपूर्ण, अंतरविषयक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं। वन हेल्थ फ्रेमवर्क में अपनाए जाने की स्थिति में पारंपरिक हर्बल दवाओं का प्रदर्शित प्रभाव रणनीतिक रूप से बदलावकारी हो सकता है। इस आयोजन के बाद जारी किए गए भोपाल घोषणापत्र में इस बात को रेखांकित किया गया कि अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में से विशेष रूप से आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (आयुष) जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण का मजबूत स्तंभ बन सकती हैं। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर जी–20 फोरम शुरू करने तथा आयुष और सभी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर आधारित वैश्विक उद्योगों को आगे ले जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस घोषणापत्र में सदस्य देशों और अन्य स्थानों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत बनाने के लिए सहकार्य और सहयोग के लिए

जी–20 द्वारा फोरम ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफटीएम) का गठन करने प्रस्ताव रखा गया।

एक अन्य टी–20 साइड इवेंट *'जी–20 और एसडीजी के परस्पर संबंध : चुनौतियां, समाधान और आगे की राह'* का आयोजन प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (एमएएचई), मणिपाल द्वारा टी–20 सचिवालय, ओआरएफ और आरआईएस के सहयोग से 20–21 मार्च, 2023 को किया गया। ''वैश्विक कल्याण एजेंडे पर भारत के विचार और परिप्रेक्ष्य'' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. नम्रता पाठक की भागीदारी रही।

पारंपरिक चिकित्सा को जी–20 चर्चाओं में आगे बढ़ाने में आयुष मंत्रालय की सहायता के लिए एफआईटीएम ने जी–20 आयोजनों में व्यापक प्रसार के लिए *'पारंपरिक चिकित्सा पर जी–20 प्रवेशिका'* भी निकाली। इस प्रवेशिका में वन हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी), साक्ष्य आधारित निवारक दवाओं, योग अनुसंधान एवं विकास और आयुष स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ जी–20 के लिए पारंपरिक चिकित्सा की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया।

भारत की वन हेल्थ की रूपरेखा में आयुष

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वन हेल्थ की रूपरेखा का मूलभूत पहलू, पशुजन्य और एएमआर पर नियंत्रण रहा है, हालांकि भारत में मनुष्यों, पशुओं, मवेशियों और पर्यावरण के लिए स्थायी पारंपरिक पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य प्रथाओं से लाभ उठाने की दिशा में प्रत्यक्ष प्रयास बहुत कम किए गए हैं। यह प्रासंगिक इसलिए हो जाता है, क्योंकि कई देशों के विपरीत, भारत में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा प्रणालियों का एक समृद्ध चलन रहा है, जो सदियों से मानव और पशु स्वास्थ्य को संतुलित करता आ रहा है। एफआईटीएम नीतिगत सारांश 'इंडियाज वन हेल्थ फ्रेमवर्क : हार्नेसिंग इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन' भारत की वन हैल्थ रणनीति में आयुष प्रणालियों की प्रासंगिकता को सामने लाता है।

सॉफ्ट पावर रणनीतियों के रूप में आयुर्वेद और योग

आयुर्वेद और योग आज दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। सॉफ्ट पावर के साधनों के रूप में भारत के लिए इन प्रणालियों की क्षमता को अधिकतम बनाने के लिए उन्हें सावधानी से रणनीतिक रूप से स्थापित करने की जरूरत होगी। एफआईटीएम नीतिगत सारांश 'हील बाय इंडिया, हील इन इंडियाः आयुर्वेद एंड योगा ऐज सॉफ्ट पावर टूल्स' उत्पादों और सेवाओं, कनेक्टिविटी और चिकित्सा मूल्य यात्रा मानदंडों में गुणवत्ता संबंधी आश्वासन को मजबूत करके आयुर्वेद और योग के उपयोग के लिए उपलब्ध नीतिगत विकल्पों को रेखांकित करता है। यह स्वास्थ्य सेवा व्यापार में एकीकृत, समग्र और किफायती स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के रूप में 'हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया' पहल के रणनीतिक उपयोग की सिफारिश करता है।

एफआईटीएम की पत्रिका ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू

एफआईटीएम की छमाही पत्रिका ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू के दो अंक अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2022 में प्रकाशित हुए। इनमें सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के सदस्यों जैसे प्रोफेसर ऋतुप्रिया मेहरोत्रा, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जेएनयू, पी. एन. रंजीत कुमार, उप महानिदेशक, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार (पूर्व संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय) और डॉ. हरिलाल माधवन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के योगदान से प्रासंगिक विषयों को शामिल किया गया। इन पत्रिकाओं में कवर किए गए कुछ महत्वपूर्ण विषयों में शब्दावली के मानकीकरण के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का ग्लोबल गवर्नेंस, पारंपरिक चिकित्सा के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग, पारंपरिक दवाओं के साथ सार्वभौमिक और प्राथमिक

स्वास्थ्य देखभाल, आयुष में गुणवत्ता के आश्वासन के लिए स्वैच्छिक प्रमाणनों और प्रत्यायनों की भूमिका शामिल है।

मूल निवासी और भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विमर्श

जैव विविधता, औषधीय पौधों का प्रमुख स्रोत है, जो कि पारंपरिक चिकित्सा का प्रमुख कच्चा माल हैं। स्थानीय समुदाय लंबे अर्से से जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े औषधीय ज्ञान के संरक्षक रहे हैं। इन समुदायों तक पहुंच, उनके साथ लाभ साझा करने तथा अधिकारों एवं स्वामित्व के बारे में उनकी स्थिति जैसे मुद्दों पर लंबे अर्से से वैश्विक स्तर पर बहस होती रही है। मानवाधिकारों पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं ने ऐसे लोगों को संदर्भित करने संबंधी शब्दों की उपयुक्तता पर सवाल उठाए हैं, चाहे वह ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से ही क्यों हो। 'मूल निवासी' शब्द का उचित उपयोग और यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों और विकास की कानूनी धारणाओं को कैसे आकार देता है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर टी.सी. जेम्स के शोध पत्र 'इंटरनेशनल डिस्कशन्स ऑन इंडिजनस पीपुल एंड इंडिया' का स्पेनिश, उड़िया, मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है।

जारी अनुसंधान

निकट भविष्य में पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में वृद्धि दिखाई दे रही है। एफआईटीएम पारंपरिक चिकित्सा में सार्क क्षेत्रीय सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा पर भारत–अफ्रीका सहयोग की रूपरेखा, औषधीय पौधों के क्षेत्र और आयुष एमएसएमई पर महत्वपूर्ण अनुसंधान आउटपुट लाने की दिशा में काम कर रहा है। ■

प्रमुख कार्यक्रम

- आरआईएस में फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) ने 15 अक्टूबर 2022 को 'एसडीजी 3 प्राप्त करनाः पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की भूमिका' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।
- आरआईएस ने 23 नवंबर 2022 को "जी–20 वेलबीइंग मेट्रिक्स के लिए विकल्पों की तलाश करना" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया।
- टी–20 टास्क फोर्स 3 सेमिनार श्रृंखला के अंतर्गत दूसरा सत्र 31 मार्च 2023 को "सतत उपभोग और उत्पादन, जलवायु संकट और वन हेल्थ" विषय पर आयोजित किया गया।
- थिंक–20 (टी–20) सहभागिता समूह के तहत भारत ने पर्यावरण सम्मत जीवन शैली (लाइफ), लचीलापन और सुख–समृद्धि के लिए मूल्य की शुरुआत की। लाइफ की अवधारणा और इसके विभिन्न पहलुओं को प्रसारित करने के प्रयासों के तहत, आरआईएस ने 24 मार्च 2023 से 5 मई 2023 (प्रत्येक शुक्रवार) तक एक वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ की।

प्रकाशन

परिचर्चा पत्र

- पारंपरिक चिकित्सा और बौद्धिक संपदा अधिकार कानून और नीति परिप्रेक्ष्य द्वारा टी. सी. जेम्स

नीति संक्षेप

- भारत का एक स्वास्थ्य ढांचा: भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग, द्वारा नम्रता पाठक
- हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया: प्रोफेसर द्वारा सॉफ्ट पावर टूल्स के रूप में आयुर्वेद और योग
- द्वारा टी. सी. जेम्स

पत्रिकाएं

- पारंपरिक चिकित्सा समीक्षा, खंड 2, क्रमांक 2, अक्टूबर 2022
- पारंपरिक चिकित्सा समीक्षा, खंड 1, क्रमांक 2, अप्रैल 2023

अध्याय VII

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और मानव पूंजी के लिए बच्चों में निवेश

भारत ने अपनी जी–20 की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ता से बदलाव लाते हुए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विकास के ऐसे परिवर्तित दृष्टिकोण पर जोर देने का आह्वान किया है, जो विकास में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करता हो। महिलाओं के आर्थिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने पर ही महिला–पुरुष समानता हासिल की जा सकती है, क्योंकि महिलाएं विकास और प्रगति के केंद्र में हैं और वे केवल लाभार्थी मात्र नहीं हैं, बल्कि उसकी प्रक्रिया को संचालित करती हैं। वित्तीय और डिजिटल समावेशन के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण के जरिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका सशक्तिकरण और प्रभावी प्रतिनिधित्व भारत की जी–20 की अध्यक्षता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

इस संदर्भ में, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो नवाचार बढ़ाते हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं, नौकरियों का सृजन करते हैं, उत्पादकता और वेतन में सुधार लाते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं तथा महिलाओं और कुल मिलाकर उनके परिवारों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाकर उसे बेहतर बनाते हैं। वर्ष 2012 के बाद से, जी–20 शिखर सम्मेलनों ने लगातार – सभी प्रकार के भेदभाव और जेंडर पर आधारित हिंसा को समाप्त करते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण; महिला किसानों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार; व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच; कामकाज की समुचित परिस्थितियों के साथ श्रम बल बाजार तक पहुंच और श्रम बल भागीदारी में महिला–पुरुष के अंतर को कम करने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

जी–20 की पिछली कुछ अध्यक्षताओं के दौरान, महिलाओं का सशक्तिकरण भी जी–20 के एजेंडे के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुमार रहा है। जैसा कि अमूमन होता

है, श्रम भागीदारी और समुचित नौकरियों तक पहुंच के मामले में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि पिछली चार जी–20 अध्यक्षताओं के विश्लेषण में पाया गया कि 2018 में अर्जेंटीना को छोड़कर महिला सशक्तिकरण के लिए कोई अलग टास्क फोर्स की थीम नहीं है। विभिन्न देशों की अध्यक्षता के दौरान विविध टास्क फोर्स मुख्य रूप से सामाजिक एकजुटता, वैश्विक शासन व्यवस्था और कल्याण प्रणालियों के भविष्य के मुद्दों से संबंधित रहे, जिन्होंने आंशिक रूप से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को भी छूआ।

अनुवर्ती जी–20 घोषणापत्रों में, जी–20 देशों द्वारा महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गईं। हालांकि, महिला संगठनों, महिला उद्यमियों और थिंक–टैंक के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क डब्ल्यू–20, (वीमन–20) सहभागिता समूह के साथ वी–फाई (महिला उद्यमी वित्तपोषण पहल) महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाली जी–20 की दो सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से हैं। डब्ल्यू–20 का गठन 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के अंतर्गत संयोग से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाने के साथ किया गया था, जब विश्व नेताओं ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में एसडीजी के लिए 2030 के एजेंडे के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। वास्तव में, एसडीजी के लक्ष्य–5 से संबंधित महिला–पुरुष समानता को एसडीजी के सभी 17 लक्ष्यों में महत्वपूर्ण और सभी को प्रभावित करने वाला मुद्दा माना गया है।

जी–20 देशों में महिला एसएमई की स्थिति

कोविड–19 महामारी के दौरान, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष तौर पर सेवा, खुदरा व्यापार और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों को, जहां मुख्यतः महिलाओं की बहुलता होती है, वहां उद्यमों के बंद होने और नौकरी छूटने के कारण पुरुषों की तुलना में ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा। इस बात पर भी गौर किया गया कि महिला उद्यमिता में महिला–पुरुष के अंतर को कम करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, इसके लिए महिला उद्यमियों को लॉकडाउन के दौरान पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए उपायों का समर्थन करने की सख्त जरूरत है।

हालांकि, उसी दौरान महामारी ने महिला उद्यमियों के लिए तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए अवसरों का भी सृजन किया, जिन्होंने उन्हें नई साझेदारियां कायम करने तथा यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों पर काबू पाते हुए नए ग्राहकों को लक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित किया। नई अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता के साथ अनेक महिला व्यवसायियों ने उभरते क्षेत्रीय अवसरों का लाभ उठाने के लिए, नए व्यवसाय मॉडल अपनाकर और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके कोविड –19 महामारी का प्रभावी रूप से मुकाबला किया।

वभिन्न साहित्यों में यह अनुभव किया और बताया गया कि महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबारों का काफी बड़ा हिस्सा, कम आय वाले देशों में आवश्यकता के कारण स्थापित होता है। जबकि उच्च आय वाले देशों में, महिला उद्यमिता का बड़ा हिस्सा अवसरों से प्रेरित होता है।

इसके अलावा, ऑनलाइन व्यवसाय के प्रभावी और सफल संचालन में समस्याएं उत्पन्न करने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं में डिजिटल साक्षरता कौशल, डिजिटल वित्तीय कौशल, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का ज्ञान, साइबर सुरक्षा साक्षरता आदि शामिल थीं। बैंकों में गिरवी रखने के लिए किसी भूमि का स्वामित्व न होना, घर या अन्य अचल संपत्तियों की स्वामी न होना, पारिवारिक समर्थन का अभाव होना आदि जैसे कारणों ने महिलाओं को प्रतिस्पर्धी दुनिया में संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया। महिलाओं को अपने कारोबारी उद्यमों की स्थापना करने या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने के लिए, व्यापक कागजी कार्रवाई, जटिल शब्दावली, बैंकों के संचालन के विषम घंटे, गारंटीकर्ता सहित आवेदन के साथ दस्तावेज जमा करना कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं, जिनका उन्हें अक्सर सामना करना पड़ता है।

इन बाध्यताओं के बावजूद, विकासशील देशों की अनेक महिला उद्यमियों ने न केवल पहल की, बल्कि कोविड–19 महामारी के बीच उभरते अवसरों का सक्रियता से उपयोग भी किया। कोविड–19 के कारण डिजिटल तकनीक पर बढ़ती निर्भरता ने विशेष तौर पर ,उभरते वातावरण में तालमेल बिठाने के लिए जद्दोजहद कर रही महिला उद्यमियों को प्रभावी सहायता देने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। हालांकि हालात ने संबंधित सरकारों, निजी क्षेत्र और

सिविल सोसाइटी को डिजिटल समावेशन, पहुंच और जेंडर डिजिटल भेद को पाटने के प्रयासों पर अतिरिक्त जोर देने का अवसर भी दिया।

भारत के जी–20 के एजेंडे के केंद्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता है। इसका अनुसरण करते हुए आरआईएस ने टी–20, यू–20, मध्य प्रदेश सरकार, संबद्ध थिंक टैंक, यूनिसेफ, जीआईजेड, बीएमजीएफ और आरआईएस के जीडीसी के सहयोग से जनवरी 2023 में विशेष टी–20 कार्यक्रम *'पर्यावरण सम्मत जीवन शैली (लाइफ)–नैतिक मूल्य तथा सुमंगलयुक्त वैश्विक सुशासनः संरचना, वित्त और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग का संचार'* का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, अन्य के अलावा, *'महिला और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास' और 'बच्चों में निवेश : भविष्य में निवेश'* पर दो अलग–अलग सत्र आयोजित किए गए। इनका आयोजन समाज और अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की क्षमता वाले समावेशी विकास के लिए संभावनाओं से भरपूर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर समृद्ध और व्यापक विचार–विमर्श करने के लिए किया गया था। इस बात पर बल दिया गया कि जी–20 को विशेषज्ञता साझा करने को सुगम बनाने और वित्तीय समावेशन के लिए सफलता की कहानियों को दोहराने, आय–सृजित करने वाली गतिविधियों के माध्यम से स्व–रोजगार, महिला उद्यमिता, स्कूलों में अधिक संख्या में लड़कियों का दाखिला कराने और विकासशील देशों में खेल, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे विभिन्न उत्कृष्ट क्षेत्रों में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

'बच्चों में निवेश : भविष्य में निवेश' विषय पर आरआईएस–यूनिसेफ के साझा पैनल ने जी–20 के लिए अनेक राष्ट्रीय और आंतरिक विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों, मातृत्व लाभ और बच्चे की देखरेख से जुड़े क्रमिक सार्वभौमिक लाभों को प्राथमिकता देने वाली बाल–केंद्रित नीतियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत कीं। साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में निवेश संज्ञानात्मक पूंजी को बढ़ावा दे सकता है, जिसकी बदौलत उच्चतम और अधिक समावेशी आर्थिक विकास संभव हो सकता है। बच्चों में निवेश को वह प्राथमिकता और केन्द्र बिंदु नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए था और इसलिए टी–20 प्रक्रिया में बच्चों के विशिष्ट मुद्दों को प्राथमिकता दी गई थी, ताकि पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे व्यापक जी–20 को विमर्श को अवगत कराया जा सके।

टी–20 कोर समूह के अंग के रूप में आरआईएस ने यूनिसेफ के साथ संयुक्त रूप से *'इन्वेस्टिंग इन अर्ली ईयर्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर फ्यूचर रेजिलिएंस : फॉर ऐन इंक्लूसिव एंड इक्विटस वर्ल्ड'* विषय पर विशेष प्रकाशन लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह खंड भविष्य के आर्थिक विकास के लिए दुनिया के हर क्षेत्र में बाल विकास को अनुकूलित करने के लिए बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निवेश करने की नितांत आवश्यकता पर केंद्रित है। यह प्रस्तावित करता है कि भविष्य के लचीलेपन में निवेश, वर्तमान बाल समूहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उच्च मानव पूंजी से सुसज्जित अगली पीढ़ी के बाल समूहों तक फैला हुआ है; इस प्रकार आज के बच्चे अपने जीवनकाल के दौरान अपनी भावी पीढ़ियों की समृद्धि और लचीलेपन को आकार दे सकते हैं। समावेशितापूर्ण मानव–केंद्रित विकास के लिए, पुस्तक महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करती है, चाहे वह जेंडर और बाल बजटिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, प्रवासन के प्रभाव, आईटी की भूमिका, मानव पूंजी में सुधार के लिए ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आदि ही क्यों न हो।

इसके अलावा, टास्क फोर्स 6 (टीएफ–6)/टी–20 (जेंडर के प्रति संवेदनशील एसडीजी में तेजी लाना),के तत्वावधान में जी–20/टी–20 के भाग के रूप में आरआईएस, भारत में संयुक्त राष्ट्र, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट (एडीबीआई) और सेवा भारत ने मार्च, 2023 को टी–20 साइड इवेंट 'आर्थिक विकास की सक्रिय भागीदार और प्रेरक के रूप में महिलाएंः आजीविका और देखभाल के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना' विषय पर एक दिवसीय पैनल चर्चा का आयोजन किया। विचार–विमर्श के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि लक्षित हस्तक्षेपों और प्रगति की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर, नियमित और अलग–अलग जेंडर डेटा की आवश्यकता है। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यम ज्यादातर नैनो–आकार के होते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक का सालाना कारोबार 12,000 डॉलर से कम होता है। इसलिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित महिला उद्यम विकास कोष की

तालिका 1: उद्यमों के वितरण का प्रतिशत (पुरुष/महिला एवं उद्यमियों के अनुसार) (2015–16)

सेक्टर	पुरुष	महिला	सभी
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
सभी	79.63	20.37	100
श्रेणी			
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100
सभी	79.63	20.37	100

स्रोतः एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, 2022–23

आवश्यकता बताई गई। इस बात को भी रेखांकित किया गया कि देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण को जी–20 नेताओं के एजेंडे में प्राथमिकता बनाने की जरूरत है, जिसके बगैर महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास टिकाऊ और वास्तविक लक्ष्य नहीं होगा। आईसीडीएस जैसे कार्यक्रमों को अद्यतन करते हुए उनका विस्तार करना चाहिए, ताकि उन्हें क्रेच बनाया जा सके। डिजिटल समावेशन के संबंध में, यह स्वीकार किया गया है कि महिलाओं को डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और एआई के उपयोग के संबंध में शिक्षित करने की आवश्यकता है। महिलाओं को डिजिटल अवसंरचना तक बेहतर पहुंच और उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए 'डिजिटल सखी' जैसे मध्यवर्ती संस्थाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहिए।

भारत की स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पुरुष प्रधान उद्यम व्यापक रूप से प्रचलित हैं। यह भी पता चलता है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों में (18.42 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक (22.24 प्रतिशत) है। (तालिका –1)

महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत की जी–20 की अध्यक्षता के मुख्य विषयों में से एक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और महिला–पुरुष अंतर को कम करना सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के मुख्य वाहकों में से एक है। अनुसंधान ने दर्शाया है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो इसका उनके बच्चों, घरों और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। महिलाएं जब काम करती हैं, तो अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं – इससे उत्पादकता बढ़ती है, आर्थिक विविधता और आय समानता बढ़ती है। उन्हें आर्थिक रूप से पूर्णतया और सही मायने में सशक्त बनाने के लिए विश्व को रोजगार या उद्यमिता के माध्यम से उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। ■

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- यूएनईएससीएपी–एपीसीटीटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चीन और गुआंगज़ो विश्वविद्यालय द्वारा 30 जून 2022 को 4आईआर प्रौद्योगिकियों के नवाचार, हस्तांतरण और प्रसार विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में '4आईआर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और उन्हें अपनाने की रणनीतियों और व्यापार मॉडल को सक्षम बनाना' पर प्रस्तुति दी।
- कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा 27 जून 2022 को भारत की भागीदारी और निष्कर्ष; जलवायु के मुद्दों में समानता का प्रश्न और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना तथा जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले भारत की भागीदारी की प्रासंगिकता पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया।
- आईसीडब्ल्यूए द्वारा 15 जून 2022 को भारत की विकास साझेदारीः विस्तारशील परिदृश्य विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत की विकास भागीदारी' पर प्रस्तुति दी।
- मुंबई में आईजीआईडीआर द्वारा 14 जून 2022 को आयोजित 21वें आईएएसएसआई वार्षिक सम्मेलन में 'इंडियन सोशल साइंस रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी–थिंक टैंक कनेक्ट : द वे फॉरवर्ड' पर तरलोक सिंह स्मृति व्याख्यान दिया।
- इंडिया राइट्स नेटवर्कय इंडिया एंड द वर्ल्ड पत्रिका द्वारा सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स (सीजीआईआई) के सहयोग से 9 जून 2022 को आयोजित 'द क्वाड वे : ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड' पर वेबिनार को संबोधित किया।
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 7 जून 2022 को 'स्वास्थ्य और विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचार – भारत के डिजिटल सार्वजनिक सामान दुनिया को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं' विषय पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा द्वारा 5 जून 2022 को 3एस इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आयोजित "स्वदेशी, आत्म–निर्भर एंड सस्टेनाबिलिटीः कंवर्जेंसेज एंड वे फॉरवर्ड" पर प्रमुख भाषण दिया।
- आईएलआर स्कूल ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और जीआरएएएम द्वारा 28 मई 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित 3पीई–पब्लिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम इवेल्यूएशन कार्यशाला के चौथे संस्करण के दौरान "बड़े पैमाने की सरकारी परियोजनाओं की निगरानी" पर विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता की।
- जी–20 की संरचना के भीतर तथा इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय, डी20 और टी20 तथा बी20 के आधिकारिक संबद्ध समूहों के सहयोग से 24 मई 2022 को बर्लिन में आयोजित वर्चुअल सेमिनार में बुनियादी ढांचे में भावी निवेश के बारे में साझा दृष्टिकोण का निर्माणः टी 20, बी 20, डी 20 का योगदान से संबंधित सत्र में 'बहाली और सुरक्षित, सतत भविष्य के लिए बलों के साथ जुड़ना : जी–20 में उच्च प्रभाव वाली सतत ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बहुपक्षीय रोडमैप का आकलन करना' विषय पर चर्चा में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव और डीआईई द्वारा 23 मई 2022, को बर्लिन में आयोजित 'थिंक 7 समिट : प्रतिस्पर्धी भू–राजनीतिक वातावरण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना' में 'नए भू–राजनीतिक वातावरण में जी–7 की भूमिका' पर विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
- ग्लोबल पार्टनशिप इनिशिएटिव ऑन इफैक्टिव ट्राइएंगुलर को–ऑपरेशन (जीपीआई) की ओर से 23 मई 2022 को बर्लिन में ट्राइएंगुलर को–ऑपरेशन विद् एशियाः स्टेप्स फ्रॉम पोलिटिकल सपोर्ट टू प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन' विषय पर अनौपचारिक रणनीतिक विचार–विमर्श में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव और डीआईई द्वारा 23 मई 2022, को बर्लिन में आयोजित 'थिंक 7 समिट : प्रतिस्पर्धी भू–राजनीतिक वातावरण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना' में ' जी–7 को जी–20 के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना

चाहिएघ' पर विषय पर पूर्ण अधिवेशन में पैनल चर्चा में भाग लिया।

- समान विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रिक्स के लिए बौद्धिक समर्थन को सुदृढ़ करना थीम पर आयोजित 14वें ब्रिक्स एकेडेमिक फोरम 2022 में चाइना काउंसिल फॉर ब्रिक्स थिंक टैंक कोऑपरेशन द्वारा 20 मई 2022 को 'वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करना और वैश्विक आर्थिक शासन प्रणाली में सुधार लाना' विषय पर आयोजित सत्र में भाषण दिया।
- सीपीसी केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग, चाइना काउंसिल फॉर ब्रिक्स थिंक टैंक और चाइना एनजीओ नेटवर्क फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से 19 मई 2022 को आयोजित किए गए ब्रिक्स राजनीतिक दलों, थिंक टैंक और सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन फोरम ऑन सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन टुअर्ड्स कॉमन डेवलपमेंट और ब्राइटर फ्यूचर के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया।
- सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज के समन्वय से वाणिज्य विभाग द्वारा 18 मई 2022 को आयोजित एमसी–12 की तैयारी में डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर परामर्श बैठक में भाग लिया।
- आईसीएसएसआर द्वारा 15 मई 2022 को आयोजित "अर्थशास्त्र को समझने की चुनौतियां" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत की विकास संभावनाओं पर एक सत्र में भाषण दिया।
- स्पेशल इवेंट 3 में पैनलिस्टः साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (एसटीआई फोरम) द्वारा इंटर एजेंसी टास्क टीम ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर एसडीजी (आईएटीटी) के सहयोग से 6 मई 2022 को आयोजित किए गए ''सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) से रिकवरी के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार'' पर एसडीजी के लिए एसटीआई पर सातवें वार्षिक बहु–हितधारक फोरम में राष्ट्रीय क्षमताओं और पार्टनरशिप इन एक्शन फॉर एसटीआई4एसडीजी रोडमैप का समर्थन।
- "एसटी की कानूनी स्थिति; उनकी पहचान और भविष्य" पर ग्लोबल आस्पेक्ट ऑफ द नेशनल विमर्श के चौथे सत्र में 1 मई 2022 को 'भारत को आदिवासी लोगों की बहस पर अत्यावश्यकता के साथ क्यों गौर करना चाहिए' विषय पर विशेष भाषण दिया।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए), भोपाल और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा 28–29 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश पीएचडी कोलोक्वियम, 2022 में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और अनुसंधान डिजाइन की रणनीतियों पर सत्र की अध्यक्षता की।
- श्री बालाजी विद्यापीठ, एबीएलई और स्टीमसन द्व ारा संयुक्त रूप से 26 अप्रैल, 2022 को बेंगलुरु में 'सुरक्षित व्यापार और जैव प्रौद्योगिकी का हस्तांतरणः भारत में विनियम और अच्छी पद्धतियां' विषय पर आयोजित कार्यशाला में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के व्यापार, निवेश और नवाचार की दिशा के बारे में प्रस्तुति दी।
- ग्रेटर नोएडा में 23 अप्रैल 2022 को शारदा यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन (यूपीयूईए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 17वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में आजादी के 75 वर्ष पर शिक्षा और अर्थशास्त्र के शिक्षण में व्यापार को कैसे एकीकृत किया जाए पर प्रस्तुति दी।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल 2022 को गांधीनगर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में विचार–विमर्श से सहयोग तक : सरकार और उद्योग पर गोलमेज 3 में प्रस्तुति दी।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल 2022 को गांधीनगर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में विश्व के लिए भारतीय आयुष संभावनाओं पर गोलमेज 2 में प्रस्तुति दी।
- क्षेत्रीय प्रौद्योगिकीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी) द्वारा भारत की एसटीआई एजेंसियों और एपीसीटीटी के बीच 19 अप्रैल 2022 को आयोजित विचार–विमर्श सत्र में भाग लिया।
- दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से 15 अप्रैल 2022 चित्रकूट में आयोजित 'सतत विकास लक्ष्यों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में 'एसडीजी' पर व्याख्यान दिया।
- भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा 13 अप्रैल 2022 को आयोजित भारत–चीन व्यापार घाटा और

उभरते व्यापार आख्यान विषय पर एक सत्र में भारत चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार आख्यान पर प्रस्तुति दी।

- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए), भोपाल और प्रिया, नई दिल्ली द्वारा 8–9 अप्रैल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित सतत विकास के लिए साझेदारी और अनुभव साझा करने के लिए सीएसओ के साथ सम्मेलन' के दौरान उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और 'विकास संचार और लेखन' पर सत्र तथा 'सतत विकास के लिए साझेदारी और अनुभव साझा करनाः सीएसओ के साथ सम्मेलन' पर भी सत्र को संबोधित किया।
- संसद टीवी पर डिप्लोमैटिक डिस्पैच पर साप्ताहिक कार्यक्रम में 6 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री देउबा की यात्रा के संदर्भ में संबंधों के आर्थिक आयामों पर भारत–नेपाल संबंधों पर रिकॉर्डिंग।
- नीति आयोग द्वारा 11 जुलाई 2022 को 'बिहाइंड द कर्वः व्हॉट द ग्लोबल एक्सपीरियंस टेल्स अस अबाउट मैन्यूफेक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट'' विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के प्रोफेसर रॉबर्ट जेड लॉरेंस, अल्बर्ट एल विलियम्स के साथ भाग लिया।
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्व ारा 12 जुलाई 2022 को 'बदलते वैश्विक वातावरण में ब्रिटेन–भारत व्यापार और सीमा पार निवेश का भविष्य' विषय पर आयोजित कार्यशाला में 'फिनटेक और फिनटेक–सक्षम सेवाओं में व्यापार : उभरते रुझान और वृद्धि की संभावनाएं' पर प्रस्तुति दी।
- फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी ऑफ इंडोनेशिया(एफपीसीआई) द्वारा 14 जुलाई 2022 को 'जी–7ः इसकी रणनीतिक दिशा और विश्व के लिए इसके मायनों को समझना' विषय पर आयोजित पब्लिक फोरम में पैनलिस्ट।
- आईएफपीआरआई ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 जारी किए जाने और और दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर पॉलिसी फोरम के दौरान आईएफपीआरआई द्वारा 21 जुलाई 2022 को 'जलवायु परिवर्तन और भारत में खाद्य प्रणालियों के संबंध में परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 27 जुलाई 2022 को इसरो द्वारा आयोजित आईआईसी हीरक जयंती विज्ञान प्रदर्शनी में 'भारत में न्यूस्पेस के लिए संभावनाएं और रास्ते' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट।
- नीति आयोग द्वारा 'रिफॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्डर : व्हॉट शुड इमर्जिंग मार्केट्स बी सीकिंग' विषय पर 3 अगस्त 2022 को आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में पैनलिस्ट।
- भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा 08 अगस्त 2022 को 'ळ20/2023 – द रोड मैप टू इंडियन प्रेसीडेंसी' पर आयोजित चर्चा के दौरान भाषण दिया।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त 2022 को जी–20 और एससीओ के बारे में माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक संक्षिप्त बैठक में 'जी–20 और एससीओ' पर प्रस्तुति दी।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 17 अगस्त 2022 को आयोजित मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की जी–20 बैठक (एमएसीएस) में जानकारी प्रदान की।
- 20 अगस्त 2022 को आयोजित मध्य प्रदेश प्रथम कॉन्क्लेव में "मध्य प्रदेश को 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की राह में चुनौतियां" विषय पर प्रस्तुति दी।
- जीआईजेड इंडिया की परियोजना सी–एसएएसए और नाबार्ड द्वारा 25 अगस्त 2022 को आयोजित विश्व जल सप्ताह 2022 में एशिया में सतत कृषि और जलीय कृषि के लिए भागीदारी जल प्रबंधन पर सत्र में पैनलिस्ट।
- यूएनआईडीओ और यूएनईएससीएपी द्वारा 30 अगस्त 2022 को संयुक्त रूप से यूएनआईडीओ की औद्योगिक विकास रिपोर्ट 2022 "द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीलाइजेशन इन अ पोस्ट–पेंडेमिक वर्ल्ड''' के एशिया के लिए क्षेत्रीय लॉन्च के अवसर पर पैनलिस्ट।
- आईपीएजी एशिया प्रशांत, ऑस्ट्रेलियाई सूचना सुरक्षा संघ (एआईएसए) और एससीआईसीसी द्वारा संयुक्त रूप से 4 सितंबर 2022 को बाली में आयोजित जी–20 एंड एआई : कनेक्टिंग द डॉटेड लाइन्स बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमेनिटी' में टी–20 के एक साइड इवेंट में 'एआई गवर्नेंस एंड इथिक्स–द रोल ऑफ द जी–20 कम्युनिटी' पर सत्र का संचालन किया।
- बाली में 5 सितंबर 2022 को टी–20 इंडोनेशिया शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान आरआईएस द्वारा ईआरआईए और टी–20 इंडोनेशिया के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित ' लॉन्च ऑफ जी–20 रिसर्च

फोरम : टूअर्ड्स मल्टी–डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स ऑन जी–20 डेवलेपमेंट एजेंडा' पर विशेष सत्र की अध्यक्षता की।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में आयोजित 'केंद्र–राज्य विज्ञान सम्मेलन के दौरान राज्यों में 'राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- पॉट्सडैम में 13 सितंबर 2022 को जीआईजेड द्वारा आयोजित जीआईजेड फ्यूचर फोरम 2022 – फ्रॉम ग्रोथ टू वेलबीइंगः रीथिंकिंग डेवलेपमेंट फॉर अ डिजिटल, ग्रीन एंड जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन?' में 'फ्रॉम ग्रोथ टू वेलबीइंगः ए शेयर्ड विजन ऑफ ए ग्रीन, डिजिटल एंड जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन?' सत्र में पैनलिस्ट।
- फोर्ड फाउंडेशन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस द्व ारा 21 सितंबर 2022, न्यूयॉर्क में आयोजित गवर्नमेंट–फिलैन्थ्रॉपी राउंडटेबलः रीअलाइनिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस विद द एसडीजी थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन' के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक उच्च स्तरीय साइड इवेंट में पैनलिस्ट।
- न्यूयॉर्क में एयूडीए–एनईपीएडी द्वारा 22 सितंबर 2022, को अफ्रीका के विकास सहयोग और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर पुनर्विचार विषय पर आयोजित उच्च–स्तरीय कार्यक्रम में पैनलिस्ट।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 28 सितंबर 2022 को आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत और भारत का विदेश व्यापार विषय पर व्याख्यान दिया।
- बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 29 सितंबर 2022 को कोलकाता में आयोजित इंडियन इकोनॉमी कॉन्क्लेव में इंडियन इकोनॉमी कॉन्क्लेव ऑन अ मिड सेमेस्टर लुक के दौरान ओवरराइडिंग डिस्रप्टिव चेंजिस इन द ग्लोबल इकोनॉमी पर सत्र में पैनलिस्ट।
- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा 30 सितम्बर 2022 को भोपाल में आयोजित जल सम्मेलन में पैनलिस्ट।
- भूटान के पारो में 16 अक्टूबर 2022 को दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिसेफ कंट्री ऑफिस भूटान द्वारा आयोजित साउथ एशिया फाल रीजनल मैनेजमेंट टीम (आरएमटी) की बैठक में 'दक्षिण एशिया के लिए विज़न – जोखिम और अवसर विषय पर सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग और यूनेस्को द्वारा एफएओ विज्ञान और नवाचार फोरम 2022 के दौरान 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित 'एसटीआई रोडमैप्सः कृषि उत्पादन और खपत में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका' पर विशेष कार्यक्रम में कृषि खाद्य प्रणाली के परिवर्तन में एसटीआई सीमाएं, अवसर और चुनौतियां विषय पर सत्र में पैनलिस्ट।
- सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा 26 अक्टूबर 2022 को आयोजित इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 में भविष्य के लिए भारत की अंतरिक्ष रणनीति : विज़न को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाना' विषय पर सत्र में विशेष अतिथि और वक्ता के रूप में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव (जीएसआई) और जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (आईडीओएस) द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को आयोजित थिंक 7 हैंडओवर इवेंट में पैनलिस्ट रहे, जैसा कि वर्ष 2022 में जर्मनी की जी–7 अध्यक्षता के साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के दौरान थिंक टैंक्स को थिंक 7 प्रक्रिया के लिए अधि देशित किया गया।
- आईसीआरआईईआर के 14वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय जी–20 सम्मेलन में, 1 नवंबर 2022 को आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित 'जी–20 की भारत की अध्यक्षता : लचीली, समावेशी और सतत अर्थव्यवस्था (आरआईएसई) पर भारतीय धारणा तैयार करना' में 'विकास और जलवायु संधारणीयता कार्य समूहों में संभावित प्राथमिकताएं और परिणाम' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट।
- इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय और जी–20 फाइनेंस ट्रैक द्वारा टी–20, डी–20–एलटीआईसी और बी–20 के साथ संयुक्त रूप से 2– 3 नवंबर 2022 को ट्यूरिन, इटली में 'सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अनलॉकिंग द पावर ऑफ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डिलीवरी' पर जी–20– टी–20/बी–20/डी–20 में आयोजित तीसरे सेमिनार में 'इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्मः एक्टिवेटिंग प्राइवेट इनवेस्टमेंट एंड बिल्डिंग ऑन डिजिटल ऑपर्चुनिटीज' सत्र में और 'इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज टू अचीव नेट जीरो टार्गेट्स, लैसन्स फ्रॉम जी–20 इंडोनेशिया ऑन द वे टू द जी–20 इंडिया' पर सत्र में पैनलिस्ट।

- मिस्र के शर्म अल–शेख में केएपीएसएआरसी, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज, डब्ल्यूईसी द्वारा 10 नवंबर 2022 को रोड टू नेट ज़ीरोः क्षेत्रीय और वैश्विक संभावनाएं' विषय पर आयोजित कार्यशाला में 'सस्टेनिंग एम्बिशन एंड एक्शन थ्रू ग्लोबल एनर्जी टर्बुलेंस' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- आईटीबी–ईआरआईए –टी 20 सचिवालय द्वारा 'सतत और सशक्त रिकवरी के लिए डिजिटल नवाचारों को आकार देने पर जी–20 लीडर्स समिट की तर्ज पर 15 नवंबर 2022 को आभासी रूप से आयोजित विशेष टी–20 साइड इवेंट में मुख्य वक्ता।
- पेरिस पीस फोरम द्वारा पेरिस में 12 नवंबर 2022 को, पेरिस पीस फोरम के पांचवें संस्करण में आयोजित 'जी–20 : स्टिल ए इफैक्टिव फोरम इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड?' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एसएआईएआरडी) द्वारा 19 नवंबर 2022 को 'सुशासन अभ्यास करने, निरंतरता का अभ्यास करने' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गोलमेज सत्र में प्रमुख पैनलिस्ट।
- आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) द्वारा 24 नवंबर 2022 को आयोजित रिसर्च इंस्टीट्यूट नेटवर्क (आरआईएन) बैठक में 'जी–20/टी–20' पर तीसरे सत्र में प्रस्तुति।
- काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग (सीआईईयू) द्वारा 25 नवंबर 2022 को आयोजित 'जी–20 के लिए भारत का एजेंडा' विषय पर गुप्त या क्लोस्ड डोर गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जनजातीय अनुसंधानः अस्मिता अस्तित्व एवं विकास पर 26 नवंबर 2022 को आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि।
- कार्नेगी इंडिया द्वारा 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक आयोजित किए गए इंडियाज डिजिटल वे : द रोड टू जी–20 एंड बियॉन्ड ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्सेशनः जी–20 ट्रोइकाः इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील' पर पैनल में मॉडरेटर।
- टी–20 सचिवालय, ओआरएफ द्वारा 30 नवंबर 2022 को आयोजित टी–20 संयुक्त कार्यशाला और हैंडओवर इवेंट और 'लाइफ, लचीलापन और सुमंगलम के लिए नैतिक मूल्य' पर द्विपक्षीय कार्यशाला टास्क फोर्स 3 की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में टी–20 सचिवालय द्वारा 30 नवंबर 2022 को आयोजित टी–20 हैंडओवर बैठक : फ्रॉम इंडोनेशिया टू इंडिया में टी–20 सचिवालय हैंडओवर समारोह में भाषण।
- जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन (जेईएफ) द्वारा 2 दिसंबर 2022 को आयोजित जेईएफ–एएनयू संयुक्त एशिया प्रशांत फोरम 2022 में नियम आधारित आर्थिक सुधार (आर्थिक व्यवस्था आधारित हस्तक्षेप) पर सत्र में पैनलिस्ट।
- सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) और ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिसंबर 2022 को ओईसीडी की बहुपक्षीय विकास वित्त रिपोर्ट (एमडीएफआर) को आभासी रूप से जारी करने के अवसर पर आभासी चर्चा में विशिष्ट पैनलिस्ट।
- सीआईआई द्वारा 9 दिसंबर 2022 को आयोजित सीआईआई वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन 2022 में वैश्वीकरण के भविष्य पर सत्र में पैनलिस्ट।
- द डिप्लोमैटिस्ट द्वारा 14 दिसंबर 2022 को ''इंडियाः लीडिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर'' पर द डिप्लोमैटिस्ट के वार्षिक संस्करण में अतिथि संपादक के रूप में भाग लिया
- स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और आईआईटी इंदौर द्वारा 21 दिसंबर 2022 को आयोजित इंडियलिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022: इंडियाज इनोवेशन सिस्टम /75: अचीवमेंट्स, लिमिट्स एंड वे फॉरवर्ड में उद्घाटन भाषण (आभासी रूप से) दिया।
- बेंगलुरु में 27 दिसंबर 2022 को जैन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 105वें वार्षिक सम्मेलन में 'भारत की अध्यक्षता और जी–20 का विकास का एजेंडाः व्यापक चिंतन' पर विशेष भाषण दिया।
- उज्जैन में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 को आयोजित फ्रेमिंग इंडियन नैरेटिव ऑन एनवायरनमेंट पर आयोजित सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लिया।
- चतुर्वेदी, सचिन. 2022. इंडिया जी–20 प्रेसीडेंसीः वर्किंग टुवॉर्ड्स इन्क्लूसिव डेवेलपमेंट फॉर आल – गेस्ट एडिटर्स नोट। एक्स्ट्रॉडिनरी एंड प्लेनीपटेन्शीएरी डिप्लोमेट –वार्षिक संस्करण।

- 9 जनवरी 2023 को कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित एमसीसीआई इकोनॉमिस्ट फोरम की पहली बैठक के दौरान 'व्यवधानों के दौर में विकास रणनीतियां–मुसीबतों का साहस के साथ मुकाबला करना' विषय पर गोलमेज ओपन सत्र में भाग लिया।
- 12–13 जनवरी 2023 को टी–20 सचिवालय और ओआरएफ द्वारा आयोजित टी–20 आरंभिक बैठक में 'वैश्विक कल्याण पर सर्वसम्मति तलाशना : लाइफ, ऊर्जा संक्रमण और एसडीजी पर पूर्ण सत्र में भाग लिया।
- 23 जनवरी 2023 को भारतीय दूतावास और सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज द्वारा आयोजित (ऑनलाइन) भारत–नेपाल विकास साझेदारी सम्मेलन में 'भारत–नेपाल विकास साझेदारी : चिंतन और संभावनाएं' विषय पर सत्र में प्रस्तुति दी।
- 27 जनवरी 2023 को जयपुर में एशिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित टीएएफ की रणनीति बैठक में 'भारत की अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग रणनीति को क्या परिभाषित करता है और इसे कैसे डिलिवर किया जा रहा है' पर विचार प्रकट किए।
- 2 फरवरी 2023 को यूनिसेफ द्वारा आयोजित "भारत और विश्व : 2023 में और उसके बाद भारत के बच्चों और युवाओं के लिए विकास का एजेंडा" विषय पर एक सत्र में विचार प्रकट किए।
- 14 फरवरी 2023 को ओईसीडी द्वारा आयोजित (ऑनलाइन) 2023 विकास सहयोग रिपोर्ट का सार्वजनिक लॉन्च : सहायता प्रणाली पर विचार–विमर्श में भाग लिया।
- गांधीनगर में लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा गुजरात विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए 15 फरवरी 2023 को आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में "जी–20 की भारत की अध्यक्षता" पर प्रस्तुति दी।
- ब्राजील के विदेश मंत्रालय और ओईसीडी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क द्वारा 16 फरवरी 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एक साथ बढ़ावा देना : दक्षिणीय और त्रिपक्षीय सहयोग के संचार से सबक' पर आयोजित (ऑनलाइन) कार्यक्रम में 'दक्षिणीय और त्रिपक्षीय सहयोग के सिद्धांत और संचार' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- जर्मनी संघीय गणराज्य के दूतावास द्वारा 16 फरवरी 2023 को आयोजित त्रिपक्षीय और वैश्विक विकास सहयोग पर भारत और विकास भागीदारों के बीच गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
- सी–20 के लाइफ कार्यसमूह द्वारा 18 फरवरी 2023 को आयोजित सिविल–20 इंडिया 2023 में 'पर्यावरण सम्मत जीवन शैली (लाइफ)' पर प्रस्तुति दी।
- काठमांडू में 24 फरवरी 2023 को यूनिसेफ और सार्क सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यूनिसेफ की क्षेत्रीय रिपोर्ट "रिस्पॉन्डिंग टूडे फॉर टूमारो – चाइल्ड–फ्रेंडली इकॉनोमिक एंड सोशल पॉलिसीज इन द टाइम ऑफ द पैंडेमिक एंड प्राइस इंफ्लेशन इन साउथ एशिया" जारी होने के अवसर पर पैनलिस्ट।
- काठमांडू में 24 फरवरी 2023 को यूनिसेफ द्वारा 'दक्षिण एशिया में बच्चों पर निवेश करना' विषय पर आयोजित सेमिनार में विचार प्रकट किए।
- रूसी अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्पूतनिक द्वारा 3 मार्च 2023 को ऑनलाइन आयोजित 'जी–20 विदेश मंत्रियों की बैठक' में प्रमुख वक्ता।
- ओआरएफ द्वारा 4 मार्च 2023 को आयोजित रायसीना डायलॉग 2023 के दौरान 'उलझावों से परेः खाद्य, ईंधन और उर्वरक संघर्ष को हल करना' पर आयोजित सत्र में प्रस्तुति दी।
- वसंत विहार लिटफेस्ट के दौरान 4 मार्च 2023 को आयोजित 'वैश्विक विपरीत परिस्थितियां और भारतीय अर्थव्यवस्था' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- ओआरएफ द्वारा 5 मार्च 2023 को आयोजित जी–20 ग्लोबल थिंक टैंक टाउन हॉल में "कार्रवाई का दशकः सतत विकास लक्ष्यों की समीक्षा" पर एक सत्र का संचालन किया।
- 9 मार्च 2023 को ईआरआईए द्वारा आयोजित 'अ फ्रैग्मेंटिंग वर्ल्ड ऑर्डरः इंप्लीकेशन्स फॉर साउथईस्ट एशिया इन द इंडो–पैसिफिक एरा' पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 9 मार्च 2023 को 'भारत में खाद्य प्रणाली में परिवर्तन' विषय पर आयोजित एक इंटरैक्टिव गोलमेज में भाग लिया।
- बेलाजियो में 14 मार्च, 2023 को एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) और रॉकफेलर फाउंडेशन, बेलाजियो सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'जी–20/जी–7 रिट्रीट – अ मैटर ऑफ पीस' में 'जी–7 जर्मनी और जी–20 इंडोनेशिया के दौरान

टी–7 और टी–20 से सीखे गए सबक' पर पूर्ण सत्र की सह–अध्यक्षता की।

- बेलाजियो में 16 मार्च, 2023 को एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) और रॉकफेलर फाउंडेशन, बेलाजियो सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'जी–20/जी–7 रिट्रीट – अ मैटर ऑफ पीस' में 'जी–7 और जी–20 में थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी के अन्य संबद्ध समूह' पर सत्र की अध्यक्षता की।
- तिरुपति में 19 मार्च 2023 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित पिछले पांच वर्षों की 'उपलब्धियां/प्रिज्म योजना के प्रभाव का प्रकाशन' पर अंतिम परियोजना समीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया।
- फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज द्वारा 22 मार्च 2023 को आयोजित "ऑपरच्यूनिटी फॉर प्रोजेक्शन ऑफ इंडियाज सॉफ्ट पॉवर इन द लाइट ऑफ जी–20 समिट" पर एफजीएस एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पॉडकास्ट कार्यक्रम में अतिथि वक्ता।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान और विदेश मंत्रालय द्वारा कोलकाता में 25 मार्च 2023 को संयुक्त रूप से आयोजित दूसरे सम्मेलन 'बिम्सटेक–25 इयर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड नेबरहुड कोऑपरेशन' में सम्मानित अतिथि।

प्रोफेसर एस के मोहंती

- आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ– दिल्ली संवाद XII:हिंद–प्रशांत में संबंधों में सुधार लाना में भाग लिया तथा 16 जून, 2022 को नई दिल्ली में भारत और आसियान के बीच आर्थिक साझेदारी को प्रगाढ बनाना :महामारी से उबरने के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण व्यापार, निवेश और मूल्य श्रृंखलाओं को सुगम बनाने से संबद्ध सत्र में द्विपक्षीय एफटीए की समीक्षा प्रस्तुति दी।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव में भाग लिया और विश्व महासागर दिवस, के अवसर पर 8 जून, 2022 नई दिल्ली में नीली अर्थव्यवस्था पर एक विशेष वार्ता के रूप में भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता पर एक प्रस्तुति दी।
- मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एमईआई–एनयूएस), सिंगापुर द्वारा 18 मई, 2022 को आयोजित पश्चिम एशियाः एशियाई प्रतिस्पध र्ा के लिए एक नया क्षेत्र? पर वार्षिक सम्मेलन 2022 में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और एक क्षेत्र के रूप में एमई सहित भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर जूम के माध्यम से प्रस्तुति दी।
- मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एमईआई–एनयूएस), सिंगापुर द्वारा 17 मई, 2022 को आयोजित पश्चिम एशियाः एशियाई प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया क्षेत्र? पर जूम वार्षिक सम्मेलन 2022 में चर्चा के बिंदुओं पर विचार–विमर्श में भाग लिया।
- नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट (एनआईआईसीई) द्वारा 6 मई, 2022 को दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर वेबिनार में भाग लिया और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार सहयोग को बल देने पर एक प्रस्तुति दी।
- एमएसएमई कॉन्क्लेव 2.0– 'ओईएम आपूर्ति श्रृंखला प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देनाः वैश्विक और भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र के संबंध में भविष्य की संभावनाएं' पर वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया तथा ईईपीसी इंडिया, नई दिल्ली द्वारा 14 जुलाई 2022 को आयोजित 'इंजीनियरिंग एमएसएमई के लिए डिजिटल टेक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना' सत्र में 'एमएसएमई भागीदारी के लिए इंजीनियरिंग निर्यात को लक्षित करनाः विस्तारक इंजीनियरिंग क्षेत्र का लाभ उठाने की रणनीति' पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 28 अगस्त 2022 को नेस्ट बोर्ड की बैठक में भाग लिया और विकास पथ और नए आकलन दृष्टिकोण सत्र की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली 9 नवंबर 2022 को फिक्की द्वारा नीली अर्थव्यवस्था पर आयोजित ज्ञान कार्यशाला में भाग लिया और भारत में नीली अर्थव्यवस्था : कारोबारी समुदायों के लिए अवसर विषय पर प्रस्तुति दी।
- वाणिज्य भवन में 9 नवंबर 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई चीन से आयात पर माननीय वाणिज्य और उद्योग, सीएएफपीडी और कपड़ा मंत्री की बैठक में भाग लिया।
- यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा 14 नवंबर 2022 को आयोजित यूजीसी जेएमआई व्याख्यान श्रृंखला के तहत 'बिम्सटेक क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण

की संभावनाएं: कृषि व्यापार पर केंद्रित' पर आभासी व्याख्यान दिया।

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्व ारा प्रलेखन अधिकारी, जेएनयू के संबंध में सीएएस पदोन्नति के लिए निर्धारित चयन समिति की 15 नवंबर 2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 'चीन पर आयात निर्भरता कम करने की दिशा में कार्य प्रगति पर : क्षेत्रवार रणनीति विकसित करना' रिपोर्ट 6 दिसंबर 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।
- विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा बिम्सटेक में मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों की क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं पर शोध अध्ययन पर चर्चा करने के लिए 8 दिसंबर 2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया।
- लोक सभा सचिवालय – संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित सांसदों, संसदीय कर्मचारियों और संस्थागत अवसरों वाले अन्य लोगों के लिए विभिन्न विषयों में व्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जी–20 के बारे में संवेदनशील बनाने संबंध ी सत्रों की एक श्रृंखला में भाग लिया और ''वैश्विक शासन के मुद्दों पर निर्णय लेने की दिशा में कार्य समूहों (टी–20, बी–20, सी–20, वाई–20,एल–20, डब्ल्यू–20) पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी–20 की भूमिका'' जी–20 के मुद्दों के निर्धारण और जी–20 के मुद्दों पर पहुंचने की प्रक्रिया में टी–20 की भूमिका का विश्लेषण और जी–20 नेताओं के घोषणा पत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया–अतीत से सबक" विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- आरआईएस, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन और जैन सीएमएस बिजनेस स्कूल, बेंगलुरु द्वारा 27 दिसंबर 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 105वें वार्षिक सम्मेलन में 'जी–20 की भारत की अध्यक्षता और विश्व आर्थिक व्यवस्था : व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी' पर एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया तथा जी–20 के संबंध में वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बदलते रंग : जी–20 भारत की अध्यक्षता के लिए निहितार्थ' पर प्रस्तुति दी।
- मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा 18 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित थिंक20 / जी–20: टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट साउथ एशिया में भाग लिया और 'लचीलेपन और क्षेत्रीय वृद्धि को प्रोत्साहन' पर प्रस्तुति दी।
- चेन्नई में 15 फरवरी 2023 को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कुलपति और डीन तथा संकाय के वरिष्ठ सदस्यों के साथ नीली अर्थव्यवस्था और नए संभावित अवसरों और सहयोग के क्षेत्रों के संबंध में चर्चा बैठक में भाग लिया।
- 16 फरवरी, 2023 को पुडुचेरी में पांडिचेरी विश्वविद्यालय (पीयू) के कुलपति और संकाय के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आरआईएस और पीयू अपने भविष्य के प्रयासों विशेषकर नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनुसंधान और नीति–निर्माण के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), नई दिल्ली द्वारा 27 फरवरी 2023 को नीली अर्थव्यवस्था पर आयोजित एक कार्यशाला में वक्ता के रूप में भाग लिया और 'नीली अर्थव्यवस्था: ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत' पर प्रस्तुति दी।
- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय द्व ारा 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 70वें प्रोफेशनल कोर्स फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स में भाग लिया और 'भारत में नीली अर्थव्यवस्था नीति को आकार देने की ओर' पर राजनयिकों को संबोधित किया।
- मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपीआईडीएसए) द्वारा 24 मार्च 2023 को आयोजित एमपी–आईडीएसए–सिचुआन यूनिवर्सिटी ट्रैक 2 ऑनलाइन द्विपक्षीय संवाद में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों पर प्रस्तुति दी।

डॉ.सब्यसाची साहा

एसोसिएट प्रोफेसर

- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान(एसएसआईएफएस) में गुरुवार 16 फरवरी को ईरान के लिए दूसरे विशेष पाठ्यक्रम में 'सतत विकास लक्ष्यों' पर व्याख्यान दिया।
- नई दिल्ली में 18 फरवरी 2023 को सिविल–20 लाइफ (पर्यावरण सम्मत जीवन शैली) कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया।
- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान(एसएसआईएफएस) में मंगलवार, 27 फरवरी 2023 को प्रशांत द्वीपीय देशों

के राजनयिकों के लिए तीसरे विशेष पाठ्यक्रम में 'सतत विकास लक्ष्यों' पर व्याख्यान दिया।

- नई दिल्ली में 04 मार्च 2023 को रायसीना डायलॉग के दौरान सह–अध्यक्षों की टी–20 टास्क फोर्स 3 बैठक में भाग लिया।
- अमृतसर, पंजाब, भारत में 18–20 मार्च 2023 को जी–20 इंसेप्शन मीट में एल–20 में "काम की बदलती दुनिया : जी–20 देशों में रोजगार के नए अवसर" पर व्याख्यान दिया।

डॉ प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- टी20 इंडोनेशिया के सहयोग से आईएसपीआई, इटली द्वारा 20–21 जून, 2022 को आयोजित ग्लोबल पॉलिसी फोरम में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- जी–20 की संरचना के भीतर तथा इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय, डी20 और टी20 तथा बी20 के आधिकारिक संबद्ध समूहों के सहयोग से 'बहाली और सुरक्षित, सतत भविष्य के लिए बलों के साथ जुड़ना : जी–20 में उच्च प्रभाव वाली सतत ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बहुपक्षीय रोडमैप का आकलन करना' विषय पर 24 मई 2022 को आयोजित वर्चुअल सेमिनार में चर्चा में भाग लिया।
- रशियन प्रेसिडेंशियल एकेडेमी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आरएएनईपीए) द्वारा आभासी रूप से 4–5 अक्टूबर, 2022 को ''द वर्ल्ड एट ए क्रिटिकल जंक्चर व्हाट फ्यूचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस?'' विषय पर आयोजित पर सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- एक्सआईएम विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा 10 दिसंबर, 2022 को आयोजित किए गए 'पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड बिजनेस इन ए सस्टेनेबल वर्ल्ड' शीर्षक वाले पब्लिक पॉलिसी कॉन्क्लेव में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- इंडियन–आसियान स्टडी डिपार्टमेंट, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, हेन्कुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, दक्षिण कोरिया में 14 दिसंबर, 2022 को ''बिम्सटेक के नए परिदृश्य: सेवाएं, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर'' पर आभासी माध्यम से व्याख्यान दिया।
- इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 105वें वार्षिक सम्मेलन में जी–20 पर आरआईएस–टी–20 विशेष सत्र में सीएमएस बिजनेस स्कूल, जैन विश्वविद्यालय, बेंगलुरु द्वारा 27 दिसंबर 2022 को आयोजित विश्व आर्थिक व्यवस्था : व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी' में मॉडरेटर के रूप में शामिल हुए, तथा ''अवसंरचना एवं विकास वित्त तक पहुंच बढ़ाना'' विषय पर प्रस्तुति दी।
- भारत सरकार और यूएनडीपी द्वारा नई दिल्ली में 19 जनवरी, 2023 को आयोजित 'रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी समिटः विजन 2047' में 'स्ट्रेटेजीज टू बिल्ड कोस्टल रेजिलिएंस इन इंडिया' पर आयोजित साइड इवेंट में पैनलिस्ट के रूप में प्रस्तुति दी।
- सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे द्वारा 20–21 जनवरी, 2023 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय संबंध सम्मेलन में 'भारत और अफ्रीकाः पुराने साझेदार, नई चुनौतियां और अवसर' विषय पर पैनलिस्ट के रूप में प्रस्तुति दी।
- 2 फरवरी, 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद में विद्यार्थियों के लिए "जी–20 और उभरते भू–आर्थिक मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर व्याख्यान दिया।

डॉ. पंकज वशिष्ठ

एसोसिएट प्रोफेसर

- 1 फरवरी 2023 को संसद टीवी पर बजट पूर्व –चर्चा में भाग लिया।
- 17 फरवरी 2023 को संसद टीवी के प्राइम टाइम शो अर्थनीति में भाग लेकर केंद्रीय बजट 2023, पर चर्चा की।

डॉ. अमित कुमार

सहायक प्रोफेसर

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नई दिल्ली में 13 जनवरी 2023 को "भारत की आर्कटिक संबद्धताएं" विषय पर आयोजित छमाही बैठक में भाग लिया।
- 28 फरवरी 2023 को इंडिया कोरिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन (आईकेसीआरआई), नई दिल्ली के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में भाग लिया; इसमें इसके निदेशक, डॉ (सुश्री) वाई जे पार्क और भारत में दक्षिण कोरिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अताशे श्री ह्योही ली शामिल रहे।

डॉ. पंखुडी गौर

सहायक प्रोफेसर

- इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, श्रीलंका द्वारा श्रीलंका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एसोसिएशन (एसएईए) के 16वें वार्षिक अनुसंधान मंच में 20 जनवरी, 2023 को आयोजित "दक्षिण एशिया में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को शामिल करना" में पैनलिस्ट।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फेलो

- विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के निमंत्रण पर 26 मई, 2022 को उज्बेकिस्तान द्व ारा आयोजित 'शंघाई सहयोग संगठन की संरचना में 'गरीबी में कमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में 'भारत में गरीबी में कमी' पर प्रस्तुति दी।
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा 11 अक्टूबर, 2022 को भारत में कृषि और पौष्टिक खाद्य प्रणालियों के संदर्भ में आयोजित गोलमेज चर्चा में विचार–विमर्श किया।
- आईएसआईडी द्वारा 27 जनवरी 2023 को 'इफैक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: थ्योरी एंड एम्पिरिक्स' पर आयोजित शोध संगोष्ठी में भाग लिया।
- 31 जनवरी–1 फरवरी, 2023 को ओईसीडी कें 'सतत विकास सम्मेलन के लिए निजी वित्त' में भाग लिया।

श्री राजीव खेर

विशिष्ट फेलो

- एस्या सेंटर द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से 17–18 जून, 2022 को आयोजित डेटा मार्केट में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों से संबंधित रणनीतिक योजना पर चर्चा में भाग लिया।
- डेलॉइट द्वारा 19 मई,2022 को आयोजित 'डिजिटल फ्रंटियर: टेक्नोलॉजी एंड द बोर्ड' विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया।
- 17 मई, 2022 को 8वीं क्यूसीआई पीपीडी संचालन समिति की बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर–केएएस द्वारा 5 मई,2022 को आयोजित कोविड के बाद के विश्व में डब्ल्यूटीओ 2.0 पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- डेलॉइट द्वारा 4 मई, 2022 को आयोजित कार्यक्रम 'इन्फ्लैशन आउटलुक: हाउ कैन बोर्ड्स प्रीपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लैशन?' में भाग लिया।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 28 अप्रैल, 2022 को 'गियरिंग अप विद् ईएसजी : अ डिस्कशन ऑन इंडियाज़ ईएसजी प्लेबुक, प्रीपेयर्डनेस एंड एक्सपेक्टेशन्स' विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- कट्स द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को 'क्या 'डेटा स्थानीयकरण' और 'राष्ट्रीय चैंपियन' दृष्टिकोण एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा? विषय पर आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया।
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को 'फ्रॉम ग्रे टू ग्रीन :नेट–जीरो ट्रांसिशन ऑप्र्ट्यूनिटीज़ फॉर इंडिया' विषय पर आयोजित में प्रमुख संगोष्ठी में भाग लिया।

डॉ भास्कर बालकृष्णन

साइंस डिप्लोमेसी फेलो

- आईएफएस के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 7 जुलाई 2022 को सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (एसएसआईएफएस) द्वारा आयोजित प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान कूटनीति पर व्याख्यान दिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. सामाजिक क्षेत्र: समावेशी बुनियादी ढांचा, योजना, अप्रैल 2022

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. स्ट्रेंगथनिंग बिम्सटेक पार्टनरशिप्स फॉर कलेक्टिव डेवलॅपमेंट. इन 25 ईयर्स ऑफ बिम्सटेक : टुअर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल, ढाका, बिम्सटेक सचिवालय, ढाका (पीपी.35–46)।

चतुर्वेदी, सचिन, टिम बुथे, पीटर बी पायोयो और कृष्णा रवि श्रीनिवास 2022. 'इंडिया एंड द फिलीपींस इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस' इन रीथिंकिंग पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, जोस्ट पॉवेलिन, मार्टिनो मैगेटी, टिम बुथे, और आयलेट बर्मन द्वारा संपादित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2022, (पीपी 349–378) ।

चतुर्वेदी, एस एंड पोगे, थॉमस. 2022. इंडियाज़ स्टैंड ट्रिप्स वैक्सीन इनेक्विटी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 08 जून, 2022

चतुर्वेदी, एस. 2022 . बांड्स ऑफ द बेः फुलफिलिंग द पोटेंशियल ऑफ बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी. इंडियन एक्सप्रेस, 09 अप्रैल, 2022

चतुर्वेदी, सचिन, टिम बुथे, पीटर बी पायोयो, और कृष्णा रवि श्रीनिवास, 'इंडिया एंड द फिलीपींस इन ग्लोबल हैल्थ गवर्नेंस' जूस्ट पॉवेलिन, मार्टिनो मैगेटी, टिम बुथे, और आइलेट बर्मन द्वारा संपादित, रीथिंकिंग पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2022, आगामी (पीपी 349–378)।

चतुर्वेदी, सचिन, साहा, सब्यसाची और शॉ, प्रतिवा 'इंडिया 'लीवरेजिंग ट्रेड इन हाई टेक्नोलॉजी फॉर इमर्जेंसः द ब्रिक्स एक्सपीरियंस, 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली', वॉल्यूम स्टप्प्ए नंबर 39, सितंबर 2022।

चतुर्वेदी, सचिन.2022. वाइ बाइलैटरल ट्रेड डील्स आर बेनिफिशियल फॉर इंडिया? इकोनॉमिक टाइम्स, 23 नवंबर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. रिडिज़ाइनिंग ग्लोबल फाइनेशियल आर्किटेक्चर एंड डेवेलपमेंट स्ट्रेटेजी। ब्लिट्ज इंडिया, 18 नवंबर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. टुअर्ड्स जी–20 इंडिया : ब्रिंगिंग बैक द स्प्रिट ऑफ कोऑपरेशन। इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पोलिटिकल स्टडीज, कॉमेंट्री 14 नवंबर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. जी–20 समिट : न्यू एनर्जी फॉर द जी–20ः एक्सप्लोरिंग द वे अहैड। द ग्लोबल गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जी–20 इंडोनेशियाः द बाली समिट–2022 ।

चतुर्वेदी, सचिन.2023. सोशल सेक्टर एलोकेशन्स : एंडेवर फॉर इफैक्टिव आउटकम्स, योजना, मार्च–पी 23–27.

चतुर्वेदी, सचिन.2023 सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटनः ठोस परिणाम के लिए प्रयास योजना, मार्च–पी 23–27(हिंदी).

चतुर्वेदी, सचिन. 2023। इन माइ व्यूः वर्क विद सदर्न प्रोवाइडर्स टू अचीव ग्रेटर स्केल एंड रेलेवेंस डेवलेपमेंट कोऑपरेशन रिपोर्ट : डिबेटिंग द ऐड सिस्टम में। ओईसीडी, पेरिस. पी 201–203.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. द अककंप्लीशमेंट – अक्क्रूइंग द पोटेंशियन : ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी अरविंद सिंह (संपा.) नरेंद्र मोदी शेपिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, साप्ताहिक विवेकः मुंबई.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. एजेंडा 2063 एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी–फेसेटेड इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिप, निवेदिता रे और संकल्प गुर्जर (संपा) इंडिया एंड अफ्रीका लुकिंग अहेड कंटेम्पररी रिएलिटीज एंड इमर्जिंग प्रॉस्पेक्ट्स में। पी 67–72. मैकमिलन, 1 जनवरी 2023

चतुर्वेदी, सचिन. 2023 (सह–लेखक)। अ ब्ल्यूप्रिंट फॉर अ टी–20 नेटवर्क इन एशिया. टेत्सुशी सोनोबे और अन्य (संपा) अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, अ वर्ल्ड इन प्रोग्रेसः ग्रोइंग बेटर टुगेदर, में एडीबी इंस्टीट्यूट.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. रिड्रेसिंग ग्लोबल फाइनेंसिंग फॉर एसडीजी, डेट रिलीफ फॉर एलडीसी, इंडिया एंड द वर्ल्ड–इंडियाज जी–20 मोमेंटः हीलिंग,होप एंड हारमनी, खंड–5 संख्या–4.

चतुर्वेदी, सचिन और पी. दाश. 2023 "अ ब्ल्यूप्रिंट फॉर टी–20 नेटवर्क इन एशिया। एडीबीआई की पुस्तक 'अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, अ वर्ल्ड इन प्रोग्रेस– ग्रोइंग बेटर टुगेदरः लेसन फ्रॉम अ डिकेड ऑफ टी–20' में.

चिराथिवट, सुतिफंद, चरित तिंगसाध, प्रबीर डे (संस्करण) (2022) बिटवीन द टू ओशन्स ऑफ इंडो–पेसिफिकः स्ट्रेंगथनिंग म्यांमार–थाईलैंड सदर्न कॉरिडोर, सेज, नई दिल्ली, सितंबर 2022।

प्रियदर्शी दाश, 2023. "कोऑपरेशन अमंगस्ट गवर्नमेंट्स : एन्श्योरिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडो–पैसिफिक"। रीजनल इंटिग्रेशन इन इंडो–पैसिफिक : कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन एंड न्यू सप्लाई चेन,लिंकेजिस में। ईआरआईए रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2022 संख्या 19.

डे, प्रबीर (2022) "थाईलैंड–म्यांमार ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोरः एन इंडियन पर्सपेक्टिव" चिराथिवत एट ऐल में। (2022)।

डे, प्रबीर और निदा रहमान (2022) "रिव्यू ऑफ आसियान–इंडिया एफटीए इन गुड्सः ब्रॉड कंटूर्स एंड द नेक्स्ट स्टेप्स", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम. 57, नंबर 33, 13 अगस्त, 2022

डे, प्रबीर और दुरइराज कुमारसामी (2022) "आसियान–इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप : मलेशियाज़ रोल इन इंटेसिफाइंग कोऑपरेशन",एमईए–आईएसआईएस मलेशिया में (सं।) इंडिया–मलेशिया/65, केन्द्र बिंदु, कुआलालम्पुर

डे, प्रबीर (2022) ''थर्टी ईयर्स ऑफ आसियान–इंडिया कनेक्टिविटी'', टॉमी कोह एट ऐल (संपा.) आसियान एंड इंडियाः द वे फॉरवर्ड, वर्ल्ड साइंटिफिक, सिंगापुर।

डे, प्रबीर (2022) ''डिसाइफरिंग द 19 आसियान– इंडिया समिट'', हिंदुस्तान टाइम्स, 13 नवंबर 2022

कुमार, कृष्ण 2023. टीएफ 3: 'लाइफ रेजिलिएंस एंड वेल्यूज फॉर वेलबीइंग'– टी–20 पॉलिसी ब्रीफ एबस्ट्रैक्ट टाइटल्ड, 'गोइंग बीयोंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) : वेल्यूइंग वेलबीइंग'; प्रमुख लेखक के रूप में।

कुमार, कृष्ण 2023. टीएफ –6: एक्सीलेरेटिंग एसडीजीः एक्सप्लोरिंग न्यू पाथवेज टू द 2030 एजेंडा'– टी–20 पॉलिसी ब्रीफ एबस्ट्रैक्ट टाइटल्ड, ' फाइनेंसिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल एग्री–फूड सिस्टम्स' (सह–लेखक) के रूप में।

मोहंती, एस.के. 2023. "प्रॉस्पैक्ट्स ऑफ ग्रोथ डायनेमिज्म इन साउथ एशिया" द रूटलेज हैंडबुक ऑफ साउथ एशिया में रूटलेज इंडिया पृ. 176–197.

मोहंती, एस.के. 2022 रीजनल इकॉनोमिक्स डायनेमिक्स ऑफ बिम्सटेक ड्यूरिंग द ग्लोबल रिसेशनः चायना फैक्टर इन द रीजनल कॉकस। न्यू फ्यूचर्स फॉर बिम्सटेक में। रूटलेज इंडिया पृ.147–166.

मोहंती, एस.के., गौड़, पी., दवानी, सी., सिरेगर, आर.एन., जू, एन., क्रेट, जी., ... एंड मैज़ोटी, पी. 2022। ग्रीनिंग ग्लोबल ट्रेडः एन्हेंस्ड सीनर्जीज बिट्वीन क्लाइमेट एंड ट्रेड पॉलिसीज फॉर डीकार्बोनाइजेशन. टी20 टीएफ1, नीतिगत सारांश 4. जी–20 इंडोनेशिया।

श्रीनिवास रवि के. 2023. सह–लेखक "ए चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डेटा गवर्नेंस रिजीम" द हिंदू, मार्च 14.

श्रीनिवास रवि के. वैन एस्ट, आर. के साथ सह–लेखक 2023. " टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन डेवेलपिंग कंट्रीज : द केस ऑफ इंडिया– एक्जांपल ऑफ गवर्नमेंटल एंड इनफॉर्मल टीए": हेन्नेन, एल., हैन, जे., लेडिकास, एम., लिंडनर, आर., पिस्सल, डब्ल्यू., वैन एस्ट, आर. (संपा) टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। स्प्रिंगर, चैम. पीपी 101–123, 2023.

श्रीनिवास रवि के. वान बालेन, एस., हे, जी. के साथ सह–लेखक 2023. "चैलेंजिस ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी – ब्रिंगिंब क्लेरिटी एंड बैटर अंडरस्टेंडिंग इन फ्रैगमेंटेड ग्लोबल गवर्नेंस": हेन्नेन, एल., हैन, जे., लेडिकास, एम., लिंडनर, आर., पिस्सल, डब्ल्यू., वैन एस्ट, आर. (संपा) टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। स्प्रिंगर, चैम. पीपी 149–173, 2023.

श्रीनिवास रवि के. 2023. टेक्नोलॉजी असेसमेंट एक्टीविटीज इन इंडिया : हेन्नेन, एल., हैन, जे., लेडिकास, एम., लिंडनर, आर., पिस्सल, डब्ल्यू., वैन एस्ट, आर. (संपा) टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। स्प्रिंगर, चैम. पीपी 149–173.

श्रीनिवास रवि के. 2023. "सिसजेनेसिस एंड सिजेनिक क्रॉप्सः नीड फॉर ए पैराडाइम शिफ्ट इन हार्नेसिंग एंड गवर्नेंस" – सिसजेनिक क्रॉप्सः सेफ्टी, लीगल एंड सोशल इश्यूज में (संपा) अनुराग चौरसिया, चित्तरंजन कोले चैमः स्प्रिंगर. पीपी 255–268.

श्रीनिवास रवि के. बोनादियो, ई., अयंगर, और बी. पी., चौधरी, ए. 2023. के सह–लेखक "गांधीयन फिलॉसफी एंड इंडियन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी" : मित्तल, आर., सिंह, के.के. (संपा) रेलेवेन्स ऑफ ड्यूटीज इन द कॉन्टेंपररी वर्ल्ड में। स्प्रिंगर, सिंगापुर। पीपी 343–365.

वशिष्ठ पी. एंड जे.डी. दुबे (2022):'टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया', एस. महेंद्र देव (संपा) ''इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022'': ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

वशिष्ठ पी. (2022): 'इंडो–पैसिफिक स्ट्रैटेजीजः व्हाट डू दे एन्टेल फॉर इंडिया', आरआईएस चर्चा पत्र संख्या 274, आरआईएस, नई दिल्ली।

सुखमय चक्रवर्ती पुस्तकालय आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

आरआईएस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ने हाल के महीनों में नवीनतम विशिष्ट प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–जर्नल्स एवं लेखों इत्यादि को हासिल किया है, ताकि आरआईएस की संकाय और आगंतुक विद्वानों को अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें। यह कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न प्रकाशनों या आलेखों के कार्यक्रम का आदान–प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों पर विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी अधिक प्रकाशनों या आलेखों तथा अध्ययन कार्यक्रमों को जोड़कर संसाधन आधार को निरंतर समृद्ध करता रहता है।

इस केंद्र के प्रमुख वैश्विक संस्थानों जैसे कि एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इत्यादि के साथ घनिष्ठ जुड़ाव हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य–पत्र (वर्किंग पेपर), परिचर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर), री–प्रिंट्स, समसामयिक पत्र दरअसल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या तो परस्पर आदान–प्रदान किए गए कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त होते हैं या संस्थागत वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। वर्तमान केंद्र में 24,590 से भी अधिक पुस्तकें हैं जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज शामिल हैं। इनके अलावा सजिल्द पुस्तक के रूप में 1850 पत्र–पत्रिकाएं हैं। इस केंद्र ने 434 से भी अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्र–पत्रिकाओं की सदस्यता भी ले रखी है जिनमें जस्टर, आईएमएफ ई–लाइब्रेरी, एल्सवियर– साइंसडायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विली इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस केंद्र को प्रतिष्ठित स्रोतों से सम्मानार्थ भेंट के आधार पर लगभग 50 पत्र–पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। 350 से भी अधिक सीडी रॉम और डेटाबेस हैं। एक और खास बात यह है कि 'डेलनेट' का सदस्य होने के नाते यह संसाधन–साझाकरण को बढ़ावा देता है।

इस केंद्र में आसान पहुंच के लिए इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन समृद्ध संग्रह उपलब्ध है।

अभिलेखन केंद्र/पुस्तकालय के संग्रह में ये शामिल हैं

- पुस्तकें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी
- जर्नल / पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र
- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस
- आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8– अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस, भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाबेस, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आरआईएस डेटाबेस

आरआईएस ने देवकूपइंडिया नामक एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया है, जिसका उद्देश्य 1947 से 2021 तक भारत की ओर से भागीदार देशों को प्रदान की गई विकास संबंधी सहायता का ब्यौरा को दर्ज करना है। इस डेटाबेस में डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की पांच कार्यपद्धतियां अर्थात्– क्षमता निर्माण, अनुदान, रियायती वित्त, व्यापार और बाजार तक पहुंच, और तकनीकी हस्तांतरण शामिल हैं। प्रमुख वर्गीकरण को उप–कार्यपद्धतियों, क्षेत्रों और गतिविधियों में विभाजित किया गया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अतिरिक्त कई अन्य मंत्रालय शामिल किए गए हैं, जो अनेक कार्यपद्धतियों और उप–कार्यपद्धतियों के माध्यम से विकास संबंधी सहायता देने में सम्मिलित हैं। डेटाबेस में भारत के अनुदान शामिल हैं, जिनमें द्विपक्षीय विकास के लिए सहायता के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिया गया योगदान भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में विकास सहायता के लिए आवंटन 2021–22 के संशोधित अनुमानों द्वारा निर्धारित है, जैसा कि 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

एक अन्य डेटाबेस में जीडीपी, व्यापार, निवेश, शुल्क और अन्य संबद्ध कारकों जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। व्यापार और शुल्क डेटाबेस के संदर्भ में, आरआईएस डेटा को अधिकतम पृथक स्तर पर प्रभावी ढंग से पुनर्गठित करता है। उदाहरण के लिए, भारत के लिए द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों का आवंटन 8–अंकों वाले हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित है, जबकि शेष विश्व के लिए यह 6–अंकों वाले एचएस वर्गीकरण पर आधारित है। डेटा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण में मौजूद सभी शब्दावलियों में दर्ज किया गया है। पृथक्करण का स्तर और समय श्रृंखलाओं का

स्तर अलग–अलग डेटा स्रोतों के साथ भिन्न–भिन्न होता है। इस डेटाबेस को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस एक आधुनिक डेटा सर्वर का रख–रखाव बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है जिसमें उसके आंकड़ो कोष की बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत आंकड़ों को नष्ट करने वाले वाइरल या हैकिंग सहित किसी भी संभावित बाहरी हमले से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण ीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2020–21) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैं:

परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों,

आरआईएस बुक क्लब

व्यक्तियों को सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, विविध परिप्रेक्ष्यों का आदान–प्रदान करने और उनके महत्वपूर्ण चिंतन के कौशलों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने की दिशा में एक पहल है।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया

आरआईएस ने ट्विटर, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचो पर अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में इसके अनुगामी भी हैं। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को निरंतर अपडेट रखा जाता है। लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आयोजनों को इसकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया जाता है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल की दर्शक संख्या में अच्छी–खासी वृद्धि दर्ज की गई है तथा उसका ग्राहक आधार भी अब और ज्यादा बढ़ गया है।

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर

4 हजार से भी अधिक अनुगामी हैं और इसके पेजों को लोगों की रायशुमारी के आधार पर 5 में से 4.3 रेटिंग दी गई है। ट्विटर हैंडल के 4 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वास्त. विक समय पर लोगों की त्वरित पहुंच के लिए आरआईएस के

ब्रिक्स
http://bricscivil.ris.org.in

बिमस्टेक
http://bimstec.ris.org.in

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
http://aagc.ris.org.in

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) पहल
http://iora.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों पर आरआईएस का कार्यक्रम
http://sdg.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल
http://sti4sdg.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

एफआईएसडी
http://fisd.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

ब्लू इकोनॉमी फोरम
http://blueeconomyforum.ris.org.in

वैश्विक विकास केंद्र
http://gdc.ris.org.in

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

न्यू एशिया फोरम
http://newasiaforum.ris.org.in

इसके अलावा, वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबसाइट पेज भी हैं :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
http://ris.org.in/asian-infrastructure-investment-bank

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
http://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series-0

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दस्तावेज
http://ris.org.in/documents-non-aligned-movement

समर स्कूल
http://ris.org.in/summer-school-0

पेरिस शांति फोरम
http://ris.org.in/deadline-extended-extra-time-submit-your-project-paris-peace-forum

विश्वविद्यालय कनेक्ट
https://ris.org.in/university-connect-engaging-young-minds

टी20
https://ris.org.in/think-20

जी20 डाइजस्ट
https://ris.org.in/G20Digest/index.html

आरआईएस की देख–रेख वाली अन्य वेबसाइटें

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.org

इब्सा
http://ibsa-trilateral.org

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

चालू वित्त. वर्ष (2019–20) के दौरान आरआईएस की वे. बसाइट ने 'हिट' की कुल संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की है। इसने

प्रत्येक प्रमुख कार्यकलाप को इन दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, दर्शकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक है।

आरआईएस की इंट्रानेट सुविधा

संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट सुविधा है जो कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़ी बातों के संबंध में पासवर्ड संरक्षित जानकारियां प्रदान करती है, जिनमें अवकाश का रिकॉर्ड, वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अपने संकाय के लिए अनुसंधान डेटाबेस भी प्रदान करती है जो सीडी प्रारूप में उपलब्ध होता है और जो अन्य बातों के अलावा व्यापार आंकड़ों की दिशा, कस्टाडा, विश्व विकास संकेतकों, सरकारी वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) को कवर करता है।

सोशल मीडिया आउटरीच

बीते वर्षों में इस संस्थान ने ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी पहुंच को व्यापक बनाया है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को लगातार अद्यतन रखा जाता है। ट्विटर पर लगभग 10 हजार हैं। कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग सुगम पहुंच के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाती है। यूट्यूब चैनल पर दर्शकों की संख्या और ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हुई है। आरआईएस यूट्यूब चैनल पर लगभग 1.26 हजार सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 4.7 हजार से ज्यादा है और पब्लिक ओपिनियन पोल्स के आधार पर इसके पेजों को 5 में से 4.6 रेटिंग दी गई है। आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख आयोजन को वास्तविक समय के आधार पर त्वरित सार्वजनिक पहुंच के लिए इन दोनों प्लेटफार्मों पर तत्काल फ्लैश किया जाता है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन आदि पर दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहवर्धक रही है।

हम आरआईएस के संकाय सदस्यों के अत्यधिक आभारी हैं, जिनके अटूट समर्पण ने नवोन्मेषी अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, जिसकी बदौलत संस्थान की वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है। हमारे सम्मानित संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की गई आरआईएस की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की प्रभावशाली यात्रा का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करती है।

पिछले पांच वर्षों में आरआईएस के हिट्स

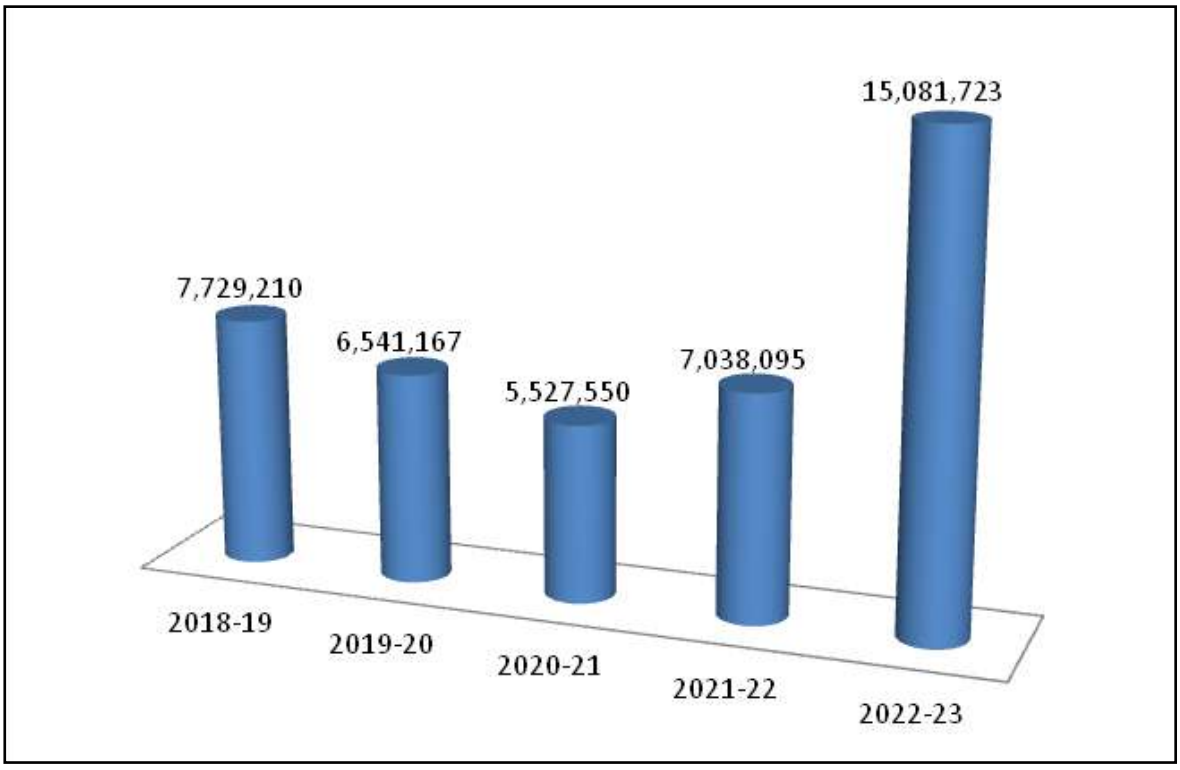

अभिस्वीकृति

हम आरआईएस के संकाय सदस्यों के अत्यधिक आभारी हैं, जिनके अटूट समर्पण ने नवोन्मेषी अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, जिसकी बदौलत संस्थान की वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है। हमारे सम्मानित संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की गई आरआईएस की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की प्रभावशाली यात्रा का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करती है।

जी20 अध्यक्षता

प्रमुख समन्वयक	**डॉ प्रियदर्शी दाश**
	डॉ पी के आनंद
	डॉ. सब्यसाची साहा
	डॉ. चैतन्य गिरी
	डॉ. पंकज वशिष्ठ
	डॉ भास्कर बालाकृष्णन
	डॉ सायंतन घोषाल
विशेष टिप्पणी	**डॉ आईवी सरकार**

वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था और सहयोग

प्रमुख समन्वयक	**डॉ सायंतन घोषाल, रितुपर्णा**
विशेष टिप्पणी	**डॉ भास्कर बालाकृष्णन**

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा

प्रमुख समन्वयक	**डॉ शंपा कुंडू**
विशेष टिप्पणी	**डॉ. पंकज वशिष्ठ**

व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सहयोग

प्रमुख समन्वयक	**डॉ. पंखुरी गौड़**
विशेष टिप्पणी	**प्रोफेसर एस. के. मोहन्ती**

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रगति के मुद्दे

प्रमुख समन्वयक	**डॉ स्नेहा सिन्हा**
	डॉ नम्रता पाठक
	डॉ बीना पाण्डेय
विशेष टिप्पणी	**प्रोफेसर टी सी जेम्स**

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ एस के मोहंती
प्रोफेसर (31 अक्टूबर 2022 तक)
विशिष्ट फैलो (1 नवंबर 2022 से)
विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ सब्यासाची साहा
सह प्रोफेसर
विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश
सह प्रोफेसर
विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ पंकज वशिष्ठ
सह प्रोफेसर
विशेषज्ञताः व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ बीना पाण्डेय
सहायक प्रोफेसर
(31 मार्च 2023 तक)
विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. सुशील कुमार
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. अमित कुमार
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञताः नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

सुश्री पंखुड़ी गौर
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, एफटीए और मेगा क्षेत्रीय

विशिष्ट फैलो

श्री राजीव खेर
विशिष्ठ फैलो
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

श्री अमर सिन्हा
विशिष्ठ फैलो
विशेषज्ञता: आर्थिक कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग

श्री आर वी साही
विशिष्ठ फैलो

विजिटिंग फैलो

डॉ भास्कर बालाकृष्णन
साइंस डिपलोमेसी फैलो
विशेषज्ञता: एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

श्री कृष्ण कुमार
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: आधिकारिक सांख्यिकी एवं सतत विकास लक्ष्य

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

डॉ. पी के आनन्द
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: आर्थिक विकास और विकास

डॉ. राम उपेन्द्र दास
वरिष्ठ विजिटिंग फैलो
(26 नवंबर 2022 तक)

फैलो/सलाहकार

डॉ नम्रता पाठक
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता: पारंपरिक ज्ञान

डॉ अंशुमन गुप्ता
सलाहकार
विशेषज्ञता: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

डॉ सविता के एल
फैलो
(7 मार्च 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक)
विशेषज्ञता: एसडीजी के लिए पर्यावरण अर्थशास्त्र, एसडीजी और एसटीआई

डॉ चैतन्य गिरी
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतरिक्ष डोमेन रणनीतियाँ, ग्रह विज्ञान

डॉ स्नेहा सिन्हा
सलाहकार
विशेषज्ञता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन

डॉ राहुल रंजन
सलाहकार
विशेषज्ञता: ऊर्जा अर्थशास्त्र और ऊर्जा में व्यापार

श्री सायंतन घोषाल
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सुरक्षा कल्याण प्रणाली

डॉ रोहित सैनी
फैलो
(16 अगस्त 2022 से)

डॉ कनिका रखरा
सलाहकार
(25 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2023 तक)
विशेषज्ञता: बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
सलाहकार
(23 फरवरी 2023 से)
विशेषज्ञता: सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

डॉ जी. ए. टडस
सलाहकार
(12 अप्रैल 2022 से)

डॉ पी. श्रीनिवास राव
फैलो
(29 अप्रैल 2022 से)

डॉ दुर्गेश रॉय
फैलो
(31 दिसंबर 2022 तक)

डॉ आईवी रॉय सरकार
फैलो
(31 जुलाई 2022 से)

सुश्री नियती सिंह
सलाहकार
(1 मार्च 2023 से)

सुश्री एलिज़ाबेथ रोश
सलाहकार
(14 मार्च 2023 से)

आसियन–भारत केंद्र

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर / समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ तुहिनसुभ्रा गिरि
अनुसंधान सहायक
(10 मई 2022 से)
विशेषज्ञता: अतंराष्ट्रीय व्यापार

डॉ शम्पा कुन्डू
सहायक

डॉ निदा रहमान
(31 मई 2022 तक)
यंग प्रोफेशनल

वैश्विक विकास पर पहल

श्री अतुल कौशिक
जीडीसी फैलो
(19 दिसंबर 2022 से)

सुश्री रितुप्रना बैनर्जी
जीडीसी मैनेजर

श्री अमित अरोड़ा
जीडीसी मैनेजर

अनुसंधान सहायक

सुश्री कृतिका खन्ना
(27 नवंबर 2022 तक)

सुश्री संजना अग्रवाल
(20 जनवरी 2023 तक)

श्री सैयद अर्सलान अली

सुश्री श्वेता शाजू
(3 सितंबर 2022 तक)

सुश्री नीलाक्षी महर्षि
(13 नवंबर 2022 तक)

सुश्री सुखमनी कौर
(29 अप्रैल 2022 तक)

सुश्री सिद्धि शर्मा
(31 मई 2022 तक)

श्री चैतन्य खुराना
(25 मई 2022 तक)

श्री प्रणेश एम
(25 मई 2022 तक)

सुश्री इशिता वर्मा
(26 जुलाई 2022 तक)

श्री अर्पित बर्मन
(10 अगस्त 2022 से)

श्री सुक्रित जोशी
(10 अगस्त 2022 से)

सुश्री नेहा गुप्ता
(10 अगस्त 2022 से)

सुश्री राणा अमानत सिंह
(16 अगस्त 2022 से)

श्री आर्य जैश
(22 अगस्त 2022 से)

सुश्री देबाजंना
(1 नवंबर 2022 से)

सुश्री टिंवकल गुप्ता
(16 नवंबर 2022 से)

श्री कार्तिक किशोर
(22 दिसंबर 2022 से)

सुश्री रमनदीप कौर होरा
(1 दिसंबर 2022 से 20 जनवरी 2023 तक)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर अमृता नार्लीकर
अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (गीगा)

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. बिश्वजीत बनर्जी
मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा

डॉ. मितु सेनगुप्ता
प्रोफेसर, राजनीति और प्रशासन विभाग, रायर्सन यूनिवर्सिटी, कनाडा, विजिटिंग प्रोफेसर काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट (सीएसडी)

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर शाहिद अहमद
प्रोफेसर और प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवान
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

डॉ. रामकिशन एस. राजन
वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर और विजिटिंग फेलो, आरआईएस

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ गणेशन विग्नराज
एडजंक्ट सीनियर फेलो
सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ओवरसीज इंस्टीट्यूट (ODI), लंदन; अनिवासी सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS)

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

श्री एच. के. मलिक
(10 मार्च 2022 से)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं वित्त)

महानिदेशक कार्यालय

श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव *(31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत)*
श्रीमती रितु परनामी, निजी सचिव
सुश्री गोहर नाज, सचिवीय सहायक
श्री बलजीत, सपेशल सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक
(वेब और डिजाइन)
श्री संजीव करना, संपादकीय सहायक
(1 नवंबर 2022 से)

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
(31 जनवरी 2023 तक)
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
श्री सौम्य रंजन, आईटी सहायक *(31 मई 2022 तक)*
सुश्री निशा सैनी, वेबसाईट डेवलपर *(4 जुलाई 2022 से)*

वित्त एवं प्रशासन

श्री अनिल कांत शर्मा, सलाहकार
(8 अगस्त 2022 से)
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार (*डेपूटेशन पर)*
श्री अनिल कुमार, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिक
श्री अरूण कुमार गुप्ता, सलाहकार (लेखा)
(8 सितंबर 2022 से)
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती
श्री भास्कर तिवारी, सहायक लेखाकार

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव *(31 जनवरी 2023 तक),*
सचिवीय सहायक *(1 फरवरी 2022 से)*
श्री संजीव शर्मा, निजी सचिव (*डेपूटेशन पर)*
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
श्री जे. श्रीनिवास राव, सहायक
श्री बैदनाथ पाण्डेय, कार्यालय सहायक

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान (एमटीएस)
श्री प्रदीप (एमटीएस)
श्री राजू (एमटीएस)
श्री राज कुमार (एमटीएस)
श्री मनीष कुमार (एमटीएस)
श्री राज कुमार (एमटीएस)
श्री सुधीर राणा (एमटीएस)
श्री बिरजू (एमटीएस)
श्री प्रदीप नेगी (एमटीएस)
श्री अविनाश कपूर (एमटीएस)
श्री रमेश सिंह चौधरी (एमटीएस) *(27 जनवरी 2023 से)*

वित्तीय विवरण

जीएसए एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

16, डीडीए फलैट्स, ग्राउंड फलोर, पंचशील शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली–110017 टेलीफोन : 41811888, 7862099205, ई–मेलः admin@gsa.net.in

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली की आमसभा के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

राय

हमने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (इकाई) के तहत पंजीकृत सोसाइटी 'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली' के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च, 2023 तक का तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में 31 मार्च, 2023 को इकाई की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान के बारे में सही और निष्पक्ष छवि प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुरूप लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के खण्ड 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व' में वर्णित हैं। हम अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए उपयुक्त नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस इकाई से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और अपने अन्य आचार उत्तरदायित्वों का निर्वहन आचार संहिता के अनुसार किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन और शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व

भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही व निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सुनाम प्रतिष्ठान बने रहने में इकाई की क्षमता का आकलन करने, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण और लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने अथवा संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा कोई ठोस विकल्प न हो।

इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए शासी प्रभारी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन होने के बावजूद यह गारंटी नहीं देता कि 'एसए' के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण तथ्य संबंधी गलतबयानी होने पर सदैव उसका पता लगा ही लेंगे। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे ठोस तभी माना जाता है, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों की व्यक्तिगत या समग्र रूप से इनसे प्रभावित होने की संभावना हो।

'एसए' के अनुसार की जाने वाली लेखा परीक्षा के तहत हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यवसायिक तौर पर संशय से युक्त दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं को निर्मित एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।
- हम परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षण से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेते हैं।
- हम प्रयुक्त की जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार की उपयुक्तता और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई ठोस अनिश्चितता है, जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में अपना संचालन जारी रखने संबंधी इस इकाई की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने मत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां इकाई के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में संचालन जारी न रखने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सारांश, का आकलन करते हैं, तथा ज्ञात करते हैं कि क्या अंतर्निहित लेन–देन के व्यवहार और स्थितियों का विवरण उचित स्वरूप में वित्तीय विवरणों में दिया गया है या नहीं।

हम अन्य मामलों के अलावा शासन व्यवस्था के प्रभारी लोगों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों सहित लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित की गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण खामियों जानकारी देते हैं।

हम शासन व्यवस्था के प्रभारी लोगों को ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं जिसका संकलन हमने स्वतंत्रता से संबंधित उपयुक्त आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया है, और हम उनको उन सभी संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी देते हैं जिनका असर संभवतः हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, पर पड़ सकता है।

अन्य अपेक्षाओं की रिपोर्ट

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
- हमारे मतानुसार, इकाई द्वारा लेखा बहियों का अनुरक्षण विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है, ऐसा हमारे द्वारा इन बहियों की छान–बीन से प्रतीत होता है, और
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया तुलन–पत्र, आय एवं व्यय का विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।
- हमारे मतानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

स्थान : नई दिल्ली :
दिनांक : 04 / 09 / 2023

ह./–
सीए सुनील अग्रवाल
साझेदार
एम संख्या : 083899
यूडीआईएनः 22083899BGXUFT7420

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी)

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र

राशि

	vuqlph #	31मार्च, 2023 का	31मार्च, 2022 का
देनदारियां			
अनुसंधान एवं विकास कोष	1	158,979,552.22	145,026,683.01
अचल परिसंपत्ति कोष (गैर एफसीआरए)	2	116,827,535.00	118,326,021.00
अचल परिसंपत्ति कोष (एफसीआरए)		46,037.00	114,634.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (गैर एफसीआरए)	3	8,218,008.14	16,292,667.14
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (एफसीआरए)		80,919,187.15	90,988,960.24
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित सहायता अनुदान	4a	-	6,510,730.00
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान(गैर एफसीआरए)	4	53,975,073.60	61,816,104.63
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान(एफसीआरए)		10,087,720.00	7,252,196.00
कुल		**429,053,113.11**	446,327,996.02
परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (गैर एफसीआरए)	5	116,827,535.00	118,326,021.00
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (एफसीआरए)		447,333.00	515,930.00
निवेश (गैर एफसीआरए)	6	34,156,930.00	52,619,103.00
निवेश (एफसीआरए)		189,849,406.95	86,153,579.95
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (गैर एफसीआरए)	3	11,478,167.20	8,052,406.00
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (एफसीआरए)		2,618,735.62	160,672.90
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (गैर एफसीआरए)	7	53,666,026.67	63,985,822.03
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (एफसीआरए)		20,008,978.67	116,514,461.14
कुल		429,053,113.11	446,327,996.02

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

ह./–
सीए सुनील अग्रलवाल
साझेदार
एम सं. 083899
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04/09/2023

ह./–
अनिल कांत शर्मा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था)
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता राशि में

राशि रु. में

	अनुसूची #	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
आय			
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान	4ए	140,342,651.00	119,065,528.00
कार्यक्रम से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए हस्तांतरित प्रायोजित परियोजना अनुदान (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	3	97,625,342.96	38,348,023.74
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर हस्तांतरित अधिशेष राशि (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	3	–	2,142,204.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय (गैर–एफसीआरए)		254,695.00	282,818.00
अर्जित ब्याजः			
सावधि जमा पर (एफसीआरए)		4,752,929.00	4,787,984.00
सावधि जमा पर (गैर–एफसीआरए)		1,705,429.00	2,394,767.00
बचत खाता/ऑटो स्वीप खाता (एफसीआरए) पर		722,692.00	525,445.00
बचत खाता/ऑटो स्वीप खाता (गैर एफसीआरए) पर		1,057,788.00	300,911.00
कर्मचारियों को दिए ऋण पर (गैर–एफसीआरए)		28,301.00	92,396.00
आयकर रिफंड पर (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		89,439.00	33,934.00
अन्य विविध आय (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		9,367.18	–
प्रायोजित परियोजनाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपरिव्ययों के लिए वसूली(गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		6,339,491.00	1,855,709.00
देय बट्टे खाते में डाला		–	1,432.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – बेची गई/बट्टे खाते में डाल दी गई संपत्तियों का डब्ल्यू.डी.वी. (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2	–	–
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – भारत सरकार/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिगृहीत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		3,467,093.00	5,030,180.00
व्यय		**256,395,218.14**	**174,861,331.74**
कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	8	97,625,342.96	38,348,023.74
स्थापना व्यय (गैर–एफसीआरए)	9	102,272,449.00	84,689,270.00
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (गैर–एफसीआरए)	10	38,993,050.31	37,352,160.73
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (एफसीआरए)	11	84,413.66	70,889.12
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	5	3,467,093.00	5,030,180.00
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतरित की गई घाटा राशि (गैर–एफसीआरए और पूर्व अवधि व्यय	3	–	–
अनुसंधान और विकास कोष में हस्तांतरित अधिशेष		13,952,869.21	
कुल		**256,395,218.14**	**174,861,331.74**

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं
आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

ह./–
सीए सुनील अग्रलवाल
साझेदार
एम सं. 083899
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04/09/2023

ह./–
अनिल कांत शर्मा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रसीद और भुगतान

	प्राप्तियां	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			भुगतान	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
ए	**प्रारंभिक जमा :**					ए	**व्यय**				
i)	हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)	42,473.00		36,056.00		i)	स्थापना व्यय – अनुसूची – 12 (गैर – एफसीआरए)	94,494,291.00		86,332,839.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :					ii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 13 (गैर–एफसीआरए)	50,282,673.34		31,481,631.77	
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक	39,140.00		39,140.00							
	बचत खाता/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	55,600,240.03		24,441,874.76		iii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 14 (एफसीआरए)	1,038.66		44,053.12	
	बचत खाता/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	5,477,360.14		7,354,784.14		iv)	व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं – अनुसूची – 15 (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	75,674,290.96		29,671,075.74	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	86,153,579.95		92,384,916.33			**कुल ए**		220,452,293.96		147,529,599.63
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर एफसीआरए)	52,619,103.00		50,646,467.00		बी	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान**				
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	106,520,308.00		272,523.00		i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (गैर–एफसीआरए)	17,466,307.00		87,775,634.00	
		239,036.00				ii)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (एफसीआरए)			35,046.00	
	कुल ए		306,691,240.12		175,175,761.23		**कुल बी**		17,466,307.00		87,810,680.00
बी	**प्राप्त अनुदान**					सी	**अग्रिम और जमा**				
i)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से	145,900,000.00		228,400,000.00		i)	अग्रिम (गैर–एफसीआरए)	1,383,108.00		388,392.00	
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर–एफसीआरए)	28,328,512.82		22,933,746.80		ii)	अग्रिम (एफसीआरए)	44,339.00		174,510.00	
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से(एफसीआरए)	45,904,814.13		106,408,161.00		iii)	टीडीएस पर स्वीट ट्रांसफर (गैर–एफसीआरए)	90,361.80		278,529.00	
	कुल बी		220,133,326.95		357,741,907.80	iv)	टीडीएस पर स्वीट ट्रांसफर	2,017.00		545,980.00	
सी	**अर्जित ब्याज**					v)	गतावधि या पुराने चेक	-		331,128.00	
				66,438.00			**कुल सी**		1,519,825.80		87,810,680.00
i)	ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज, (गैर–एफसीआरए)	25,301.00		525,445.00		डी	**अन्य**				
ii)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(एफसीआरए)	711,763.00		2,440,337.00		i)	लौटाए गए अनुदान	10,774,521.00		383,720.00	
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	2,057,140.00		7,020,375.00		ii)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को किया गया भुगतान	9,975,421.00		1,904,044.00	
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(एफसीआरए)	1,695,663.00		997,952.00		iii)	आरआईएस भविष्य निधि में भुगतान की गई राशि	-			
v)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	1,057,788.00		33,934.00		iv)	मूर्त आस्तियों और विविध मदों का निपटान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया)	723,284.00		36603	
vi)	आय कर रिफंड पर ब्याज	89,439.00									
			5,637,094.00		11,084,481.00		**कुल डी**		21,473,226.00		2,324,367.00
	कुल अग्रेनीत		**532,461,661.07**		**544,002,150.03**		**कुल अग्रेनीत**				

	प्राप्तियां	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
	कुल अग्रानीत		532,461,661.07		544,002,150.03
डी	अन्य आय				
i)	रॉयल्टी	9,367.18		117,649.72	117,649.72
ii)	विविध आय		9,367.18		
	कुल डी				
ई					
i)	अग्रिम और जमा	93,657.00		1,218,081.00	
ii)	ऋण/अग्रिम की वसूली (गैर–एफसीआरए)	-		21,677.00	
iii)	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली (गैर–एफसीआरए)	58,282.00		44,011.00	
iv)	गतावधि या पुराने चेक (गैर–एफसीआरए एव–एफसीआरए))	9,975,461.00		-	47,57,082.00
v)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को देय	-		-	
vi)	अग्रिम में प्राप्त राशि (गैर–एफसीआरए)	32,636.00		159,798.00	
vii)	ऋण/अग्रिम की वसूली (एफसीआरए)	-			1,443,567.00
	आरआईएस पीएफ की ओर से प्राप्त राशि		10,160,036.00		
एफ	कुल ई	-			
i)	अन्य			-	
ii)	मूर्त आस्तियों का निपटान	88,900.00		26,243.00	
	मूर्त आस्तियों और वविध मदो का निपटान				
iii)	(विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को लौटाने योग्य)	1,259,311.00		484,816.00	511,059.00
	आय कर रिफंड		1,348,211.00		
	कुल		543,979,275.25		546,074,425.75

	भुगतान	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
	कुल अग्रानीत		260,911,652.76		239,383,185.63
ई	अंतिम शेष (क्लोजिंग बैलेंस)			42,473.00	
i)	हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)	11,981.00			
	हाथ में नकदी (एफसीआरए)	4,608.00			
ii)	बैंक में जमा राशि :				
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक(गैर – एफसीआरए)	39,140.00		39,140.00	
	बचत खाते/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	45,514,305.87		55,600,240.03	
	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	397,661.08		5,477,360.14	
	सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	89,849,406.95		86,153,579.95	
	सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (गैर –एफसीआरए)	34,156,930.00		52,619,103.00	
	सावधि जमा– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	100,000,000.00			
	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	12,719,252.59		106,520,308.00	
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	374,337.00		239,036.00	
			283,067,622.49		306,691,240.12
	कुल		543,979,275.25		546,074,425.75

खातों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्यावश्यक भाग है
हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

ह./–	ह./–	ह./–
सीए सुनील अग्रलवाल	अनिल कांत शर्मा	प्रो. सचिन चतुर्वेदी
साझेदार	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)	महानिदेशक

एम सं. 083899
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04/09/2023

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इसकी वेबसाइटः wwww.ris.org.in देखें।

RIS@40

RIS

Research and Information System for Developing Countries

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.
वेबसाइटः http://www.ris.org.in